म आश्विन - द्वितीय आश्विन २०५८ अक्टूबर २००१

मूल्य रु० ६/-

स्वदेशी

य स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी संदेश की संवाहिका पत्रिका

और अब आतंकी आग में झुलसती अर्थव्यवस्था

Scanned with OKEN Scanner

पारिजात पुष्प की दो कविताएँ

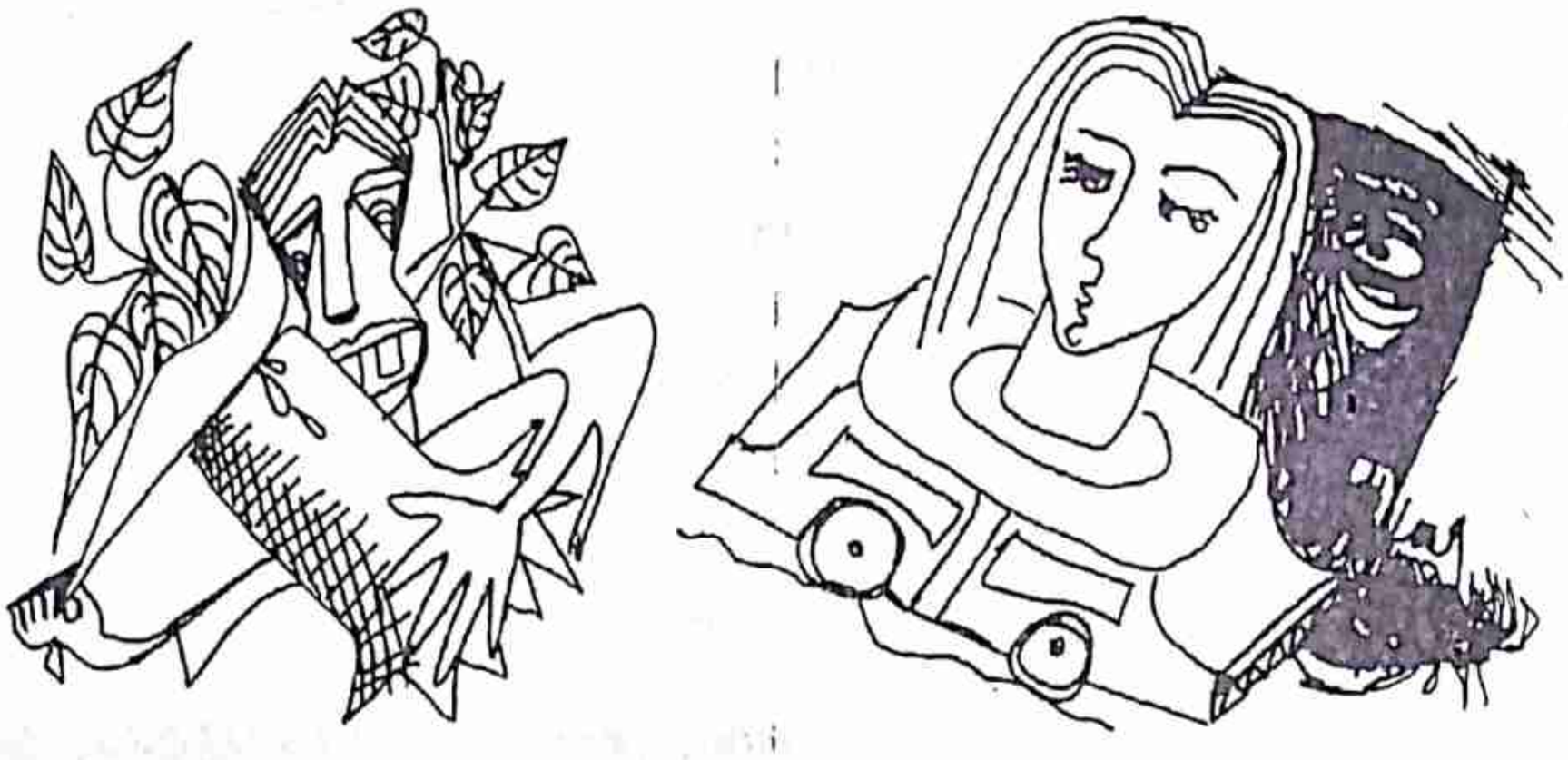

झाड़ियों का आतंक

ये हरे–भरे जंगल
मत काटिए –
इन्हें छोड़ दीजिए, मालिक!
यहाँ चिड़ियों की चहक
सुनाई देती है।
आप कहते हैं तो
मैं चुप सुन लेता हूँ
कि सोने के पिजड़ों में
रखेंगे आप हर चिड़िये को,
मैं कह नहीं पाता
कि सोना आपकी नजरों में
महत्व रखता है,
मगर चिड़िया की आँखों में
झाँकता है सिर्फ दाना–पानी,
एक अदद तिनकों का घोसला,
बच्चों की किलक
और चिड़े की प्रतीक्षा।
आप कहते हैं तो
मैं चुप सुन लेता हूँ
कि गाँव–गाँव तक जाएँगे
विश्व भर के उत्पाद
पेप्सी, पैटी, चाकलेट और पैंट
मैं कह नहीं पाता कि
ये लेबलदार विदेशी उत्पाद
आपके रहन–सहन को
दे सकते हैं ताजगी,
लेकिन, गाँव का पेट –
नहीं भरता अकेले खा लेने से,
गाँव के पेट में शामिल होते हैं –
कई कई पेट
जंगल के पेड़ों – लताओं –
तृण – तरुओं की तरह
आपस में लिपटे हुए।
जंगल कटेंगे तो
अनगिनत पेट कट जाएँगे
और खून के छीटों से भर जाएगा
आपके विकास का चेहरा,
फिर उन एक–एक छीटों से
उगेंगी कँटिली झाड़ियाँ।
इन्हीं झाड़ियों के आतंक में
आप घिर जाएँगे, मालिक!
ये हरे भरे जंगल
मत काटिए.....

पेट्रोल-युग के खिलाफ

लगातार क्रूर आँखों से देखता है
सौ बरस से अधिक उग्र का
मेरा दादा –
मेरी जापानी कार
और अमेरिकी वाइफ को,
मैं सिगार के धुएँ में
ढक लेता हूँ अपना चेहरा,
और सोचता हूँ
दादा कब मरेगा?
दादा समझता है
मैं मर चुका हूँ।
वह देखता है आसमान
लौटता है जीए हुए दिनों के पार
पेट्रोलियम के ईंधन पर
उड़ते जमाने के पहले,
मेरी अमेरिकी वाइफ के
गुलाबी रंगो आब में
दिखता है मेरे दादा को पेट्रोल,
पेट्रोल की गंध
पेट्रोल की उड़नशीलता।
वह मुझे
अरबी रेगिस्तान के बवँडर में
टिला होते हुए देखता है
लेकिन वह अपने को कभी नहीं देखता
मरता हुआ जर्जर बूढ़ा
जैसे कि वह कल
पुराने कपड़े की तरह बदल लेगा देह
और युवा होकर
बना लेगा नया युग,
पेट्रोल – युग गुजर चुका होगा।

Scanned with OKEN Scanner

...नी वार्ता

...य पाठक वृन्द,

आज विश्व संश्लिष्ट आर्थिक परिस्थितियों में घिर चुका है। आर्थिक ...क्तियों ने विभिन्न रूपों में युद्ध प्रारंभ कर दिया है। 11 सितम्बर 2001 को ...ए आतंकी हमले का भी आर्थिक पक्ष है। इसका चेहरा साफ–साफ नहीं ...खता हो तब भी विश्व व्यापार केन्द्र को लक्ष्य बनाने वाले आतंकी योजनाकार ...े आर्थिक महत्व से अनभिज्ञ नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टि से देखें ...कहना होगा कि आतंक का भी अर्थशास्त्री पक्ष है। यह विषय अभी आगे ...र खुलने वाला है। फिलहाल विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के साथ आपकी ...देशी पत्रिका आतंकी आग में झुलसती अर्थव्यवस्था पर अग्रलेख प्रस्तुत कर ...े है। आशा है आपको पसंद आएगा।

नमस्कार।

आपका

प्रमोदकुमार दुबे

...क्रम

और अब आंतकी आग में झुलसती अर्थव्यवस्था
पी.डी. कार्त्तिकेय........................../6

अमरीकी शोषण तथा इस्लामी कट्टरवाद से तटस्थ रहें
डॉ. भरत झुनझुनवाला................../13

क्या यूएस–64 पुर्नजीवित हो सकता है
रमाकान्त पाण्डेय....................../15

विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास
रुद्र दत्त................................./18

उदारीकरण में श्रम मानक एवं श्रमिक
मुकुन्द कुमार............................../21

प्राकृतिक संपदा पर सेंधमारी क्यों और कब तक!
देवेन्द्र शर्मा................................./23

भूख का भूगोल
नरेश सिरोही................................../30

संस्कृति के नाम पेटेंट हुई है हमारी जैव सम्पदा
डॉ० प्रमोद कुमार दूबे..................../36

रोजगार विषयक टास्क फोर्स के विरुद्ध सफल संगोष्ठी................/47

पाठकनामा/4, उन्होंने कहा/4, माध्यम/41, घर–गृहस्थी/42, स्वदेशी व्यंग्य/43, समाचार परिक्रमा/45

संपादकीय कार्यालय : ६०, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-११० ००१ • दूरभाष : ३०१८१७५
ई-मेल : swadeshisampark@rediffmail.com

स्वदेशी
पत्रिका

वर्ष–7, अंक–1

प्रथम आश्विन–द्वितीय आश्विन 2058,

अक्टूबर, 2001

:: अमर वाणी ::

**ओ३म् तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम
शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।।**

प्रभो! आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। आप सब कुछ देखने वाले हैं। विद्वानों, धर्मात्ओं और अपने सेवकों के कल्याणकारी हैं। आप सृष्टि से भी पूर्ण विद्यमान रहने वाले हैं। आप शुद्ध स्वरूप और प्रलय के भी पीछे रहने वाले हैं। आपकी कृपा से हम सौ वर्ष तक आँखों से देखते रहें, सौ वर्ष तक जीते रहें, सौ वर्ष तक आपके गुणों में श्रद्धा रखते हुए उनको सुनते-सुनाते और उपदेश करते रहें। आपकी उपासना करते हुए, सौ वर्ष किसी के आगे दीन होकर हाथ न फैलावें, दास न रहें, स्वतंत्र और धनाढ्य बनें। इसी प्रकार सौ वर्ष से अधिक भी आपकी अपार दया से जीएं, सुनें, बोलें और आपके पवित्र ज्ञान-वेद भगवान् - को पढ़कर उसका उपदेश करें।

(भक्ति दर्पण)

मुख्य संपादक :
डॉ. महेश चंद्र शर्मा

कार्यकारी संपादक :
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

मूल्य : एक अंक – 6 रुपए
वार्षिक सदस्यता शुल्क – 60 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क – 1000/–

विशेष सूचना : अपनी सदस्यता सूची एवं सदस्यता फार्म कृपया अपना नाम व पता, पिनकोड सहित साफ–साफ शब्दों में लिखकर भेजें।

Scanned with OKEN Scanner

पाठकनामा

श्रद्धांजलि

प्रिय सम्पादक,

नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ, त्रिपुरा द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ के चार वरिष्ठ प्रचारकों की निर्मम हत्या से सम्पूर्ण भारत का राष्ट्रभक्त हृदय आहत है। यह जघन्य हत्या राष्ट्र के अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्या कारण है कि सामाजिक कार्य के लिए दूसरे धर्मान्तरित करने वाले संगठनों को भारत रत्न का अलंकार दिया गया और देशवासियों को उसकी वास्तविक संस्कृति में रख राष्ट्रीय अस्मिता सबल करने में लगे देशभक्त समाजसेवकों को अपने देश में मौत के घाट उतारा जा रहा है। अलंकार तो दूर है देश के सूचना तंत्र भी इसे योग्य महत्व नहीं देते? इस पर प्रत्येक देशवासी को आज विचार करना चाहिए।

स्वदेशी पत्रिका ने पूज्य राष्ट्रभक्त हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देकर अवश्य धन्य हुई।

– **रविशंकर**, कोलकत्ता, पं. बंगाल

ज्ञान की नई दृष्टि

सम्पादक महोदय,

इक्कीसवीं सदी के रावण का सच्चा चेहरा पहचानकर मुझे इस लेख के लेखक डॉ. अमित शर्मा को धन्यवाद देने की इच्छा हुई। इस लेखक ने मुझे चिंतित भी कर दिया कि क्या सचमुच हम अपना उद्धार नहीं कर पाएँगे। मेरी आशा है कि वैचारिक उत्पादन के क्षेत्र में मुख्यतः भारतीय ज्ञान के उत्पादन में बड़े–बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों का योगदान नहीं होता। यहाँ तो मस्तिष्क की ग्रंथि ठीक की जाती है, उससे ग्रंथ निकल आते है। मस्तिष्क ग्रंथि ठीक करने के लिए एकांत साधना स्थली चाहिए, न कि कोलाहल से भरा वातावरण। डॉ. शर्मा के लेखकी शैली बड़ी मिथकीय लगी उन्हें धन्यवाद।

– **इन्दुरंजन शुक्ल**, भोपाल, मध्यप्रदेश

सार्वजनिक हित का महत्व

सम्पादक जी,

विकासशील देशों का पक्ष लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विकासशील देशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में जिस प्रकार के वक्तव्य दिए। वह उनके निर्णयों से प्रकट होना चाहिए यदि केवल कहने के लिए विकासशील देशों की पक्षधरता होती है तो उसका मायने नहीं है। मेरे जानते विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों का हित तभी सध सकता है जब इनमें एकजुटता रहे और भारत का प्रतिनिधित्व तभी सबल रूप में सामने आ सकता है जब वह भारत के सार्वजनिक हितों को सबसे ऊपर रखें। स्वदेशी पत्रिका में उक्त सम्मेलन की रपट पढ़कर अच्छा लगा।

– **अभिषेक रावत**, देहरादून, उत्तराँचल

उन्होंने कहा

वैश्वीकरण तभी तक स्वीकार्य है जब तक प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करता है; उदारीकरण खाद्य सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

फ्रांस के कृषि मंत्री
जीन ग्लैवानी

अभी--अभी हमने 21वीं सदी की पहली लड़ाई देखी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति
जार्ज डब्ल्यू. बुश

गाँवों से पलायन करने वाली आबादी शहरों का स्वरूप बिगाड़ रही है यदि कृषि को स्वस्थ माहौल दिया जाए तो शहरों की समस्या पर काबू पाया जा सकता है साथ ही ग्रामीण परिवेश भी समृद्ध होगा।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री
जगमोहन

अमेरिकी प्रतिबंधों के हटने का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

वित्तमंत्री
यशवंत सिन्हा

जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यह सम्मान संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। संविधान जनमत से ऊपर है।

उच्चतम न्यायालय

सरकार को आर्थिक समझ नहीं है।

प्रमुख अर्थशास्त्री
जय दुबाशी

Scanned with OKEN Scanner

अर्थ का 'प्रभाव' और आतंक

विकास सुरक्षा के बिना संभव नहीं होता और सुरक्षा बनी रहे इसके लिए ऐसे विकास की आवश्यकता होगी जिसमें प्रत्येक प्राणी के लिए जीवनदायी भूमिका हो। यदि विकास शोषण और असमानता के व्यक्तिनिष्ठ रास्ते आगे बढ़ता है, अपने अतिरिक्त अन्य लोगों के जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं को लूट लेता है तो निश्चय ही वह आतंक को जन्म देता है। आतंकवाद के विश्वव्यापी फैलाव में पहला प्रेरक तत्व क्या है? कोई ईश्वरीय मान्यता? संस्कृति–सभ्यता की असुरक्षा? स्वतंत्र राज्य की इच्छा? अथवा आर्थिक अभाव–भूखमरी बेरोजगारी? स्पष्ट रूप में देखें तो आर्थिक अभाव से विवश हुए लोगों का रक्त पीकर आतंक का दैत्य भी अर्थ शोषकों की भांति बलवान होता है और सुरक्षा की समस्या उत्पन्न करता है, फिर विकास की गति ठहर जाती है। विकास की दोषपूर्ण नीतियों में ही निहित है आतंक का बीज। मनुष्य ही क्या प्रकृति भी – विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण सर्वनाशी आतंक की भूमिका निभाने लगती है वायु – जल – भूमि और आहार – विहार सम्बन्धी प्रदूषणों के जीवनघाती विभिन्न रूप क्या विकास की दोषपूर्ण नीतियों के दुष्परिणाम नहीं हैं?

11 सितंबर, 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र और पेंटागन पर हुए आतंकी हमले की जड़ में जाए तो स्पष्ट होगा कि जिस ओसामा बिन लादेन को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है वह कम्युनिस्ट विस्तारवाद के संचालक सोवियत रूस और पूँजीवाद की कब्जेवारी का परचम लहराने वाले अमेरिका के बीच हुए शीतयुद्ध की उपज है। ओसाम को अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत सेना के विरुद्ध कार्य करने के लिए लगाया था। इस काम के लिए उसे अकूत धन दिया गया था, उसने अफगानियों की आर्थिक मदद की और जब वही अमेरिका ईराक पर हमला करने लगा, ओसामा अमेरिका का शत्रु हो गया। आज उसकी क्षमताओं का विस्तार हो चुका है। पूँजीवाद और साम्यवाद की टक्कर से निकली यह चिनगारी भी दूसरों के घर जला सकती है, पर ऐसी रोशनी कदापि नहीं दे सकती जिससे संसार में घने होते अंधकार को मिटाया जा सके।

अर्थ के वास्तविक स्वरूप को पहचाने का प्रकाश भारतीय मनीषा के पास है। हम जानते है कि प्रतिपालिका विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, इसके अंर्जन का उचित मार्ग क्या है, इस शक्ति की आराधना कैसे की जानी चाहिए। यह किसी मिथ का उल्लेख नहीं, वास्तविकता है। इसे वस्तुनिष्ठ ढंग से भी समझा जा सकता है। पर आस्था और भावना मनुष्य में सुपात्रता लाती है, सामंजस्य स्थापित करती है, परस्परावलम्बी बनाती है एकात्मकता का बोध जगाती है और यहीं से मनुष्य की वृत्तियाँ उदार हो उठती है। फिर कैसी असुरक्षा, कैसा भय–आतंक और शोषण। इसी कार्य के लिए दण्डविधान और राज्य व्यवस्था आवश्यक होती है। यह काम केवल प्रवचन से नहीं होता, समुचित अर्थव्यवस्था देने से होता है।

क्या यह सच नहीं है कि अर्थ का सघन केन्द्रीकरण हो जाने से आज अमेरिका की आर्थिक मंदी से पूरे विश्व में मंदी की स्थिति हो गई? असीमित विकास और सबसे शक्तिशाली होने की इच्छा से अमेरिका ने कभी साधन की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया, दूसरे देशों की दुर्बलताओं का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया, यहाँ कि तक अपने विकास में आने वाले किसी न्यायसंगत अवरोध को भी नजरअन्दाज किया – पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी के नियंत्रण के लिए क्या वह सहमत हो सका? तो क्या विकास उसके हिस्से रहेगा और संत्रास दूसरे के हिस्से? अर्थ के केन्द्रीकरण का लाभ है तो अभिशाप्त भी। विकास एक संतुलित मार्ग है इसे एकांगी रूप में ग्रहण करने पर प्राकृतिक–दण्ड मिलता है। इसलिए सर्वात्मा के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से ही शांति–सुरक्षा प्राप्त होती है। अमेरिका की अर्थ–पिपासाको पं. दीनदयाल उपाध्याय की अर्थदृष्टि के अनुसार अर्थ के प्रभाव का दोष कहा जा सकता है।

आज की दुनिया जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था के बावजूद आर्थिक तानाशाही के गर्त में फँसी हुई है अर्थ की समुचित व्यवस्था आर्थिक लोकतंत्र से चरितार्थ होती है इसके लिए 'अर्थायाम' की समझ जरूरी है। भूमंडलीकृत अर्थतंत्र में राज्य व्यवस्था की भूमिका सुदृढ़ नहीं हो तो व्यवसायिक अराजकता देशवासियों का अहित कर सकती है। अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद आर्थिक मंदी को और बल मिल गया है, युद्ध के बाद इसके और बढ़ने की आशा की जा रही है। इसके चपेट में व्यक्तिशः दुष्प्रभाव हो सकता है लेकिन यदि व्यक्तिशः पराश्रय नहीं हो तो जनजीवन की सामान्य आवश्यकताएँ पूरी होती रहेंगी। जो लोग विकसित देशों की स्पर्धा में देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ाने की बात करते हैं, उनके ध्यान में व्यापक जनजीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न नहीं रहता, अर्थनीतियों के निर्णेता देश से नहीं, विदेश से अपनी विचार–भूमि बनाते हैं। गाँव की आपूर्तियों से सम्बन्धित स्थानीय बाजार स्थानीय उत्पादनों की अधिक से अधिक बिक्री करें तो उनमें अधिक स्थिरता रह सकती है। इसी तरह देश के ऐसे आन्तरिक उत्पादनों को जो जनजीवन की अति आवश्यक आपूर्तियों से सम्बन्धित हों, उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। अन्यथा विषम वैश्विक परिस्थितियों में जब बाहर के उत्पादन बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे, संकट गहरा जाएगा। अर्थ के दैशिक आधार को सबल बनाना प्राथमिक कार्य होता है, लेकिन हो क्या रहा है, शत–प्रतिशत विदेशी पूँजी निवेश के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, यह सार्वजनिक हित में नहीं है। यह सच्चे विकास का रास्ता नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

अग्रलेख

और अब आतंकी आग में झुलसती अर्थव्यव

■ पी.डी. कौं

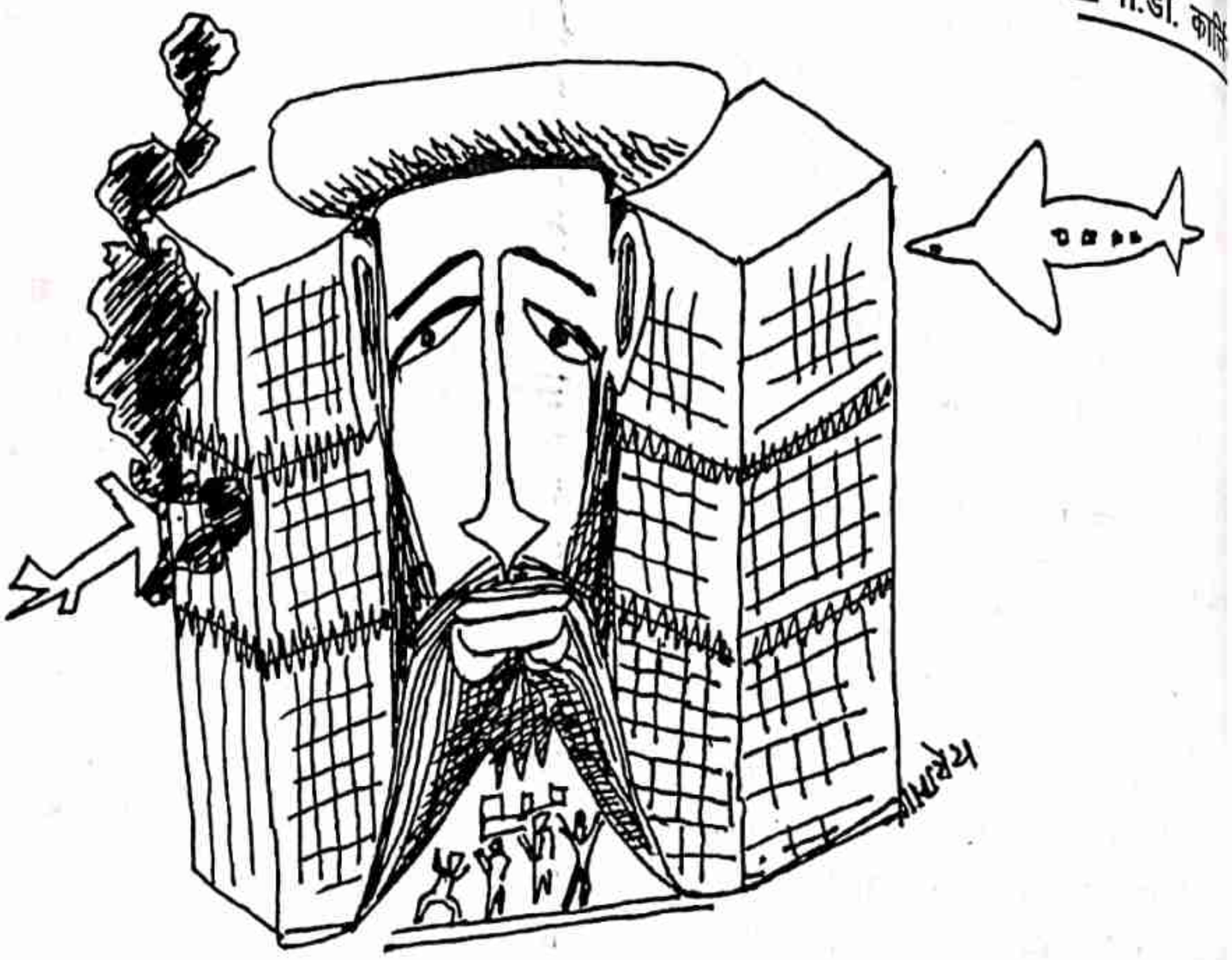

आर्थिक मंदी के बाद अब आतंकी आग की लपटों से विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत घटक देश अमेरिका परेशान हुआ है। आतंक और वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था के ढाँचे और कार्य पद्धति में अंतर दिखता है, लेकिन इनकी मानसिकता और मूल में गहरी समानता भी है। एक ही तरह की एकाधिकार की प्रकृति विरोधी सोंच इन दोनों के भीतर है। इसलिए अब उन सभी शक्ति घटकों को एक साथ देखने की जरूरत है, जो अर्थाश्रित विश्व व्यवस्था को निर्मित करते हैं। राज्य, समाज और बाजार की तीनों व्यवस्थाएँ एक--दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि राज्य व्यवस्था गृहयुद्ध से ग्रस्त हो जाती है अथवा बाहरी आक्रमण झेलती है या राज्य विस्तार के लिए युद्ध करती है, तो इससे समाज और बाजार की व्यवस्थाएँ भी प्रभावित होती हैं। इसी तरह किसी सामाजिक परिवर्त्तन से भी राज्य और बाजार प्रभावित होता है और बाजार में भी आए बदलाव से राज्य और समाज प्रभावित होते हैं। जैसे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में गहरी आर्थिक मंदी छा गयी थी, उसे 300 अरब डॉलर की हानि सहनी पड़ी थी। यह आर्थिक हानि युद्ध लड़ने में व्यय हुए धन के लगभग बराबर थी। अमेरिका ने मंदी से निकलने के लिए आर्थिक रणनीति बनाई थी। इसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक और मुद्राकोष जैसी संस्थाएँ बनी। अमेरिका ने अपने राज्यों में असंतोष को दबाया था और बाह देशों में भी शोषण के तंत्रों की जमी थीं। इससे भूमंडलीकरण एक पक्ष खड़ा हुआ और इसीके सभ्यता–संस्कृतियों के आपसी स को भी एक महत्वपूर्ण विषय के में स्वीकार किया गया। यह स हुआ कि किसी समाज आवश्यकताओं की आपूर्ति करते बाजार जनरुचि से प्रभावित होता बाजार के विस्तार के लिए लोगों इच्छाओं और आवश्यकताओं की दि का अध्ययन जरूरी है। यदि कि

Scanned with OKEN Scanner

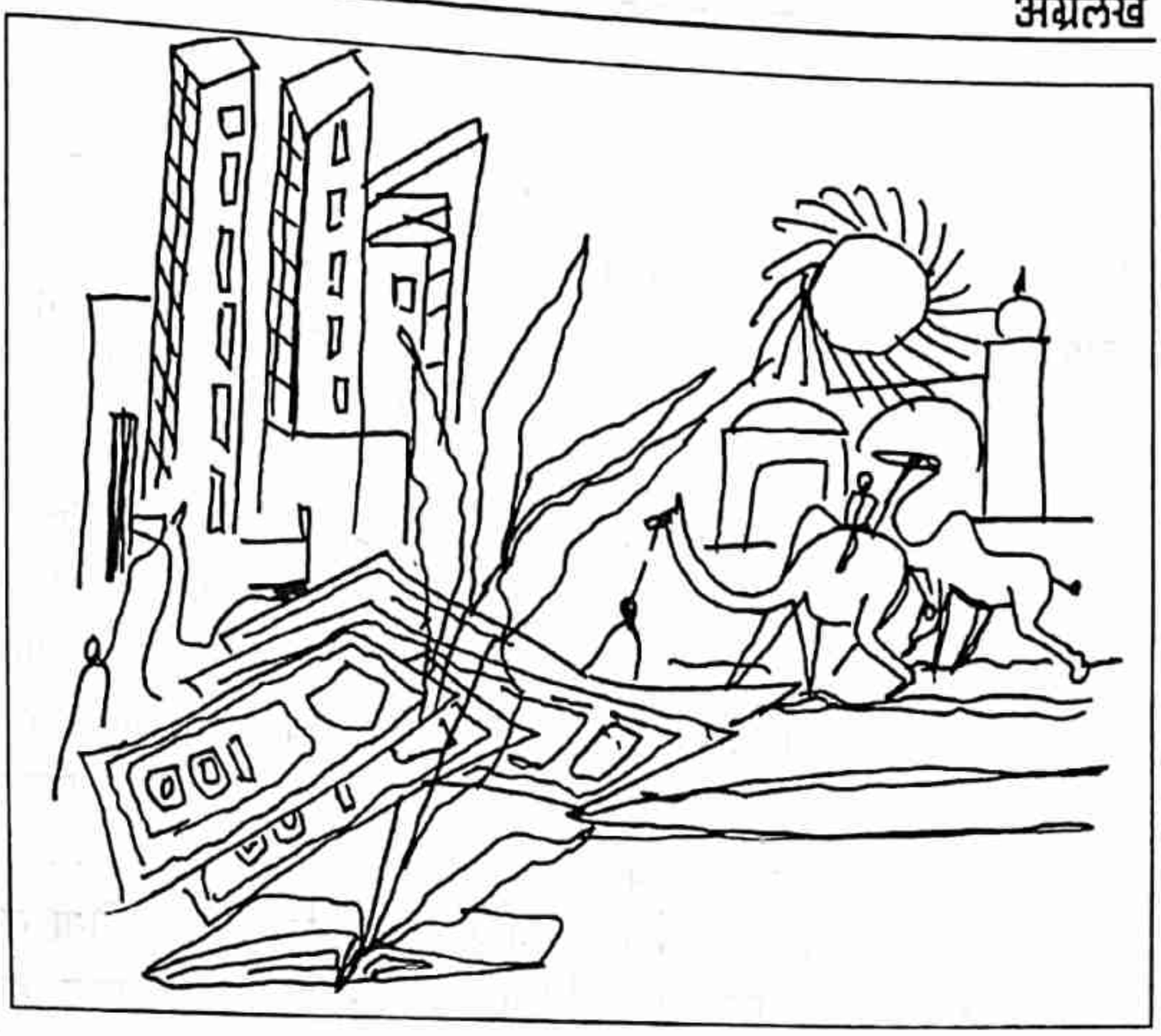

की मानसिकता में परिवर्तन
जाए, शाकाहारी से मांसाहारी
स्वास्थ्य के नाम पर कोई
लाया जाए तो उससे बाजार
र में सुविधा होगी। समाज
निक खोज के बहाने भी
का उपभोक्ता बनाया जा
साथ ही धार्मिक विश्वासों
जार और राज्य के विस्तार
माध्यम बनाया जा सकता
इतिहास, शिक्षा, स्वास्थ्य,
तकता, सांस्कृतिक–अंग
सामाजिक तत्व भी सामरिक
क अस्त्र–शस्त्रों के रूप में
आने लगे। फिल्म–फैशन
मनोरंजन के साधनों के भी
तलब अधिक गहरे हो गए।
के आर्थिक पक्ष और बाजार
अब आतंकवाद का अर्थशास्त्र
त होने लगा।

रेका के व्यवसायिक मामलों
अधिकारी जब यूरोपीय संघ
में यह कहता है कि हमारे
को बाजार नहीं देना, हम पर
म गिराने के समान है – तो
गन और विश्व व्यापार केन्द्र
ी संबंध क्या हैं, यह स्पष्ट
है। 11 सितंबर, 2001 को
कवादी अमेरिका के विश्व
केंद्र और पेंटागन पर संयुक्त
मला करते हैं तो कोई संदेह
ता कि आतंकी हमलों के
कार की खोपड़ी सामरिक और
शक्तियों के अंतर्सम्बन्ध से
नहीं है। यह भी मानना होगा
तिरण या जेहादी कारनामों में
संगठनों के प्रलोभन और हत्या
थियार स्वाभाविक मानव जीवन
द्ध हैं। इनका उद्देश्य सत्ता
अकूत सुख साधनों का भोग

करना है, जिसे प्राकृतिक नियमों की कसौटी पर एक पागलपन कहना उचित होगा।

आज अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र और पेंटागन को राख कर देने वाले हमलों के जिम्मेदार आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन नाम के एक अरबी को जिन्दा या मुर्दा सौंपने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों पर दबाव दे रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्थाएँ आतंकवादियों से पीड़ित हैं। अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध निरंतर गतिशील न्याय के नाम से लड़ाई लड़ने की तैयारी पूरी करने में लगा है, युद्ध के क्षेत्र कौन–कौन से होंगे और इसका भविष्य क्या होगा? इन विषय पर अमेरिकी विशेषज्ञों में बहसें हो रही हैं। ओसामा बिन लादेन से संबंध रखने वाली अनेक जिहादी संगठन है और उनके सहयोगी देश भी। अमेरिकी रक्षा उपमंत्री डी. वोल्फविट्ज के नेतृत्व वाले अधिकारीगण यह मान रहे है कि इराक और लेबनान के बेक्का में चल रहे आतंकी केंद्रों पर भी कारवाई करनी होगी। विदेश मंत्री कालिन पावेल की चिंता है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को न्याय संगत रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुसरण और राजनयिक समर्थन जुटाना जरूरी है। भारत में भी ओसामा को नायक मानने वाले सिमी जैसे संगठन हैं। मध्य एशिया में सक्रिय इसी प्रकार का एक संगठन है हमास। हमास के संगठनकर्त्ता शेख मोहम्मद यसीन सिमी के भी करीबी हैं। इनके अतिरिक्त अन्य माफियाओं का भी समूह है, मसलन अबू सलेम, दाऊद इम्ब्राहिम इत्यादि, जिनके विषय में संदेह है कि अफगानिस्तान पर ओसामा के लिए जब अमेरिकी हमला होगा तो भारत में भी इन अपराधियों के समूह गड़बड़ी फैला सकते हैं। सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय बढ़ाने के लिए विवश है।

एक ओसामा की देशान्तरीय उपस्थिति से दैशिक स्तर पर भी आतंक का जाल फैला हुआ है। इतनी बड़ी ताकत में ओसामा के उदय का कारण क्या है?

Scanned with OKEN Scanner

ओसामा की गतिविधियों को बल देने वाली ताकत क्या है। उसकी सब बड़ी ताकत पैसा है। पैसे की ताकत से उसने बाकी शक्तियों का अर्जन किया। पैसे का सहयोग देकर उसने अफगानियों लोकप्रिया पायी। लोकप्रिय होने के बाद इस्लाम की आस्था को जगाकर लोगों को संगठित करने लगा। वह पारंपरिक रूप से इस्लामी देशों का सर्वमान्य नेता नहीं है। उसकी पकड़ बेरोजगार मुस्लिम युवाओं पर मजबूत होती गई इसके बावजूद कि आज के विश्व में इतिहास के बीते दिनों को दुहराया नहीं जा सकता। पर उसने मध्यकालीन घटनाओं को फिर दुहराने के भ्रम साथ दुनिया को दारूल हरब से दारूल इस्लाम बनाने का जेहादी सपना दिखाया। अभी पैसे से लोकप्रिया और लोकप्रिया से धार्मिक भावना तक कदम बढ़ाने की प्रक्रिया ही पूरी हुई है कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। इसके बाद उसके दो महत्वपूर्ण कदम और हो सकते हैं, पहला सभी इस्लामी देशों का सर्वस्वीकृत बादशाह और अंतिम दूसरा कदम नया मसीहा होना। इसके बाद वह हर आस्थावान धर्म भीरू व्यक्ति की पूजा का तस्वीर बन सकता है। यह काम वह किसी धार्मिक तपस्या और कुदरती ताकत से नहीं कर रहा है उसके इस काम का आधार पैसे की ताकत और वैश्विक परिस्थितियाँ हैं जिन्हें महाशक्ति होकर दुनिया के संसाधनों पर कब्ज करने की होड़ में दो देशों के लोगों ने पैदा किया पूँजीवाद और कम्युनिज्म की रगड़ से पैदा हुई परिस्थितियों में ओसामा की प्रासंगिकता बढ़ गई। अभी कजाकिस्तान आदि देशों के दौरे पर निकले जान पॉल पोप के संदेशों पर ध्यान दीजिए, वेटकेन सिटी के ईसाई बादशाह पोप कल तक यह कह रहे थे कि एशिया महादेश को ईसाई बनाएँगे, सर्वधर्म समभाव उचित नहीं है आज यह संदेश प्रसारित करने में लगे हुए हैं कि 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना'। मतलब साफ है कि ओसामा के साथ सारी इस्लामी शक्तियाँ एकत्र न हो सकें उसे धार्मिक नेता या मसीहा का दर्जा न मिल सके इससे आतंक का धार्मिकीकरण हो जाएगा और ओसामा को मिटाना आसान नहीं होगा। भूमंडलीकृत अर्थ की शक्ति का यह प्रभाव दुनिया के लिए नई समस्या बनकर खड़ा हो चुका है। पैसे के जोर से समाज को प्रभाव में लेकर उसके हितों की बात करके नई सत्ता की लड़ाई खड़ी करने के तौर तरीके ईसाई आतंक में भी देखे जा सकते हैं। अपने देश के संदर्भ में देखें तो कम्युनिस्ट माओवादी आतंक हो, इस्लामी आतंक हो, अथवा ईसाई आतंक ये सभी अवांक्षित है। इनके उपजने से विकास के मार्ग में अवरोध तो होगा ही हमारी धार्मिक आस्था का जनतांत्रिक स्वरूप भी आहत होगा। हमारे देश में चिरकाल से वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता रही है। रावण के राज्य लंका में विभीषण जैसे रामभक्त को रहने की स्वतंत्रता रहती है। इसका अर्थ है हमारी धार्मिक आस्था का आर्थिकीकरण वर्जित है। पैसे पर धर्मभावना को खरीदना पाप है। किसी की गरीबी मजबूरी का लाभ उठाकर उसका धार्मिक परिवर्त्तन करना अनुचित समझा जाता है। पर दुनिया भर की सम्पत्ति लूटने वाले पश्चिमी आक्रांताओं में गरीबी का भी उपयोग धर्मांतरण के लिए किया। और धर्मांतरित लोगों से संगठित होकर अलग राज्य के
आतंक करने पर उतारू किया
अलग राज्य होने के बाद औपनि
पराधीनता के शोषण का चक्कर
रहता है। इसके बाद के लक्षण
हुए अमेरिकी–अफ्रीकी देशों और
देशों में देखे जाते है कि
उपनिवेशकारी शक्तियों से संघर्ष
रहता है। इन सभी षड्यंत्रों का
उद्देश्य आर्थिक शोषण है। ये
पैसे से शुरू होकर अंततः पैसों
ठहरे रहते हैं। इसका कोई
मापनवता के भीतर सद्विचार
उसकी आत्मिक उन्नति करना
है। इस षड्यंत्र में मानव की
उपयोग होती है उसका स्वतंत्रता
होती है। उसका स्वधर्म समाप्त
जाता है। धार्मिक आस्था
भूमंडलीकरण स्वधर्म को मिटा
सांस्कृतिक विविधता को नष्ट
है यह भी एक तरह की आर्थिक
का हथियार हो गया है। भारतीय
दर्शन अर्थ के विकेन्द्रित स्वरूप
तरह धर्म के भी विकेन्द्रित स्वरूप
अर्थात् स्वधर्म को स्वीकार करत
यह धार्मिक लोकतंत्र दुनिया के
देशों को समझ में नहीं आता।
में हिन्दू धर्म, धर्म के रूप में स्वी
नहीं है उसे धार्मिक स्वतंत्रता के नि
की सुविधा प्राप्त नहीं होती।
यह इसलिए है कि एक ग्रंथ एक
एक सम्प्रदाय हिन्दूओं में नहीं है
बाद व्यक्ति की निजी प्रवृत्ति भी
रखती है। एक ही सत्य को
मतों में अलग–अलग व्याख्या
स्वीकृति से धार्मिक लोकतंत्र का स्व
बनता हैं यही वास्तविक धर्म पथ
इसमें सर्वधर्म समभाव है। और
राज्य व्यवस्था से संचालित नहीं
सकता। आज के अर्थ–युद्ध से

Scanned with OKEN Scanner

रखने का यही मार्ग है।
धर्म के लोकधर्मी स्वरूप
क लोकतंत्र की तरह समझ
ए तो धर्म का व्यवसायिक
हीं हो सकता न तो कोई
नभावना का उपयोग कर
धर्मांतरण में कोई आर्थिक
सकता है। ईश्वरीय ज्ञान
क अधिकारी विरक्त लोग
के कल्याण का अनार्थिक
में प्रवृत हो सकते हैं जिन्हें
कुछ भी पाना शेष नहीं है।
रीय राज्य नहीं बनाना है।
नेक ओसामा सभी ईश्वरीय
में जनता की धर्मभावना को
ाकर खड़े हो जाएँगे। उन्हें
स्था और व्यापारी उपयोग
जब वह अपने पैर पर खड़ा
नरैल सिंह भी भींडरवाला
र अपरेशन ब्लू स्टार की
याँ बनेंगी जैसा कि अमेरिका
किए हुए ओसामा बिना
साथ हो रहा है।
ामा का उदय सोवियत रूस
निस्ट विस्तारवाद और
पूँजीवाद के टक्कर से हुआ
दो महाशक्तियों के लम्बे
की वैश्विक फसल है।
शक्तियों के विघटन के
सामा का भूमिगत दानवी
जेहादी आतंक का रूप लेता
या। आज वह अमेरिका के
फन उठा चुका है।
अफगानिस्तान आज ओसामा
द्र बना हुआ है कम्युनिस्ट
रूस और पूँजीवादी अमेरिका
म द्वन्द्व की रणभूमि भी बना।
निस्तान के शासक जहीर शाह
देश यात्रा पर थे उनके परिवार
प्रतिद्वन्द्वी सदस्य को कम्युनिस्ट

ओसामा का उदय सोवियत रूस के कम्युनिस्ट विस्तारवाद और अमेरिकी पूँजीवाद के टक्कर से हुआ है। वह दो महाशक्तियों के लम्बे शीतयुद्ध की वैश्विक फसल है। कम्युनिस्ट शक्तियों के विघटन के बाद ओसामा का भूमिगत दानवी साम्राज्य जेहादी आतंक का रूप लेता चला गया। आज वह अमेरिका के खिलाफ फन उठा चुका है।

रूस ने बलात् शासक बना दिया। और इसके बाद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन लाने का रास्ता खुल गया। इधर अमेरिका का हस्तक्षेप भी शुरू हो गया। एक समय आया जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ। लेकिन जिन साधनों से अमेरिका ने यह फतह किया था वे साधन कम्युनिस्ट रूस के विघटन के बाद और मजबूत हो गये। इस प्रकार दो महाशक्तियों के शीतयुद्ध के फलस्वरूप पैदा हुए ओसामा।

ओसामा बिन लादेन के वैश्विक आतंकी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के कुछ ठोस आधार है। केन्या में शुतुरमुर्ग, अफ्रीका से हीरों का कारोबार, सूडान में ऊँट पालन, ताजकिस्तान में खेती, तुर्की में वन–सम्पदा आदि से ओसामा के निजी खर्च चलते हैं। कहते हैं, ओसामा को काम करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। वह पूँजीवादी तरीकों से पूँजी एकत्र करने में माहिर है। अमेरिकी काँग्रेस की एक रपट के अनुसार उसके पास लगभग 30 करोड़ डॉलर की निजी सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त उसे दान में भी बहुत धन मिलता रहता है, कई सम्पत्ति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है, उसने 11 सितंबर, 2001 को किए हुए हमले में लगभग दस लाख डॉलर का खर्च किया होगा। इतना धन खर्च करना उसके लिए कठिन नहीं है। 1980 के दशक तक ओसामा के पास अधिक सम्पत्ति नहीं थी। सऊदी अरब के अमीर शेखों से उसके परिवार का संबंध था। इन दिनों भी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई के हथियार खरीदने के लिए वह धन एकत्र कर लेता था। वह अल–कायदा नामक अपने संगठन की अर्थव्यवस्था सबल बनाने के लिए प्रयासरत था। वह दान पाने के लिए अरब देशों के मुल्लाओं को फतवा जारी करने को राजी कर लिया था। ये आर्थिक स्रोत अफगानिस्तार से 1989 में सोवियत संघ के चले जाने के बाद भी बंद नहीं हुए। सऊदी अरब से हर महीने 10–20 लाख डॉलर का दान ओसामा के पास जाता है अब अमेरिका इसे बन्द करने के लिए दबाव बना रहा है। आतंकियों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हर प्रकार के अवैध व्यापार सहयोगी हैं, नशीले पदार्थ, अवैध हथियार, जाली नाटो का धंधा, तस्करी आदि इसी भूमिगत दुनिया के कारोबार हैं।

आतंकी हमले के सबसे बड़े उदाहरण रूप में अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र और पेंटागन पर हुए हमले को देखा जा रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी आर्थिक मंदी विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इस मंदी के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने

Scanned with OKEN Scanner

में सहयोगी विश्व व्यापार संगठन पर भी अँगुली उठ रही है। क्योंकि इसमें अधिकांश भागीदारी अमेरिका की है। वित्त और निवेश के वैश्वीकरण के कारण भी आर्थिक मंदी की सीमा विश्वव्यापी हो जाती है। वैश्वीकृत आर्थिक मंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी योगदान होता है। अर्थव्यवस्था के वैश्विक प्रभुत्व का अग्रणी देश अमेरिका जब इस समय आतंकवाद से क्षतिग्रस्त हुआ है, तब न केवल अमेरिका का बाजार बल्कि भारत सहित अन्य देशों के कारोबार भी पर नकारात्मक असर पड़ा है।

इन दिनों आर्थिक मंदी के मौसम में अमेरिका में नये–पुराने कारों तथा ट्रकों की बिक्री में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यह तथ्य दो सर्वेक्षण कंपनियों सी.एन. डब्ल्यू मार्केटिंग रिसर्च तथा जे.डी. पवार एण्ड एसोसिएट्स के सर्वेक्षण से सामने आयी है।

पूरे विश्व के स्टॉक बाजार पर आतंकी आक्रमण का दुष्प्रभाव छाया हुआ है। बी.एस.ई. सेन्सेक्स 21 सितंबर को अपने पिछले आठ वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 2600.12 अंको पर पहुँच गया है। भारतीय रुपये के मूल्य में भी गिरावट जारी है और यह अपने अब तक के न्यूनतम मूल्य 48.03 रुपये प्रति डॉलर पर 17 सितम्बर को बिका। बी.एस.ई. के सेन्सेक्स का स्तर दिसम्बर 1996 के 2713 एवं अक्टूबर–नवम्बर 1998 के 2741 से भी कम है जबकि सेन्सेक्स में पुनः तेजी दर्ज की गयी थी।

वर्तमान मंदी के दौर में यूरोप की विकास दर अनुमान से बहुत कम थी। केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में हुई वृद्धि से यूरोप के उत्पादकों को कुछ आशाएँ थी, लेकिन इन पर भी आतंकवादी आक्रमण ने पानी फेर दिया है।

पिछले दशक में शेयर बाजार में तेजी का रूख कायम रहने का मुख्य कारण सूचना, संचार एवं तकनीकी कंपनियों द्वारा लगातार लाभ कमाना था। इस आक्रमण से इस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

सूचना एवं संचार उद्योगों के क्षेत्र में विकसित हुई वैश्विक आपूर्ति शृंखला भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अमेरिकी कम्प्यूटर कंपनियाँ ताइवान से कम्प्यूटर पार्ट्स की खरीद में लगी थी इससे दोनों को लाभ हुआ। लेकिन यह कड़ी कब तक बनी रहेगी, इस पर संकट छाया हुआ है।

अब तो नौ परिवहन के आय में भी कमी आएगी। इससे बाहरी स्रोतों के उत्पादन पर निर्भरता घटती जाएगी। उत्पादकों को अपने माल की खपत के लिए बाहर के बाजारों से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही उत्पादन लाभ में आई कमी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिकी बाजार में आयातित मालों की कटौती हो सकती है। इससे वैश्विक स्तर पर मंदी में वृद्धि होगी।

जापान भी अपने चालू खाता अधिशेष में कमी और अपने बैंको को पूँजी देने के लिए विदेशी निवेश कम कर देगा। इससे शेयर मूल्यों में गिरावट की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई हो जाती है और यह युद्ध गंभीर रूप धारण कर लम्बे समय तक चलता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरे दिन देखने होंगे।

अमेरिका में भारतीय सॉफ्टवेय उद्योगों के उत्पादन की अच्छी ख है। भारत के उत्पादनों का 60 प्रति निर्यात उत्तरी अमेरिका और वि रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका हो है। बहुत–सी भारतीय कंपनियाँ अ कारोबार ध्वस्त हुए विश्व व्यापार के से करती थी। उनके प्रमुख ग्राह के तानेबाने टूट चुके हैं। सॉफ्टवे की तरह बीमा कंपनियाँ भी अ रुपयों की देनदारी में फँस चुकी और इन पर आश्रित उद्यमी भी च में आ गए हैं। बीमा कंपनियाँ अरब डॉलर से अधिक की देनदारी फँस चुकी है। अब दुनियाभर में ब किस्तों की लागत बढ़ जाएगी। क्यो अब आतंकी हमलों की हानि से ब के लिए कुल सम्पत्ति का बीमा करव पड़ेगा।

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों व्यापार वर्ष 2001–02 की पह तिमाही में 52 प्रतिशत की दर से था। उसमें दूसरे–तिमाही में ज्य वृद्धि की आशा नहीं की जा सक नॉसकाम के अध्यक्ष फिरोज वन्द्रेव का मानना है कि इस वर्ष में दू ओर तीसरी तिमाही में भारत कंपनियों के लाभ प्रभावित होंगे। व कंपनियों पर इसका असर अधिक सकता है। यदि भारतीय सॉफ्टवे कंपनियों के व्यापार में 30 से प्रतिशत तक की वृद्धि भी हो गई यह सबसे आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र सकता है।

भारत का पर्यटन उद्योग अमेरि पर हुए आतंकी हमले से बुरी त प्रभावित हुआ है। इस हमले के बा विमान सेवा और होटलों के आरक्ष रद्द होने लगे हैं। पर्यटन उद्योग जानकारों ने अनुमान लगाया है कि

Scanned with OKEN Scanner

औसतन लाभ 20 प्रतिशत से
ही होगा। अक्टुबर से मार्च
पर्यटन उद्योग का मौसम
इन दिनों 70 प्रतिशत यानी
.5 मिलियन पर्यटक भारत
हाँलाकि दुनिया के पर्यटन
भारत की हिस्सेदारी 0.5
है, फिर भी इस मौसम के
के पहले ही आतंक का
जबड़ा खुल गया। ट्रेवेल
डरेशन के उत्तरी क्षेत्र के
मानना है कि ऐसा लग रहा
न के मौसम का प्रारंभ होने
ी इसका अंत हो गया है।
प्रतिकूल बना रहता है तो
तक होटलों के आरक्षण
ानों की टिकटें रद्द हो

उद्योग में पहले ही मंदी
या हुआ था अब दशा और
है। फेडरेशन ऑफ होटल
एसोसिएशन के एक सचिव
है कि अगले छः माह तक
गों की दशा में सुधार की
है। जापानी पर्यटक अपना
ह मान कर रद्द कर रहे है
में युद्ध जैसी स्थिति आने
इसका मतलब स्पष्ट करते
स' के भारतीय उपमहाद्वीप
नेदेशक का कथन प्रकाश
या है कि बड़ी संख्या में
तीक्षा करो और देखते रहो
ा में हैं। इसी तरह अमेरिका
ाइन पर्यटन कंपनियाँ भी
मले से दुष्प्रभावित हुई है।
त विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश
पहले से ही आकर्षक स्थान
है फिर भी वर्ष 2000 में 2.
यन डॉलर के विदेशी निवेश
इस वर्ष इसके बढ़ने की

तेल संकट से मुद्रास्फीति बढ़ती है, इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। भारत के उद्योगों पर मंदी पहले से ही छायी हुई है, आतंकी हमले के बाद इसके सुधार में अनिश्चितता और गहराती दिखती है।

आशा की जा रही थी लेकिन बिगड़ते माहौल में यह आशा धूमिल हो सकती है। चीन और हाँगकाँग में 100 बिलियन डॉलर विदेशी पूँजी निवेश हुआ, इसकी तुलना में भारत की स्थिति नगण्य है। भारत सरकार को 10 बिलियन डॉलर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आशा थी। लेकिन इसके पूरा होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इसका नकारात्मक प्रभाव भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेश के क्षेत्र में पड़ा है। पहले विदेशी संस्थागत निवेश के लिए भारत की कंपनियों में 49 प्रतिशत से अधिक की स्वीकृत नहीं थी। लेकिन अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद यह सीमा समाप्त हो गई है अब अपने देश की किसी कंपनी के शत–प्रतिशत शेयर को कोई विदेशी कंपनी खरीद सकती है, मतलब यह कि कोई भारतीय कंपनी अपना पूरा शेयर पूरी तरह विदेशियों के हाथों में बेंचे। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति और सार्वजनिक हितों के साथ जिम्मेदारी पूर्ण राजनीतिक भूमिका नहीं कही जा सकती है।

यदि अरब देश आतंकवाद के विरुद्ध होने वाली सैन्य कार्रवाई से प्रभावित होते हैं तो तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में बेरोक वृद्धि हो सकती है। आतंकी हमले के बाद तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 26 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 31 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई। सऊदी अरब ने हर रोज 21 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन करके तेल की कीमत में संतुलन बनाए रखने का वादा पूरा कर रहा है। ओपेक देशों ने भी इस संकट से राहत देने का वादा किया है। यदि तेल की कीमत में 1 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि होती है तो भारत का आयात व्यय 500 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। खाड़ी युद्ध के समय तेल की कीमत 40 डॉलर तक पहुँच गयी थी। तेल संकट से मुद्रास्फीति बढ़ती है, इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। भारत के उद्योगों पर मंदी पहले से ही छायी हुई है, आतंकी हमले के बाद इसके सुधार में अनिश्चितता और गहराती दिखती है।

भारत प्रतिवर्ष 44.4 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात करता है। इसमें 21 प्रतिशत खरीद अमरीकी बाजार करता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय रत्न आभूषण निर्यात 35 प्रतिशत है। आतंकी हमले से इसमें 10 प्रतिशत गिरावट की संभावना है इससे देश के कारोबार में 30 करोड़ डॉलर की कमी आएगी विगत वर्ष 34.66 प्रतिशत हीरों का निर्यात अमेरिका में हुआ जिसका मूल्य 2.15 अरब डॉलर था अब इसमें 2 अरब डॉलर की कमी आने की आशंका की जा रहा है। इसी तरह आभूषण का निर्यात जहाँ बीते वर्ष में 64 करोड़ 60 लाख डॉलर का था अब 55 करोड़ डॉलर हो जाने की संभावना है। भारतीय आभूषण निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत की है। कुल 28 करोड़ डॉलर का भारतीय निर्यात

Scanned with OKEN Scanner

घटकर 25 करोड़ डॉलर तक रह जाएगा। वस्तुतः अमेरिका के सकल घरेलू आय में उपभोक्ता खर्च का अनुपात दो–तिहाई है, इसके और कम होने की उम्मीद है। इसका असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा। चूँकि अमेरिका भारत के निर्यात में 21 प्रतिशत है और सबसे अधिक विदेशी निवेशक है, यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्थाओं की तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने से भारत के आर्थिक विकास में बाधाएँ बढ़ेंगी।

आतंकी हमले के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट से सोना, चाँदी आदि मूल्य बढ़े। अफगानिस्तान से आने वाली जड़ी–बूटियाँ, मेवे और दाल के भाव भी बढ़ गए। सोना स्टैंडर्ड 315 रुपये बढ़कर 4770 रुपए प्रति दस ग्राम और चाँदी 5500 रुपए से बढ़कर 7500 रुपए प्रति किलो हो गया। ईरान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, तुर्की से आने वाला चना 125/150 रुपए बढ़कर 2170 और 3900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँचा। रंगूनी अरहर में 15 डॉलर की तेजी से आने से 80 रुपए की बढ़त से 1660 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हुई। अफगानिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध होने के कारण किसमिस की कीमत 250/4400 रुपए बढ़कर 40 किलो के लिए 10000 तक पहुँच गई। *(देखें तालिका में)*

आर्थिक मंदी के दौर में आतंकी हमले का दुष्प्रभाव रोजगार पर भी भारी रूप में पड़ा है। आज पूरी दुनिया में केवल उड्डयन उद्योग में कार्यरत एक लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। अमेरिका की दो सबसे बड़ी एयर लाइंस अपने 20–20 हजार कर्मचारियों की छँटनी करने का निर्णय ले चुकी है। अमेरिकन एयर लाइंस का कहना है कि धन की कमी के कारण इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है,। यूनाइटेड एयर लाइंस का कहना है कि हटाए गए कर्मचारियों को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। छँटनी हो रहे कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 90 हजार है। ब्रिटेन की वर्जिन एटलांटिक एयर लाइंस ने भी 1200 कर्मचारियों को निकालने का निर्णय लिया है। ब्रिटिश एयरवेज मे... नौकरियाँ खत्म हो सकती... विमान–यात्रा में आ रही भारी... के ये परिणाम दुनिया की अर्थ... में छाई मंदी और आतंक के... उत्पादित हुए हैं।

अमेरिका पर आतंकवादी हमले से पूर्व व बाद जिंसों की चाल

(भाव प्रति क्विंटल)

जिंस	10 सितंबर	वर्तमान	वृद्धि
काबली चना	3750	3900	150
राजमा लाल	1450	1625	175
चना	2045	2170	125
अरहर रंगून	1580	1660	80
मुलेठी (किलो)	40	50	10
उन्नाब (किलो)	60	75	15
रतनजोत (किलो)	24	40	16
(40 किलो)			
बादाम कैली. (40 किलो)	6100	6350	250
छुहारा रंगकाट	5000	5500	500
अंजीर (40 किलो)	9000	10000	1000
पिस्ता पेशावरी (किलो)	495	550	55
चाँदी हाजिर (किलो)	6990	7500	550
सोना स्टैंडर्ड (10 ग्राम)	4455	4770	315
डॉलर	44.34	48.02	3.60

अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था... वर्तमान दुर्दिन का विश्लेषण क... करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि... अर्थव्यवस्था शोषण और संग्र... आधारित है। हमारे देश... अर्थार्जन और उसके उद्दे... भ्रामक धारणा छाई हु... विदेशी कर्ज और विदेशी निवेश को आर्थिक उन्नति... आवश्यक माना जाता र... पर, क्या जिस कर्ज से... देशवासी प्रभावित होता है... तक कर्ज के पैसे पहुँचते... अथवा कुछ लोग कर्ज के... का लाभ उठाते है और दे... पूरे देश के सिर पर डाली... है? इसी तरह विदेशी पूँजी... से देश की सार्वजनिक... हाथ से निकल जाती है, बेरो... बढ़ जाती है और जन... आर्थिक गुलामी से पीड़ित... आतंक के हाथों का खिलौ... जाता है। बेरोजगारी और भू... से नैतिक पतन की ओर... युवक–युवतियों को आ... शोषक अर्थव्यवस्था पैदा... है तो वह आतंक को... करना नहीं चाहती, अपितु उ... को लगातार ऊर्जा देने का काम... रही है। यदि सचमुच आतंक मि... है तो ऐसी अर्थव्यवस्था के विक... विचार करना होगा जो आम जनता... की अति आवश्यक जरूरतों को अ... पूरी करे।

Scanned with OKEN Scanner

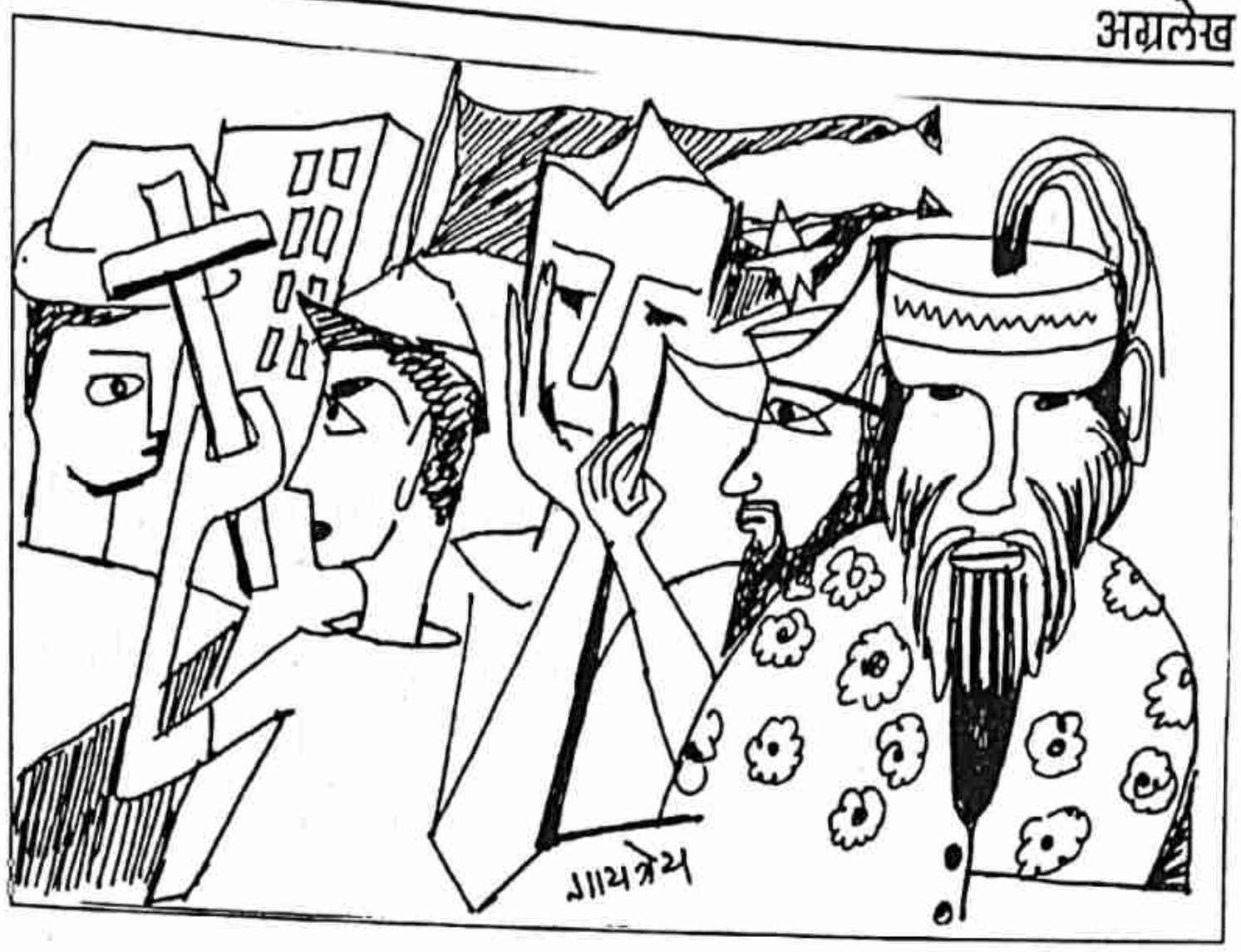

अमरीकी शोषण तथा इस्लामी कट्टरवाद से तटस्थ रहें

■ डॉ० भरत झुनझुनवाला

र्ल्ड ट्रेड सेन्टर के गिराए जाने को लोकतंत्र बनाम कट्टरवाद का मामला समझा है। भारत अमरीका के साथ इस्लामी कट्टरवाद का सामना ो उद्यत हुआ है। इस बात देखा किया जा रहा है कि लोकतंत्र के पीछे एक शोषक था है। वास्तव में इस्लामी तथा अमरीकी शोषण का दो दुष्ट लोगों के बीच है। टस्थ रहकर दोनों को आपस ने देना चाहिए।

लाम की दृष्टि से अमरीका तथा काफिर दोनों है। द्वितीय युद्ध के बाद इजराइल नामक ो जबरन बनाया गया। आधार या गया कि उस क्षेत्र से ज्यू लोगों के हजारों वर्ष पुराने संबंध है। लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत स्थानीय फिलिस्तीनियों की स्वीकृति नहीं ली गई। इसी तरह अमरीका ने ईराक पर हमला किया। ईराक–कुवैत के ऐतिहासिक संबंध पेचीदा हैं। परंतु तेल की अपनी सप्लाई को बनाए रखने के लिए अमरीका ने ईराक पर हमला किया। अमरीका के अनेक गैर लोकतांत्रिक देशों से घनिष्ठ संबंध हैं। सऊदी अरब की राजशाही से अमरीका के मधुर संबंध है चूँकि वहाँ से उसे तेल चाहिए। इसके विपरीत चिली में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई समाजवादी अयन्डे सरकार का अमरीकी एजेण्टो ने तख्ता पलट किया था। चीन की गैर लोकतांत्रिक सरकार से मधुर व्यापारिक संबंध बनाने में अमरीका को कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन लोकतंत्र का खुला मजाक है। पाँच सदस्यों को स्थाई मान्यता एवं वीटो दे दिया गया है। बाकी दुनिया के मनुष्यों को ऐसा अधिकार क्यों नहीं है? वास्तव में अमरीकी एवं अन्य पश्चिमी देशों के लोकतंत्र का आधार ही दूसरे देशों का शोषण है। अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड की आम जनता की हालत खस्ता थी। भारत जैसे देशों से लूटी गई संपत्ति से उन्हें राहत पहुँचा कर 'खरीदा' गया। अमरीका में लोकतंत्र के पीछे वहाँ की समृद्धि है जिसका एक हिस्सा दूसरे देशों के शोषण से आता है। इस प्रकार अमरीकी लोकतंत्र गरीब देशों में व्याप्त तानाशाही का प्रतिबम्ब है।

ओसमा बिन लादेन ने एक

Scanned with OKEN Scanner

कैसेट में कहा है कि "जब हम अमरीकी माल खरीदते है तो हम फिलिस्तीनियों के संहार में भाग लेते हैं। अमरीकी कंपनियाँ अरब देशों में धन कमाती हैं और अपनी सरकार को टैक्स देती हैं। उस टैक्स से अमरीका तीन अरब डॉलर प्रति वर्ष की सहायता इजराइल को देता है। इस धन का प्रयोग इजराइल फिलिस्तीनियों के संहार करने में करता है।" लादेन अमरीका के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण एवं गैर लोकतांत्रिक व्यवहार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है।

प्रोटेस्टेंट धर्म समस्या को और कठिन बना देता है। प्रोटेस्टेंट धर्म ने प्रारंभ में चर्च की संकीर्णता का विरोध करते हुए चर्च के अधिकार के स्थान पर धर्मग्रंथों के अधिकार को मान्यता दी। समयक्रम में धर्म ग्रंथों के अधिकार को भी चुनौती दे दी गई है और अब इसाइयत के व्यक्तिगत अनुभव को ही मान्यता दी जा रही है। यह व्यक्तिगत अनुभव भोगवाद का अथवा भोग–सम्मत भी हो सकता है। परमात्मा अथवा अल्लाह की सत्ता गौण हो जाती है। इसलिए अमरीकी प्रोटेस्टेंट इस्लाम की दृष्टि से काफिर बन जाते है।

दूसरी तरफ इस्लामी कट्टरवाद है जो हर गैर इस्लामी को काफिर करार देकर उस पर आक्रमण करना चाहता है। ये कट्टरवादी परमात्मा अथवा अल्लाह की सत्ता तथा मुल्लाओं की सत्ता में भेद नहीं करते हैं। जो परमात्मा अथवा अल्लाह अथवा 'गॉड' की सत्ता को स्वीकार करे परन्तु मुल्ला की सत्ता का विरोध करे उसे भी काफिर घोषित कर दिया जाता है। धर्मग्रंथ कुरान में कहा है कि

भारत को शंकराचार्य चाहिए। एक समय भारत में बौद्धों का वर्चस्व था और वे हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहे थे। शंकर ने बौद्धों से वाद–विवाद करके यह प्रमाणित किया कि बौद्ध मूल रूप से हिन्दू चिंतन का ही अनुपालन कर रहे थे।

"तुम उसे छोड़ कर किसी अन्य की उपासना नहीं करोगे" (17.23)। यहाँ 'उस' से अर्थ सर्वशक्तिमान सर्वत्र विद्यमान परमशक्ति से है जिसे हिन्दू परमात्मा, मुसलमान अल्लाह और इसाई गॉड कहते हैं। इस दृष्टि से अल्लाह, परमात्मा अथवा गॉड की सत्ता में विश्वास करने वाले कुरान के अनुसार सही रास्ते पर चल रहे हैं। परंतु इस्लामी कट्टरवाद अल्लाह और मुल्ला में भेद नहीं करता है।

दोनों ही पक्ष अपनी–अपनी कमजोरियों से ग्रस्त है। एक तरफ अमरीकी शोषणवाद है जिसे लोकतंत्र का चोगा पहना दिया गया है तथा प्रोटेस्टेंट व्यक्तिवाद है जिसका परमात्मा की सत्ता से एकसाथ स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ इस्लामी कट्टरवाट है जो अल्लाह की सत्ता तथा मुल्ला की सत्ता में भेद नहीं करता है। इन दोनों दुष्चिंतनों का समाधान आसान नहीं है चूँकि दोनों के दिमाग बंद हैं। ऐसी स्थिति में संघर्ष से ही समाधान होता है। युद्ध अवश्यंभावी है। यह मामला लोकतंत्र बनाम कट्टरवाद मात्र नहीं बल्कि शोषणवाद तथा व्यक्तिवाद बनाम कट्टरता का है।

इस्लाम के भारत पर आक्रमण का आधार बिल्कुल भिन्न है। इस्लाम के अनुसार मूर्ति पूजा वर्जित है और जन्म के आधार पर जातिभेद भी। वास्तव में हिन्दू मूर्ति पूजक नहीं है। एक निष्ठावान मुसलमान को [illegible] अध्यात्म गीता में दिए गए मूर्ति [illegible] का सिद्धान्त बताया तो उन्होंने उ[illegible] विरोध नहीं किया। सिद्धान्त य[illegible] कि उपासक अपने अंतर्मन में विद्य[illegible] परमात्मा को मूर्ति में प्रतिस्थापित [illegible] फिर मूर्ति के उस परमात्मा स्व[illegible] की उपासना करे। जिस तरह म[illegible] की तस्वीर अल्लाह की सत्ता स[illegible] में मददगार होती है उसी [illegible] मूर्तिपूजा भी परमात्मा की सत्त[illegible] आत्मसात कराने में मददगार [illegible] है। न तो हिन्दू–मुसलमान [illegible] सर्वशक्तिमान की सत्ता को [illegible] विवाद है न ही शोषण को ले[illegible] इस प्रकार मुसलमानो तथा हि[illegible] के बीच संघर्ष अनावश्यक एवं [illegible] गलतफहमी के कारण उत्पन्न [illegible] है। कश्मीर का विवाद इसी संघ[illegible] हिस्सा है। यदि कश्मीरी मुसल[illegible] को उनकी स्वयं की अल्लाह [illegible] एवं हिन्दुओं की परमात्मा भक्ति [illegible] एकरूपता का अहसास हो जा[illegible] उन्हें हिन्दुस्तान में रहने में [illegible] आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

भारत को शंकराचार्य चा[illegible] एक समय भारत में बौद्धों का व[illegible] था और वे हिन्दुओं पर अत्याचार [illegible] रहे थे। शंकर ने बौद्धों से वाद–वि[illegible] करके यह प्रमाणित किया कि [illegible] मूल रूप से हिन्दू चिंतन का [illegible]

(शेष पृष्ठ ...)

Scanned with OKEN Scanner

या यूएस–64 र्जीवित हो सकता है

क्रान्त पाण्डेय

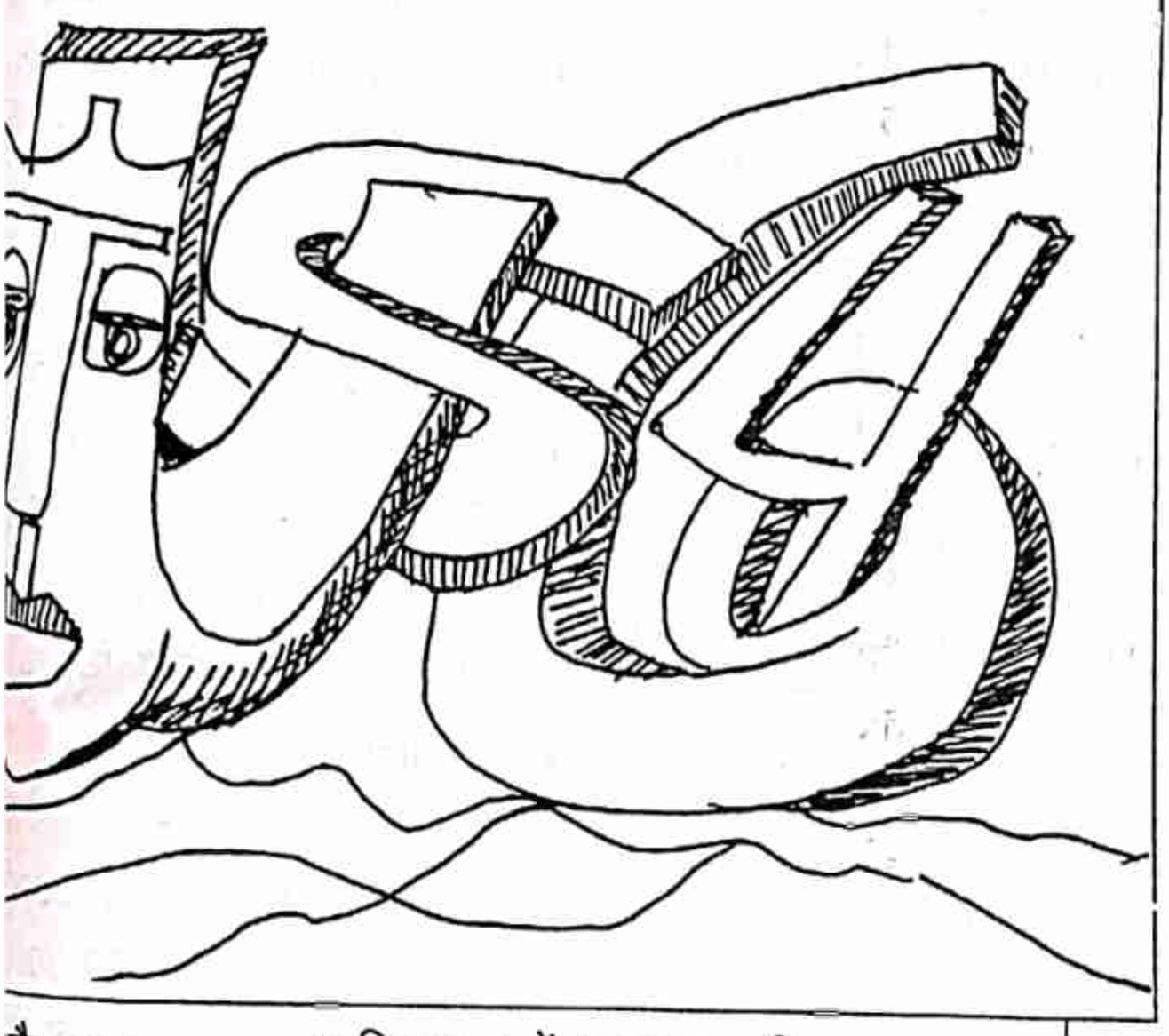

आजकल यूएस–64 सम्पूर्ण देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो वित्तीय संस्थाओं तथा आम विनियोजकों में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। संसद में तथा प्रधानमंत्री सचिवालय में बहस का विषय यूएस–64 है। विरोधी दल ने वित्तमंत्री को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। स्टॉक एक्सचेंज और पूँजी बाजार में अस्थिरता व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यूएस–64 को जीवित रखना एक अनिवार्यता है।

यूएस–64 का वन्द होना या टूटना आर्थिक विश्लेषकों की दृष्टि में एक अभूतपूर्व घटना या सुनिश्चित षड़यंत्र है। इतिहास साक्षी है कि आर्थिक घटनाओं के प्रतिफल को मात्र संसद की बहुमत से रोका नहीं जा सकता है। ऐसी घटनायें सरकार बदल देती हैं। कभी–कभी आर्थिक संरचनाएँ ही बदल जाती हैं। यूएस. एस. आर. ज्वलंत उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यूएस–64 को पुर्नजीवित करना संभव है। इसका स्वतः जवाब है कि यूएस–64 मरा नहीं है। मात्र बीमार है और बीमारी की जड़ पकड़ में आ गयी है। इसे चलाने के उपाय किए गए हैं। परिस्थिति को बदल देने से प्रतिक्रिया पैदा हो। नहीं तो प्रतिक्रिया की परंपरा चल पड़ेगी। सभी वित्तीय संस्थाएँ इस दुष्ट चक्र में पूरी तरह फँसकर सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को चकना चूर कर देगी। इस चक्र को रोकना है। इस चक्र को बंद करने के दो उपाय हैं। पहला तत्काल और मनोवैज्ञानिक तथा दूसरा उपाय दीर्घकालिक एवं वैधानिक हैं।

ौर कर) दो घटनाएँ त हैं। किंतु की तिथि और की मात्रा चत है। किसी आज जो हम करते हैं प्रतिफल कुछ वाद में है।

तकाल उपाय

मृत्यु और कर (टैकस) दो घटनाएँ निश्चित हैं। किंतु मृत्यु की तिथि और टैक्स की मात्रा अनिश्चित है। किसी प्रकार आज जो हम कार्य करते हैं उसका प्रतिफल कुछ समय वाद में होता है। आज जो रकम हम बचत खाता में डालते हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि जिस दिन इस रकम को निकालेंगे उस दिन इसकी क्या कीमत होगी। जब हम स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या रिटर्न मिलेगा,

Scanned with OKEN Scanner

क्योंकि पूँजी बाजार अनिश्चित है। हमारे जीवन में और खासकर आर्थिक क्षेत्र में जोखिम और अनिश्चितता का वातावरण रहता है। जोखिम को कम करने के लिए कुछ व्यक्ति बीमा कराते हैं। कुछ व्यक्ति निश्चित आय वाली शेयर को खरीदते हैं। यूएस–64 इसी प्रकार की एक म्युचुअल फण्ड है। जिसमें चार करोड़ विनियोजकों एवं प्रारंभिक संस्थाओं की पूँजी लगी हुयी है। तत्काल यूनिट ट्रस्ट की 87 योजनाएँ चल रही हैं। इसका विनियोग देश के 1300 विभिन्न कंपनियों में है। किंतु यूएस–64 की तरह कोई मजबूत एवं लोकप्रिय योजना नहीं है। इन योजनाओं में वे लोग विनियोग करते हैं जो संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं।

परंतु अपने समाज में एक दूसरे प्रकार के भी लोग हैं जो जोखिमों से प्यार करते हैं और अनिश्चितता में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जीव जुआ भी खेलते हैं। इन्हीं में से एक वर्ग सट्टाबाजी करता है। वे लोग देश के स्टॉक एक्सचेंज और पूँजी बाजार में अपने कुकृत्यों से उथल–पुथल करते रहते हैं। ये चिड़ियों के समान सट्टा बाजार में इधर–उधर फूदकते रहते हैं। येन–केन प्रकारेण वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री के नजदीकी हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी नजदीकी वन जाय या उनके कार्यालय में कोई ऋणी या महाजन मिल जाए। वे सौदा करना जानते हैं। डॉ. सी.डी. देशमुख नहीं फँसे। स्व. मुरारजी भाई देशाई, 7 पूर्ण बजट प्रस्तुत किए किन्तु दलालों के चंगुल में नहीं फँसे। टी.टी. कृष्णामचारी घिर गये तो रातों रात मुद्राकाण्ड में विदा हो गए। 1986 में तत्कालीन वित्त मंत्री घिर गए थे। हर्षद मेहता काण्ड में प्रधानमंत्री फँस गए थे। उनको भी जाना पड़ा। जो वित्तमंत्री इन सट्टेबाजों से नजदीकी बनाए वे गए तथा जो इनको तंग किए वे भी गए। वर्तमान वित्तमंत्री श्री सिन्हा ने नज़दीकी किया तथा वाद में उनको तंग किया। यह सर्वविदित है कि वर्तमान वित्तमंत्री ने मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 7 निदेशकों को हटाया। दूसरी तरफ केतन पारिख और पी. एस. सुब्रह्मनियम से अच्छा संबंध रखा। बाद में दोनों जेल गए और आए। दोनों ही परिस्थितियों में वित्तमंत्री हो हटना है। जितना जल्द यह निर्णय होगा उतना ही जल्द यूएस–64 पुनः निरोग एवं स्वस्थ हो जाएगा। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। पूँजी

एशिया महादेश के ही कई मुल्क आर्थिक दुष्चक्र में पूरी तरह फँस गए हैं। यूटीआई इस देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक अंग है। इससे देश के विनियोजको का विश्वास भंग हो जाएगा।

बाजार तथा स्कंध विनिमय का रूख निश्चितरूप से साकारात्मक होगा। इसके विपरित अगर वित्तमंत्री को हटाया नहीं जाता है तो सम्मिलित सरकार कमजोर होगी और घटल दल विकल्प की तलाश करेंगे। भाजपा का ग्राफ गिरेगा।

दीर्घकालिक

मजबूत वित्तीय व्यवस्था के लिए बैंक एवं पूँजी बाजार की सेवाएँ सुदृढ़ होनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में अगर एक भी पक्ष कमजोर है तो व्यवस्था को चौपट होने से बचाना कठिन है। गत कुछ महीनों में एशिया महादेश के ही कई मुल्क आर्थि दुष्चक्र में पूरी तरह फँस गए यूटीआई इस देश का एक महत्व आर्थिक अंग है। इससे देश विनियोजको का विश्वास भंग जाएगा। तो बचत और विनि दोनों प्रभावित होगा। भार औद्योगिक विकास बैंक, आई.एफ. आई. एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं के रास्ते पर तेजी से बढ़ रह रुपए के मूल्य में गिरावट, वि संस्थाओं की आर्थिक दुर्दशा दु संकेत है। आर्थिक अनिश्चितत कोई कार्यक्रम सफल नहीं ह इसका ज्वलंत उदाहरण अर्जेंट की अर्थव्यवस्था है जो 1990 दुष्चक्र में फँसकर समाप्त के व पर है। भारत में जो आर्थिक वि है वह अर्जेंटाइना से कुछ भिन्न है।

यह भी स्पष्ट है कि भा यूनिट ट्रस्ट इस घटना से बच लिए प्रयत्नशील है। ट्रस्ट सहम कि कई बैंकों की सहायता से स की जमानत पर ऋण लेकर यूएस को रास्ते पर लाकर विनियोजक विश्वास को जीत ले। यह भी समझ हुआ है कि स्टेट बैंक मोडेल प का कार्य करेगा और 5000 क रुपए की जमानत देकर 3000 क रुपए ऋण बैंकों से लेकर यूएस को चालू कर दे। किंतु आर्थि विश्लेषकों के विचार से यह योज स्थायी निदान नहीं है। इस योज के तहत 15 बैंक 10 प्रतिशत सूद दर से 6 माह के ऋण देंगे। अ यह अवधि 6 माह से अधिक होगी पीएलआर की दर से सूद चार्ज होग इसके साथ ही साथ बैंक यह चाहते हैं कि वे जमानती स्टॉक व्यापार करें। यह एक खतरनाक कद

Scanned with OKEN Scanner

र यूटीआई को यह कदम
ना चाहिए।
आई ने यह भी निर्णय लिया
-मण्डलीय (ग्लोबल) इंडिया
ारी किया जाए। इसका
ी आगामी वर्ष में नुकसानदेह
ह कदम भी नकारात्मक
ोगा। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री
दिरण ने कहा कि वे शेयरों
मूल्य पर बेचेंगे तथा उन
के विरुद्ध सख्त कदम
जो विनियोग पर लाभोपार्जन
ही हैं। 1998–99 के वार्षिक
के अनुसार ट्रस्ट ने
कोष से 12, 816.59 करोड़
विनियोग समता अंशों में
यह रकम भी 1997–98
11) से कम है। यहाँ तक की
दारी (रीडेम्पसन) योजना
नस को उत्साहित नहीं कर
थम तीन दिनों में मात्र 13
पए का प्रार्थना पत्र प्राप्त

अतः यूएस–64 को चालू करने के लिए एक हल्का परिवर्तन अधिनियम में करने की जरूरत है। यूटीआई की 86 योजनाएँ हैं। ये योजनाएँ 10 प्रकार की है। जैसे सतत् खुली यूनिट योजनाएँ, मासिक आय यूनिट योजनाएँ, अस्थायी आय यूनिट, विशेष योजनाएँ, वृद्धि योजनाएँ, आय एवं वृद्धि योजनाएँ, विदेशी निधियाँ एवं उद्यम पूँजी ये योजनाएँ विभिन्न वर्षों में चालू की गयी हैं। वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक योजना की आर्थिक चिट्ठा तैयार की जाती है। यूएस–64 का भी अलग तैयार किया जाता है। इसकी पूँजी विनियोजकों एवं संस्थापकों दोनों की है। शेष स्कीम में केवल विनियोजकों की पूँजी लगी है। इसलिए प्रत्येक योजना का लाभ–हानि और आर्थिक चिट्ठा न बनाकर उस ग्रुप की खाता तैयार की जाए। जैसे यूएस–64, यूएस–71, सीआरटीअस–81, सीजीजीएफ–86, यूएस–95, पीईएफ–95, सीजीएफ–99 तथा एसयूएस–99 को मिलाकर एक आर्थिक चिट्ठा शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (एनएपी) के आधार पर तैयार की जाए। यूएस–64 को भी एनएवी पर आधारित किया जाए।

वास्तव में यूटीआइ का आर्थिक चिट्ठा स्पष्टरूप में तैयार नहीं किया जाता है। तथ्यों को सजाकर दिखाना एक प्रकार से जालसाजी है। अंकेक्षकों के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपार्जित आय की अवधारणा गलत है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 23 के अनुसार आय की गणना होनी चाहिए किन्तु प्रतिवेदन से लगता है कि उसका पालन यूएस–64 के संबंध में नहीं हुआ है। इसी प्रकार ब्याज एवं अन्य व्ययें को आवंटन धारा 25(1) और (2) के अनुसार नहीं हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि ट्रस्ट की लेखा पद्धति में सुधार कर दिया जाए तो कोई स्कीम आर्थिक कठिनाई में नहीं पड़ेगी और विनियोजकों का विश्वास कायम रहेगा। ■

का शेष.....)

अमरीकी शोषण तथा इस्लामी कट्टरवाद से तटस्थ.....

न कर रहे थे। बुद्ध भगवान
तार माना गया। इसी प्रकार
विश्यकता इस बात की है कि
न भाईयों को बताया जाए कि
ी उन्हीं की तरह अल्लाह की
विश्वास करते है। साथ–साथ
न आधारित जाति व्यवस्था को
खाड़ फेंकना है। यदि हम
इन कमजोरियों को दूर कर लें
मारा विवाद समाप्त हो सकता
में यह नहीं भूलना चाहिए कि
ा बिन लादेन एक निष्ठावान

मुसलमान है जो बीमार गरीबों को शहद एवं जूड़ी–बूटियाँ बाँटा करता है। सभ्रांत घराने में पैदा होने के बावजूद उसने रेगिस्तानी युद्ध का कठिन रास्ता अपनाया है। जबकि अमरीकी लोकतंत्र के राष्ट्रपति एक इंटर्न के साथ अनैतिक यौन संबंध रखते थे।

भारत एवं इस्लाम का संघर्ष महज गलतफहमी के कारण है। न तो भारत दूसरे देशों का शोषण करता है न ही अल्लाह की सत्ता को नकारता है। हमारा लोकतंत्र भी दूसरे देशों के शोषण पर नहीं खड़ा है। इसके विपरीत अमरीका का लोकतंत्र फर्जी है, वह दूसरे देशों के शोषण में लिप्त है तथा उसकी अल्लाह की सत्ता की स्वीकारिता भी संदिग्ध है। इसके विरुद्ध खड़ा है इस्लामी कट्टरवाद जो शोषण, फर्जी लोकतंत्र एवं नास्तिकता का विरोधी है परंतु साथ–साथ स्वयं मुल्लावाद से ग्रस्त है। अमरीकी शोषणवाद एवं इस्लामी मुल्लावाद के इस युद्ध में हमें नहीं पड़ना चाहिए। भारत को दोनों से बराबर दूरी बनाए रखना चाहिए ओर अपना ध्यान शंकराचार्य जैसे वार्तालाप में लगाकर शुद्ध इस्लाम से आत्मसात करना चाहिए। ■

Scanned with OKEN Scanner

लेख

विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास

■ रुद्र दत्त

जाहिर है कि बहुत सी कच्ची वस्तुएं जिनका स्वतंत्रता पूर्व काल में निर्यात होता था, अब उनका प्रयोग देश के औद्योगिक कारखानों में कच्चे माल के रूप में होने लगा और इस कारण, विनिर्माण क्षेत्र जो स्वतंत्रता पूर्व काल में उपेक्षित रहा, की ओर राष्ट्रीय सरकार ने अधिक ध्यान दिया। ऐसा करना स्वाभाविक था क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात लगातार कही गयी. . . .

जैसे–जैसे आर्थिक विकास होता है उसके साथ–साथ कृषि का देश को कुल आय में भाग कम हो जाता है और क्रमशः विनिर्माण का भाग बढ़ जाता है और इसके साथ–साथ सेवा क्षेत्र के भाग में भी वृद्धि होती है। 1950–51 में विनिर्माण क्षेत्र का कुल देशीय उत्पाद में भाग 13.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 1970–71 में 19.9 प्रतिशत हो गया और फिर बढ़ता हुआ 1998–99 में 24.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया। जाहिर है कि अब विनिर्माण क्षेत्र कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग एक–चौथाई जुटाता है। यह उपलब्धि अच्छी कही जा सकती है और आर्थिक विकास के सिद्धांत के अनुकूल है। कुल रूप में, 1950–51 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (1993–94 की कीमतों पर) 1950–51 में 18,670 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1970–71 तक रुपए 58,997 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार 1950–51 से 1970–71 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.63 प्रतिशत थी जो अर्थव्यवस्था की 3.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक थी। 1970–71 से 1998–99 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान (1993–94 की कीमतों पर) जो 1970–71 में 58,997 करोड़ रुपये था बढ़कर 1998–99 में 2,65,434 करोड़ रुपए हो गया अर्थात इस 28 वर्षों की अवधि में विनिर्माण क्षेत्र बढ़कर 4.5 गुना हो गया और इस अवधि में (1970–71 से 1998–99) में इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.52 प्रतिशत रही। यह भी इस काल के दौरान कुल देशीय उत्पाद की 4.74 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। जाहिर है कि बहुत सी कच्ची वस्तुएं जिनका स्वतंत्रता पूर्व काल में निर्यात होता था, अब उनका प्रयोग देश के औद्योगिक कारखानों में कच्चे माल के रूप में होने लगा और इस कारण, विनिर्माण क्षेत्र जो स्वतंत्रता पूर्व काल में उपेक्षित रहा, की ओर राष्ट्रीय सरकार ने अधिक ध्यान दिया। ऐसा करना स्वाभाविक था क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात लगातार कही गयी कि ब्रिटिश शासन हमारे देश से कच्चे माल का निर्यात करता है और ब्रिटिश कारखानों द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में विक्रय करके मुना कमाता है।

समय निर्माण क्षेत्र के आंकड़ों ये तथ्य प्राप्त होते हैं कि औसत में प्रति कारखानें में 3.11 करोड़ की अचल पूंजी का विनियोग कि गया और प्रत्येक कारखाने से करोड़ रुपये की शुद्ध मूल्य वृद्धि की गयी। औसतन एक कारखा 73 कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त जिसमें 56 श्रमिक थे। प्रति कर्म अचल पूंजी के रूप में 4.25 रुपये का विनियोग किया गया। मूल्यवृद्धि में औसतन प्रति कर्म योगदान 1,57,112 रुपये था जि प्रति कर्मचारी 51,972 रुपये वेतन मजदूरी के रूप में प्राप्त किये अर्थात शुद्ध मूल्यवृद्धि का लगभग प्रतिशत। जाहिर है कि विनिर्माण में गैर–मजदूरी भुगतान अर्थात किर ब्याज और लाभांश का कुल मूल्यवृद्धि का 67 प्रतिशत था। अ पूंजी और शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनु 2.7 था जिससे यह पता चलता है पूंजी उत्पाद अनुपात 2.7 रहा जो व्यक्त करता है कि शुद्ध उत्पादन 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए अचल पूं के रूप में 2.7 गुना विनियोग आवश्य था।

परन्तु विनिर्माण क्षेत्र में स आकार की इकाइयाँ विद्यमान है इसका और गहरा विश्लेषण करने लिए हमने कारखानों को विनियुक्त

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर वर्गीकृत कर यह किया कि पिद्दी क्षेत्र के में जिनमें 5 लाख रुपये तक गी हुई थी, की संख्या 59,131 त कारखानों की संख्या का शत) परंतु इनमें 2,760 करोड़ ी कुल अचल पूंजी लगी हुई पूंजी का केवल 0.7 प्रतिशत) में 6,281 करोड़ रुपये की 15.96 लाख कर्मचारियों द्वारा गयी। जाहिर है कि पिद्दी कारखानों में 0.7 प्रतिशत पूंजी द्वारा 4 मूल्यवृद्धि प्राप्त ी और 16.1 कर्मचारियों को उपलब्ध कराया इससे एक बात जाती है कि ये श्रम प्रधान थे, नमें प्रति श्रमिक वार्षिक मजदूरी रुपये थी। अतः रखाने अधिक तो प्रदान करते इनमें औसत का स्तर बहुत ।

से 100 लाख रुपये की पूंजी 56,496 कारखाने थे अर्थात लघुस्तर क्षेत्र के कारखाने थे। 0,724 करोड़ रुपये की अचल की अचल पूंजी लगी हुई थी 18,890 करोड़ रुपए की शुद्ध द्धि प्राप्त की गयी। इस प्रकार तिशत अचल पूंजी से 12.1 त मूल्यवृद्धि प्राप्त हुई और 24. लाख (अर्थात 24.7 प्रतिशत) ारियों को रोजगार प्रदान किया जाहिर है कि यह क्षेत्र भी श्रम प्रधान है, चाहे इसमें पिद्दी क्षेत्र की तुलना में अधिक पूंजी लगी हुई। इस विवरण से साफ विदित होता है 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी सीमा वाले कुल कारखानों में केवल 5.6 प्रतिशत अचल पूंजी के आधार पर 16.1 प्रतिशत मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी और लगभग 41 प्रतिशत कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया गया।

तीसरा वर्ग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की पूंजी सीमा का है जिसे मध्यम स्तर कारखाने का कहा जाता

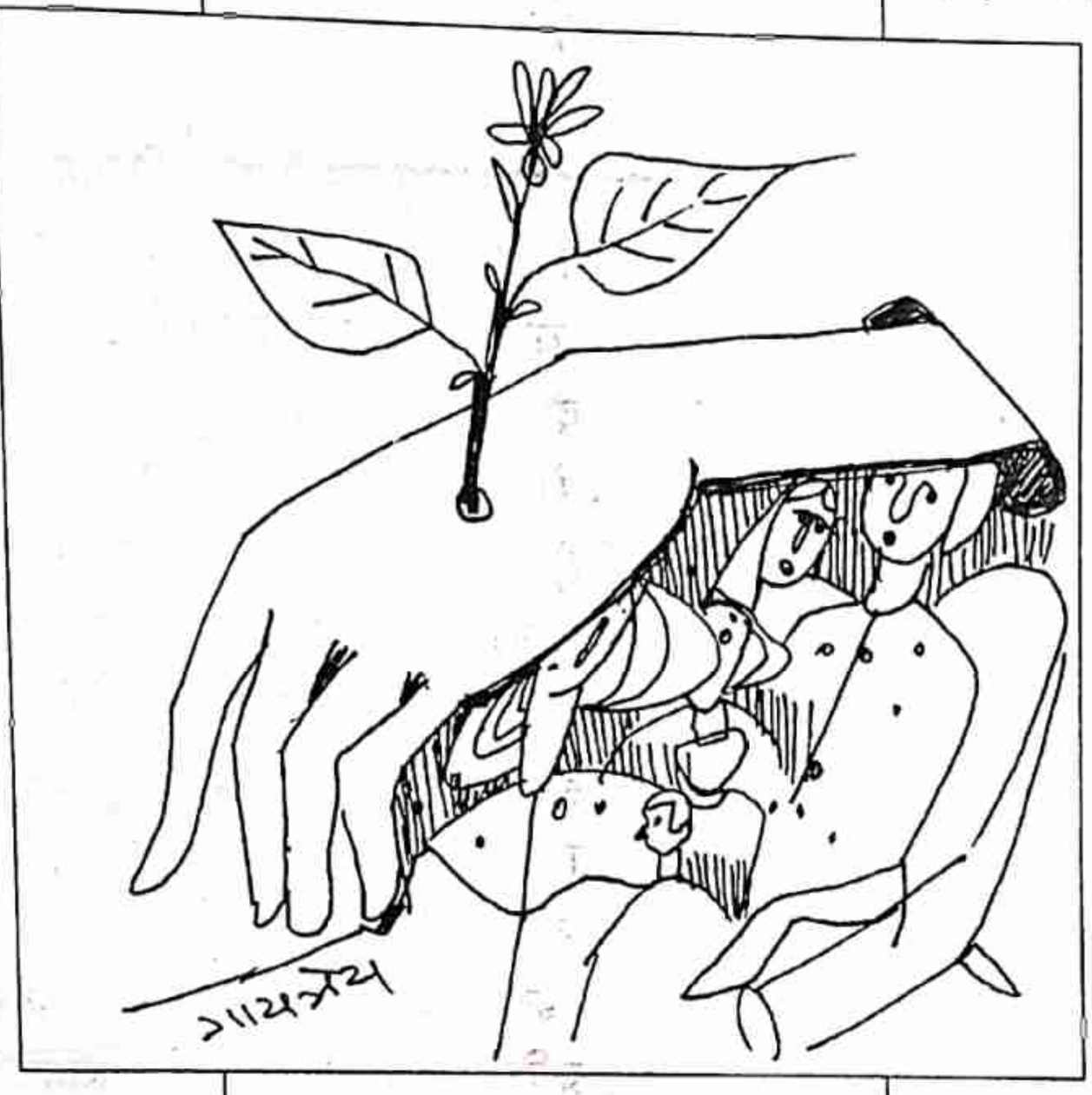

है। इसमें 13,913 कारखाने थे जिनमें 54,263 करोड़ रुपये की अचल पूंजी द्वारा 31,534 करोड़ रुपये की शुद्ध मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी जिसके आधार पर 16.76 लाख कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सापेक्ष रूप में कहा जा सकता है कि लगभग 13 प्रतिशत अचल पूंजी से 20.2 प्रतिशत शुद्ध मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी और 22.6 प्रतिशत कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस दृष्टि से यह वर्ग भी श्रम प्रधान ही कहा जा सकता है।

लघु क्षेत्र के कारखानों में श्रमिक संगठित नहीं होते, परंतु बड़े पैमाने के कारखानों में वे सबल मजदूर संघ कायम कर संगठित हो जाते हैं।

चौथा वर्ग 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपये की पूंजी सीमा का है जिसे बड़े पैमाने के कारखाने कहते हैं। इस वर्ग में केवल 5,369 कारखाने थे जिनमें 1,51,854 करोड़ की अचल पूंजी द्वारा 49,935 करोड़ रुपए की शुद्ध मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी और 26.72 लाख कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सापेक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि 36 प्रतिशत अचल पूंजी द्वारा 32 प्रतिशत शुद्ध मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी और 26.9 प्रतिशत कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस दृष्टि से यह वर्ग पूंजी प्रधान है क्योंकि इसमें पूंजी की अधिक मात्रा द्वारा अपेक्षाकृत कम श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

पांचवां वर्ग 100 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी सीमा का है जिसे बहुत बड़े पैमाने के कारखाने कहते हैं। इस वर्ग में केवल 642 कारखाने थे जिनमें 1,91,917 करोड़ रुपये की अचल पूंजी लगी हुई थी और इसमें 49,307 करोड़ रुपये की शुद्ध मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी और केवल 9.61 लाख कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध

Scanned with OKEN Scanner

कराया गया। सापेक्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 45.5 प्रतिशत अचल पूंजी से 31.6 प्रतिशत शुद्ध मूल्यवृद्धि प्राप्त की गयी, किंतु केवल 9.7 प्रतिशत कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस दृष्टि से यह वर्ग अत्यधिक पूंजी प्रधान माना जा सकता है क्योंकि इसमें केवल लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारी रोजगार प्राप्त थे।

जैसे–जैसे कारखानों की पूंजी सीमा में वृद्धि होती है, अचल पूंजी की मात्रा शुद्ध मूल्यवृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। इसे आम भाषा में पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे–जैसे पूंजी सीमा बढ़ती है, तो उत्पादन में 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पूंजी लगानी पड़ती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, पूंजी सीमा की वृद्धि के साथ कारखाने की पूंजी गहनता में वृद्धि होती है।

इसी प्रकार यदि प्रति कर्मचारी अचल पूंजी की मात्रा पर विचार करें, तो यह बात पता चलती है कि जहाँ पिद्दी क्षेत्र और लघु क्षेत्र में प्रति कर्मचारी क्रमशः 0.17 लाख रुपये और 0.84 लाख रुपये की अचल पूंजी लगी हुई थी, वहां बड़े पैमाने और अत्यधिक बड़े पैमाने के कारखानों में प्रति कर्मचारी अचल पूंजी की मात्रा क्रमशः 5.68 लाख रुपये और 19.96 लाख रुपये थी।

इसी तरह यदि प्रति श्रमिक शुद्ध मूल्य वृद्धि पर विचार करें, तो पिद्दी क्षेत्र में यह 39,319 रुपये थी, जो लघु क्षेत्र में 77,014 रुपये हो गयी और फिर मध्यम क्षेत्र में बढ़कर 1,40,654 रुपये हो गयी। परंतु यह बड़े पैमाने के क्षेत्र में 1,86,856 रुपये तक और अत्याधिक बड़े पैमाने के वर्ग में एकदम बढ़कर 5,12,923 रुपये हो गयी। जाहिर है कि पूंजी सीमा में वृद्धि के साथ प्रत्यक्षतः प्रति श्रमिक शुद्ध मूल्यवृद्धि में वृद्धि होती है जो पूंजी की गहनता में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम उत्पादिता में वृद्धि के रूप में प्रकट होती है।

इसी प्रकार यदि प्रति श्रमिक औसत मजदूरी पर विचार करें, तो यह ज्ञात होता है कि पिद्दी क्षेत्र में औसत मजदूरी 16,757 रुपये थी, जो लघु क्षेत्र में बढ़कर 25,313 रुपये हो गयी, मध्यम क्षेत्र में और बढ़कर 40,124 रुपये तक पहुँच गयी। परंतु बड़े पैमाने के कारखानों में यह और बढ़कर 57,759 रुपये और अत्यधिक बड़े पैमाने के वर्ग पर 94,657 रुपये की सीमा पर पहुँच गयी है। जाहिर है कि कारखानों की पूंजी–सीमा स्तर में उन्नति के साथ प्रति श्रमिक औसत मजदूरी में वृद्धि होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जैसे–जैसे कारखानों में पूंजी–गहनता बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे इन कारखानों में अपेक्षाकृत अधिक कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ती है जिन्हें अधिक मजदूरी देनी पड़ती है। दूसरे, लघु क्षेत्र के कारखानों में श्रमिक संगठित नहीं होते, परंतु बड़े पैमाने के कारखानों में वे सबल मजदूर संघ कायम कर संगठित जाते हैं। ये मजदूर संघ भी को संगठित क्रियाओं से मजदूरी बढ़ाने सफल हो जाते हैं। अंतिम, मजदू को शुद्ध मूल्यवृद्धि के अनुपात में जाए, तो यह बात स्पष्ट होती है जहाँ पिद्दी क्षेत्र और लघु क्षेत्र में अनुपात क्रमशः 37 प्रतिशत और प्रतिशत था, यह मध्यम क्षेत्र में प्रतिशत और बड़े पैमाने एवं अत्यधि बड़े पैमाने के कारखानों में क्रम कम होकर 22 प्रतिशत और प्रतिशत हो गया। जाहिर है कि पैमाने के वर्गों में पूंजीपति वर्ग किराया, ब्याज एवं लाभांश के रूप अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त है।

इस विश्लेषण का सार यह है रोजगार की दृष्टि से पिद्दी एवं लघु और मध्यम क्षेत्र को ही प्रोत्साहन दि जाना चाहिए, परंतु जटिल परिमार्जित वस्तुओं के उत्पादन लिए बड़े पैमाने पर अत्यधिक पैमाने वाले कारखाने अधिक योगद दे सकते हैं। अतः देश में इन दो प्रक के श्रम–प्रधान एवं पूंजी प्रधान कारखा में सामंजस्य स्थापित करने आवश्यकता है, ताकि उत्पादन रोजगार वृद्धि के लक्ष्यों में तालमे बिठाया जा सके।

कोल्ड ड्रिंक्स एवं दिमागी रोग

प्रसिद्ध चिकित्सक एन. डब्ल्यू. वाकर ने हाल ही में अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'वाटर कैन अंडर माइन योर हेल्थ' में लिखा है कि यदि कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन किया जाए तो यह सेरेबरल पाल्सी व अन्य दिमागी रोग उत्पन्न कर सकता है। यह दिमाग के तंत्रिकाओं को क्षीण कर देता है।

कोल्ड ड्रिंक्स में जहरीले रसायन

कैफीन के अलावा कोला में एमरंथ रेडद्व बोरडिएक्स ब्राउन, आरेंज वन पीला, पौंसियाऊ नामक कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए बेहद घातक व नुकसानदायक है।

Scanned with OKEN Scanner

वैश्वीकरण में श्रम मानक एवं श्रमिक

■ मुकुन्द कुमार

अपने स्थापना काल (1995) से ही विश्व व्यापार संगठन अपने कार्यशैली के कारण विवादित रहा है। विशेष रूप से श्रमिकों पर इसका प्रभाव व्यापक ढंग से हुआ है। वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन में अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को बहुपक्षीय

व्यापार व्यवस्था में सम्मिलित करने का मुद्दा विश्व के अनेक सामाजिक एवं आर्थिक मंचों में विवाद का विषय बना हुआ है। विकसित देश श्रम मानकों को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहते है जबकि विकासशील देश इसका विरोध कर रहे है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों में व्यापार करने की खुली छूट मिली हुई है जिससे पूरे विश्व में उपभोक्ताओं की अभिरूचियों में एकरूपता आई है।

विश्व व्यापार संगठन में श्रम मानकों के समर्थकों का मानना है कि विकासशील देशों में श्रम सस्ता होने के कारण इन देशों का उत्पादन विश्व व्यापार में तुलनात्मक रूप से सस्ता है, जिसके कारण इन देशों का निर्यात बढ़ा है। इनके अनुसार सस्ते निर्यात के कारण विकसित देशों के रोजगार में कमी आ रही है, जिसके कारण श्रमिकों की मजदूरी घट रही है लेकिन विकासशील देश इस तर्क से सहमत नहीं है। विकसित देशों द्वारा श्रम एवं पर्यावरण मानकों की आड़ में विकासशील देशों के निर्यात पर गैर–प्रशुल्क प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। अभी तक श्रम मानकों के संरक्षण की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की है। अगर कोई देश इसकी सिफारिशों को स्वीकृति देता है, तब यह स्वीकृति उस देश का कानून का अंग बन जाता है। भारत अभी तक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 36 सिफारिशों को स्वीकृत कर चुका है।

श्रम मानकों को व्यापार से जोड़ने पर बहस 19वीं शताब्दी से ही चल रही है, लेकिन 1980 एवं 1990 के दशकों में इस मुद्दे ने अधिक जोर पकड़ा, खासकर विश्व व्यापार संगठन के स्थापना वर्ष में यह ज्यादा विवादित हो गया। विकसित देशों द्वारा सिंगापुर में आयोजित प्रथम वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्रम मानकों को विश्व व्यापार संगठन में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन विकासशील देशों के विरोध के कारण यह घोषित किया गया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम मानकों से निबटने में सक्षम है। लेकिन विकसित देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर हुई अपनी हार को पचा नहीं पाये और यदा–कदा इस मुद्दे पर बहस करते रहे। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जार्लेन बर्सिफ्सकी ने सम्मेलन के अंत में कहा "हमें यह समझना चाहिए कि

Scanned with OKEN Scanner

कर्मचारियों के कल्याण एवं अधिकार का मुद्दा निरपेक्ष रूप से व्यापार बहस का मुद्दा है, चाहे हम सैद्धांतिक रूप से माने या नहीं।"

सिएटल सम्मेलन में विकसित देशों ने इस मुद्दे को एक बार फिर जोर शोर से उठाया, अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि श्रम मानकों के उल्लंघन करने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। अर्थशास्त्री इसे विकसित देशों में फैली बेरोजगारी को दूर करने का उपाय मानते है। विकसित देश अपने यहाँ फैली बेरोजगारी का मुख्य कारण विकासिल देश के सस्ते निर्यात को जिम्मेदार मानते है। श्रम मानकों को विश्व व्यापार की कार्यसूची में सम्मिलित करने के पक्ष में समर्थकों ने विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं –

1. श्रम सस्ता होने के कारण विकसित देशों की पूँजी विकासशील देशों की तरफ जा रही है, जिसके कारण विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2. विकसित देशों के उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए अपने श्रम मानकों में कमी कर सकते है, जिससे इन देशों के रोजगार एवं मजदूरी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
3. विकासशील देशों के सस्ते निर्यात को ये अपने यहाँ फैली बेरोजगारी तथा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में स्थिरता के लिए जिम्मेदार मानते है।

जबकि कुछ विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययन यह बताते है कि आयात प्रतिस्पर्धा एवं बेरोजगारी में बहुत कम संबंध है। मरकस (1997) द्वारा किए गए अध्ययनों से इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि विकासशील देशों के उद्योगों में घटिया श्रम मानक विकसित देशों के व्यापार, रोजगार एवं पूंजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

भारत की स्थिति

भारत मानव एवं श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है ऐसा संविधान में लिखित है उसके बावजूद भारत श्रम मानकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जोड़ने के खिलाफ है, क्योंकि इससे देश के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, संरक्षणात्मक प्रवृति बढ़ेगी तथा ये एक प्रकार से गैर प्रशुल्क प्रतिबंध होंगे जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के बजाए पूंजीपतियों के हितों को संरक्षित करेंगे।

निःसंदेह भारत के विभिन्न निर्यात प्रधान उद्योगों में श्रम मानकों की स्थिति खराब है। कामगारों को न्यूनतम निर्धारित

(शेष पृष्ठ 35 पर)

श्रमिक संघ संशोधन विधेयक लोस में पारित

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूर यूनियनों की बढ़ती संख्या पर लगाम कसने और कामकाज का स्वस्थ माहौल बनाने के लिए लाये गये श्रमिक संघ संशोधन विधेयक 2001 को लोकसभा ने ध्वनि मत से पास कर दिया। राज्यसभा में यह पहले ही पास हो चुका है। इस अवसर पर श्रममंत्री सत्यनारायण जटिया ने घोषणा की कि सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए जल्दी ही एक व्यापक विधेयक लाएगी। जाटिया ने सदन में श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा का संक्षिप्त उत्तर देते हुए बताया कि श्रमिकों के कल्याण के लिए दूसरा श्रम आयोग काम कर रहा है। इसकी सिफारिशें मिल जाने के बाद सरकार सभी श्रम संगठनों से विचार विमर्श करेगी तथा सदन में इस बारे में एक व्यापक विधेयक लाएगी।

इस विधेयक में श्रमिक संगठनों के पंजीकरण के लिए श्रमिकों की मौजूदा संख्या सात को बढ़ाकर एक सौ अथवा किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत मजदूरों की कुल संख्या का दस प्रतिशत करने की व्यवस्था है। जटिया ने बताया कि यह विधेयक रामानुजम समिति और उनके मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है तथा इससे देश में एक स्वस्थ ट्रेड यूनियन परंपरा विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे पहले लोकसभा में श्रमिक संघ कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान सभी पक्षों के सदस्यों ने उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की पुरजोर वकालत की। केंद्रीय श्रमंत्री सत्यनारायणन जटिया ने श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक सदन में विचारार्थ पेश करते हुए कहा कि आज की बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक संघों की बढ़ती संख्या में कमी लाना है।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के पवन सिंह घाटोवाद ने कामगारों के हितों के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर और बदली हुई परिस्थितियों में ये संशोधन काफी नहीं है।

श्री घाटोवाद ने कहा कि रामानुजम समिति ने अन्य मामलों में कई सिफारिशें की थी। लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला वर्षों से लंबित पड़ा रहा है। श्रमिक संगठनों से मिलकर बातचीत करने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो कुछ हो रहा है वह केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जिनकी संख्या केवल 18 प्रतिशत है। उन्होंने जानना चाहा कि देश के 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होगी। वे ही असली भारत है।

Scanned with OKEN Scanner

प्राकृतिक संपदा पर सेंधमारी, क्यों और कब तक!

देवेन्द्र शर्मा

सबके लिये दोषी भारत कार है जो इस संपदा के क्षण के लिये कानून बनाने असफल रही हैं। जैव विधता के प्रस्तावित कानून मामला ही देख लीजिए। वरण और वन मंत्रालय पेचीदा मुद्दे पर सहमति पहुंचने में चार साल से ज्यादा का समय लग ।

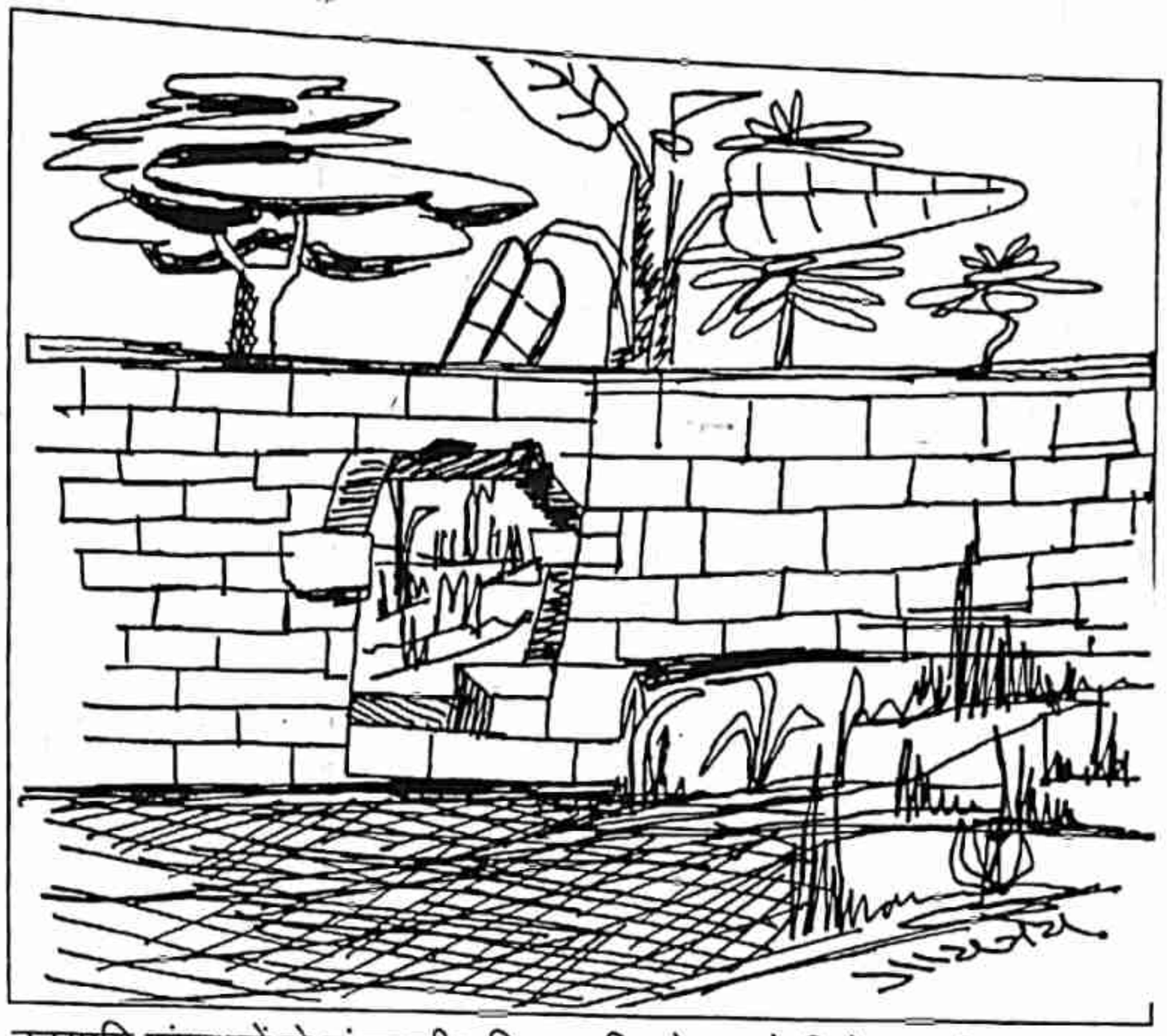

क बार फिर भारत झपकी लेते हुए मिला। एक ओर जहाँ अमेरिकी कंपनी राइसटेक के ती पर पेटेन्ट के दावे को की पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय स्वीकार कर लेने के फैसले पर ीतिक और बौद्धिक बहस हो कि यह 'जीत' है अथवा 'हम हीं देश अब भी राष्ट्रीय संसाधनों क्षण के लिये तत्पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बहस जारी तु विकसित देश चुपके–चुपके लगातार परंपरागत ज्ञान तथा स्तु जो बौद्धिक संपदा नियंत्रण ष्टि से लाभदायक है, का पेटेंट चले जा रहे हैं। वास्तविकता कि भारतीय कंपनियाँ, सरकारी न और नागरिक समूह इन नेयों द्वारा पारंपरिक ज्ञान और वनस्पति संसाधनों के संग्रह की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में सहायता पहुँचा रहे हैं।

यह स्थापित तथ्य है कि इन कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेटेंट के फलस्वरूप समूची खाद्य आपूर्ति व्यवस्था भारत की खाद्य सुरक्षा इन कंपनियों द्वारा हासिल किये जाने वाले मुनाफे पर निर्भर करने लगेगी। चूँकि खाद्य उत्पादों के मामले में विविधता और बहुलता की दृष्टि से भारत की जासूसी के ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर पशुओं, चटनी से लेकर आधे उबले चावलों और इडली से पुलाव तक ये खाद्य–सेंधमार हर उस वस्तु की तलाश में हैं जो बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिहाज से उनके फायदे की है। यहाँ तक कि एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने रिहाड्रेशन के लिये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आमतौर पर दी जाने वाले दवा पर भी पेटेंट हासिल कर डाला है।

इसी तरह की चौकाने वाली खबर एक अमेरिकी कंपनी द्वारा काली मिर्च के सहउत्पाद पिपेरीन का प्रौसेस पेटेंट हासिल कर लेने की है। पिपेरीन बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा कर देने वाला पदार्थ हैं। केरल की एक फर्म को अमेरिका के सैविंसका कारपोरेशन ने कानूनी नोटिस देकर दावा किया है कि पिपेरीन के फार्मूले पर उसके पास 1996 से पेटेंट है। और तो और

इंग्लैड की कंपनी जॉर्ज विलियम सन लिमिटेड ने चाय की पतियों को तोड़ने से लेकर डिब्बों में पैक करने तक की समूची उत्पादन प्रक्रिया पर पेटेंट के लिये दावा ठोक दिया है।

Scanned with OKEN Scanner

इसे देखते हुए समूचे देश में सर्वसामान्य द्वारा प्रयुक्त इस प्रक्रिया पर एकाधिकार जामाने की कोशिश को चाय बोर्ड ने चुनौती दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी नेसले पहले ही वैजीटेबल पुलाव और अधपके चावलों पर यूरोपीय पेटेंट हासिल कर चुकी हैं।

भारत अपनी विशेष स्थिति वाले क्षेत्र अर्थात् औषधीय पौधों के मामले में केवल इतना ही कर रहा है कि हल्दी, बैंगन, करेला तथा जामुन मधुमेह ठीक करने वाली वनस्पतियों पर अमेरिका द्वारा प्राप्त पेटेंट की जांच–पड़ताल और उसे कानूनी चुनौती दे रहा है। इस बीच स्थिति यह है कि अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, यूरोप पेटेंट कार्यालय और जापान पेटेंट कार्यालय से आंवले के औषधीय तथा सौंदर्यवर्धक गुणों पर बड़ी संख्या में पेटेंट हासिल कर लिये गये हैं या फिर उनके समक्ष विचाराधीन हैं। अमेरिका में इस संदर्भ में कम से कम पांच पेटेंट मंजूर किए जा चुके हैं जबकि जापान के पेटेंट कार्यालय में चार मामले विचारधीन हैं। और इनमें ज्यादातर पेटेंट किसी ऐसी वस्तु की रासयनिक संरचना से संबंधित हैं जिसका भारत को परंपरागत ज्ञान रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य औषधीय वनस्पतियों के ज्ञात गुणों पर भी विभिन्न पेटेंट अधिकार हासिल कर लिये गए हैं।

इस सबके लिये दोषी भारत सरकार है जो इस संपदा के संरक्षण के लिये कानून बनाने में असफल रही हैं। जैव विविधता के प्रस्तावित कानून का मामला ही देख लीजिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय को पेचीदा मुद्दे पर सहमति पर पहुंचने में चार साल से भी ज्यादा का समय लग गया। इसके बाद उसने जैव विविधता विधेयक तैयार किया जो संसद के समक्ष विचार के लिये पड़ा हुआ है। सांसद किसी न किसी बहाने सदन की कार्यवाही रोकने का मौका तलाशते रहते हैं जबकि यह कानून लागू करने में देश समय गवाँ रहा है। इसी का नतीजा है कि यह विधेयक आज भी अटका पड़ा है।

उत्पाद विशेष के भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा में असफलता की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) के अनुच्छेद भौगोलिक संकेतकों के लिये नियमों का प्रावधान करते हैं। यह कानून यदि लागू कर दिया जाता तो अन्य देशों के लिये बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय और बीकानेरी भुजिया जैसे विशिष्ट उत्पादों का पेटेंट हासिल करने में कठिनाई होती है। हकीकत यह है कि भौगोलिक संकेतकों के लिए विधेयक को 1999 में कानून का रूप दे दिया गया। लेकिन अगस्त 2001 तक इस कानून के प्रावधान, नियम और कायदे का विवरण तक तैयार नहीं किया जा सका।

भारत अगर बासमती के भौगोलिक संकेतकों के प्रावधानों के अंतर्गत ही ले आता, जो एक उत्पाद को अन्य देशों द्वारा बाजार बेचने पर कानूनी प्रतिबंध लगाता तो बासमती चावल भारतीय उत्पा ही बना रहता। पेटेंट (संशोधन) कानू 1999 जैसे वैधानिक उपाय कि व्यापार संगठन के दबाव में लागू कि गए थे। इतना ही महत्वपूर्ण वैधानि नियमन संयुक्त राष्ट्र के जैव विविध प्रस्ताव के अंतर्गत स्वदेशी वनस्पति और परंपरागत ज्ञान पर प्रभुसत्ता नियंत्रण का प्रावधान करता है। लेकि वह भी किसी न किसी कारण संसद में अटका पड़ा है परिणामस्वरूप अमेरिका, यूरोप, जाप और आस्ट्रेलिया की निजी कंपनि और संस्थान बेशकीमती वनस्पति और सूक्ष्म जीवों की देश के जंग में टोह लेते घूम रहे हैं। अने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों ने भारत कंपनियों के साथ शोध समझौते क लिये हैं ताकि वे विशेष पौधों अ जीवों का संग्रह और संप्रेषण क सकें।

अब जबकि जड़ी–बूटियों

कोल्ड ड्रिंक्स एवं आपके दाँत

अमरीका के मशहूर दंत चिकित्सक डॉ. राबर्ट चेज तथा दंत चिकित्सा विज्ञान के क्लिनिकल रिसर्च न्यूज लेटर के संपादक एवं प्रकाशक डॉ. जार्डन क्रिस्टेन्सन ने साफतौर पर माना है कि कोल्ड ड्रिंक्स (मीठा कार्बेनेट पानी) का पोषण मान तो नगण्य है ही और यह आपके दाँतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमरीका के मिशिगन विश्वविद्यालय के स्कूटल ऑफ डेन्टीस्ट्र के प्रोफेसर फिलिप जैन का अध्ययन है कि एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स में साढ़े छह से दस चम्मच चीनी होती है जो दाँतों में गड्डा बनाने तथा दाँतों को सड़ाने के लिए पर्याप्त हैं वे कहते हैं कि जब बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो चीनी मुँह के लार के बैक्टीरिया से मिलकर एक अम्ल बनाता है जो दाँतों की ऊपरी परत पर प्रहार कर दाँतों की ऊपरी परत पर प्रहार कर दाँतों को गला देता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स, चाकलेट, कैण्डी या केक आदि को निकाल फेंकने की अपील की है।

Scanned with OKEN Scanner

पश्चिम की ओर खिसक गया
त परंपरागत औषधि प्रणाली
ोपैथी को फिर से मजबूती
लिये कार्यदलों के गठन में
है और नवीं योजना के लिये
सिफारिशें तैयार करने की आम
में जुटा हुआ है। एक ओर
ीति निर्माता तथा योजनाकार
प्रावधानों पर मुग्ध हैं, वही
तीय पौधों पर धड़ाधड़
ष्ट्रीय पेटेंट किए जा रहे हैं।
में वनस्पतीय पौधों पर चीन 46
पेटेंट हासिल करके अव्वल
जबकि जापान 20 प्रतिशत
स तथा यूरोपीय संघ ने 12–12
पेटेंट हासिल किए थे। इस
अमेरिका और आस्ट्रेलिया भी
हिस्सा लेने में कामयाब रहे
उन्होंने 10–10 प्रतिशत पेटेंट
किए।

ह बड़ी अजीब बात है कि भारत
से क्षेत्र में विश्व प्रतिस्पर्धा में
छूट रहा है, जिसमें अब भी
विशिष्टता हासिल है। आठवें
में भारत दुनिया में सबसे बड़ा
ति निर्यातक था तब वह अकेले
य संघ को हर साल 10 हजार
भी अधिक पौधे और 14 टन से
वनस्पति उत्पाद निर्यात करता
बाद के अध्ययनों से पता चलता
1992 में भी सबसे ज्यादा
त वाले औषधीय 74 प्रकार के
में से कम से कम 22 की आपूर्ति
रहा था। पिछले पांच साल के
न भारत से अकेला जर्मनी 40
र टन औषधीय वनस्पतियों का
ात करता रहा है। जहां तक भारत
औषधीय पौधों के निर्यात की बात
ो कानूनी और गैर–कानूनी दोनों
लिहाज से उसका निर्यात 3 से 4
गुना तक बढ़ा है।

जहां यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि कानूनी तौर पर देश से बाहर व्यापार के लिये भेजे जाने वाले औषधीय पौधों का हिस्सा बहुत मामूली है, वही यह तथ्य अपनी जगह सही है कि आज भी भारत वनस्पतीय सामग्री के संग्रह की दृष्टि से और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा आमची सहित मानकीकृत दवा प्रणाली और परंपरागत ज्ञान के दस्तावेजों के मामले में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में परंपरागत पद्धति से चिकित्सा करने वाले लगभग 4.60 लाख चिकित्सकों में से 2.71 लाख रजिस्टर्ड हैं। उनकी पहुँच 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक है। इसीलिए हाल के वर्षों में भी परंपरागत दवा निर्माताओं की संख्या लगातार बढ़कर 7843 तक पहुँच गयी है। यह संख्या लाइसेंस प्राप्त दवा निर्माताओं की है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति आधारित दवाओं के प्रयोग में स्पष्ट इजाफा हुआ है। 1990 में दो हजार से अधिक यूरोपीय कंपनियां हर्बल दवाओं का व्यापार कर रही थीं। इसके अलावा 223 बड़ी दवा कंपनियां नई दवाओं की खोज के लिए पौधों की जांच–परख में जुटी थी। यह केवल एक दशक का घटनाक्रम था। 1992 में रियो सम्मेलन में जैव विविधता संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर से विभिन्न देशों की सरकारों के अपने वनस्पति जैव संसाधनों पर प्रभुसत्तात्मक अधिकारों पर तो मोहर लगाई गई थी लेकिन इन संसाधनों से विकसित उत्पादों पर वर्चस्व जैसे अधिक जटिल सवाल को यूँ ही छोड़ दिया गया। इसका फायदा बहुराष्ट्रीय दवा उद्योग अपना विश्व एकाधिकार बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन के तामझाम की मदद से उठा रहा है।

बहुराष्ट्रीय दवा उद्योग बाजार पर अपना शिकंजा कसने के लिये पेटेंट अधिकारों के अलावा डब्ल्यूटीओ के अन्य प्रावधानों का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत के लिये इस प्रकार की पहल निश्चित रूप से वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली को नुकसान पहुँचाने वाली सिद्ध होगी। भारत के औषध महानियंत्रक का पूर्वानुमान है कि सन 2000 तक 25 प्रतिशत पाबन्दी घटाने के स्वीकृत मानदण्ड के फलस्वरूप ऐलोपैथी उद्योग धराशयी हो जाएगा। भारत में बनने वाली अधिकतर दवाएं बाजार से बाहर हो जाएंगी क्योंकि आयातित दवाएं सस्ती होंगी। इस परिस्थिति में भारतीय चिकित्सा प्रणाली की अपेक्षाकृत लाभकारी और मजबूत हालत बनी नहीं रह पाएगी। बौद्धिक संपदा नियंत्रण और औषधीय पौधों के मामले में अति सक्रिय नीति से राष्ट्रीय हितों की रक्षा होने के साथ–साथ विश्व बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखना भी संभव होता। यह सही है कि अब भी असमंजस बना हुआ है कि सैकड़ों साल से चले आ रहे नुस्खों और उत्पादों का पेटेंट कैसे किया जाए। लेकिन यह भी सही है कि परंपरागत दवाओं पर ही दुनियाभर में सैकड़ों पेटेंट लिये जा रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि जहाँ भारत अब भी बहस और इस मामले में सोच विचार में लगा हुआ है, वही अन्य देश परंपरागत ज्ञान के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं पेश कर रहे हैं और पेटेंट के लिये दावे कर रहे हैं। इस लेन–देन में भारत में अपने मौजूदा ज्ञान के भंडार पर नियंत्रण को खोता जा रहा है। ■

Scanned with OKEN Scanner

कोयला के अतिरिक्त किसी अन्य ऊर्जा उत्पादन स्रोत के ठीक से विकास न करने के कारण आज हमारे देश में जहाँ दुनिया के 15 प्रतिशत आबादी रहती है को दुनिया के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत मिल पाता है वहीं अमेरिका और रूस जिनकी सम्मिलित आबादी दुनिया की कुल आबादी का 7 प्रतिशत है का विद्युत उत्पादन एवं उपभोग पूरी दुनिया के 50 प्रतिशत के बराबर है।

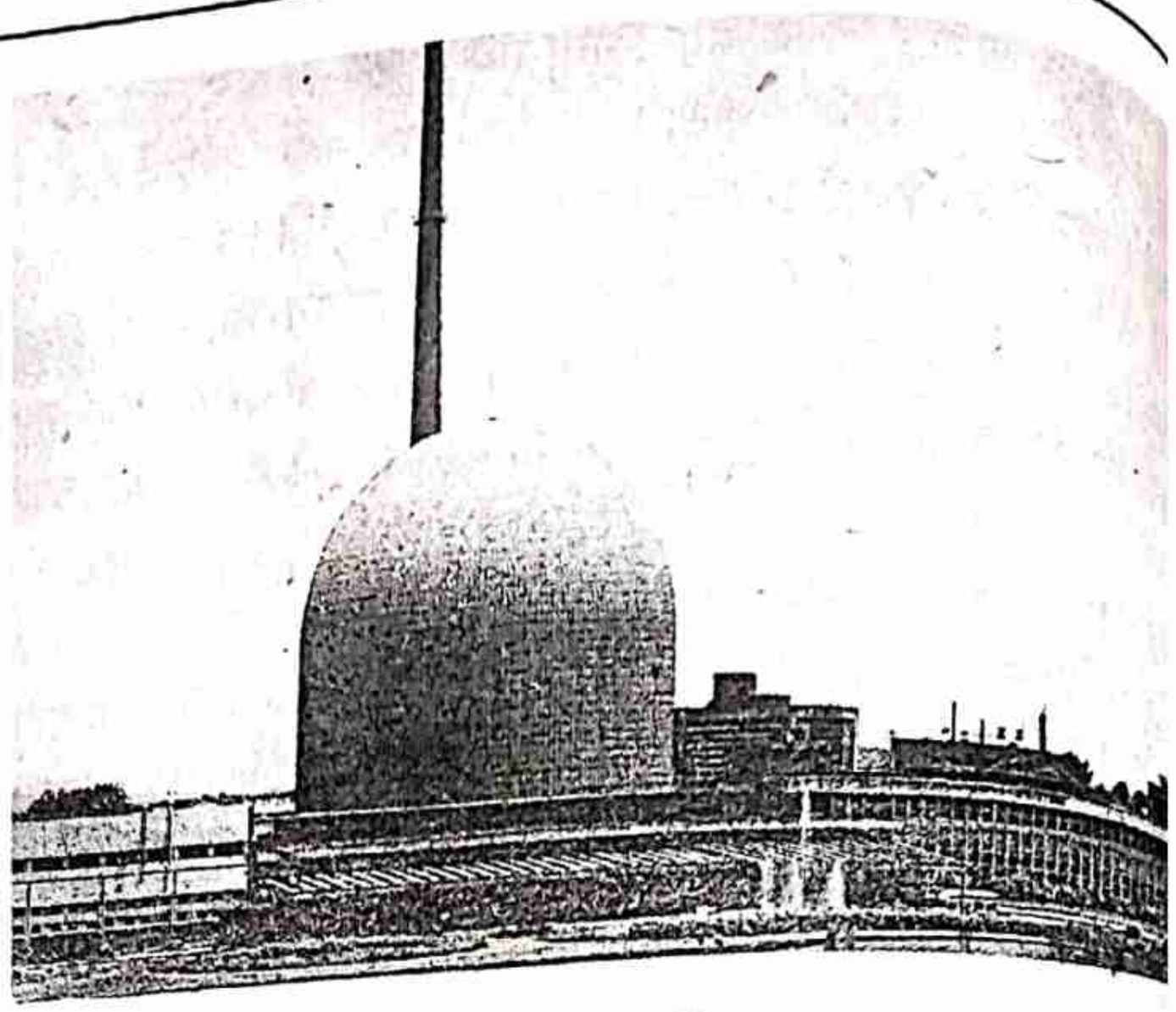

नाभिकीय ऊर्जा : देश के लिये उत्तम विकल्प

■ धीप्रज्ञ द्विवेदी

11 सितम्बर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक राजधानी वाशिंगटन डी.सी. में अवस्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक पेन्टागन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की वाणिज्यिक शजधानी न्यूयार्क में अवस्थित वैश्वीकरण के अग्रस्तंभ बहुमंजिले वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुये अबतक के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों ने जहाँ मंदी में डूबी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बेहदा तगड़ा झटका दिया उसके साथ ही हमारा ध्यान हमारे देश के महत्वपूर्ण समस्या की तरफ पुनः आकृष्ट किया। इस हमले में अमेरिका में हजारों लोग मारे गये, अरबों डॉल्र का नुकसान हुआ जिसके साथ ही अचानक रुपये के डॉलर के मुकाबले मूल्य में भयंकर गिरावट हुयी और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया। रुपये के मूल्य में डॉलर की तुलना में आयी भारी गिरावट (करीब 3.60 रुपये) तथा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने से देश के तेल पूल घाटे में अचानक बढ़ोत्तरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। देश की मंदी में फँसी अर्थव्यवस्था के लिये तेल पुल के घाटे में बढ़ोत्तरी कंगाली में आटा गीला होने जैसा है।

तेल पूल के इस घाटे का कारण, हमारी अर्थव्यवस्था का अपनी ऊर्जा उपलब्धता के लिये पेट्रो पदार्थों पर निर्भरता है जिसके लिये हम ओपेक देशों पर निर्भर हैं। ओपेक देश कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य तय करते है जिसमें विकसित राष्ट्रों की भी भूमिका होती है। अभी अमेरिका प हुये आतंकवादी हमलों के बाद कच्च तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बढ़ का कारण यह माना जा रहा है कि इन हमलों के प्रतिक्रिया स्वरू अमेरिका अपने ही मानस पुत्र तालिबा पर हमला करेगा। इस हमले के परिणामस्वरूप तेल के मूल्यों में वृद्धि अवश्यंभावी है साथ ही उदारीकरण के परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य में अस्थिरता जारी रहेगी। रुपये के मूल्य के अस्थिर होने के कारण तेल पूल घाटे में और बढ़ोत्तरी होगी। तेल पूल घाटे में होने वाली इस बढ़त का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये और बुरा हो सकता है।

तेल पूल के इस घाटे से उबरने के लिये हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पेट्रो

Scanned with OKEN Scanner

पर अपनी निर्भरता को कम होगा। क्योंकि तेल एवं अन्य दार्थों की मूल्य वृद्धि का सीधा र्थव्यवस्था पर पड़ेगा जिसमें अपने तेल पूल के घाटे को रने के लिये पेट्रो पदार्थों के वृद्धि करेगी जिससे सभी के मूल्य में वृद्धि होगी। देश पेट्रो पदार्थों के उपलब्धता +घरेलू उत्पादन) का 25 सैन्य क्षेत्र, में 27 प्रतिशत पर तथा 48 प्रतिशत ऊर्जा होता है। वर्त्तमान में 30 प्रति बैरल के मूल्य पर तेल घाटा प्रतिमाह 200 करोड़ ढ़ रहा है जिससे इस वित्त अगले छह महीनों में इसके अनुमान की अपेक्षा 1200 रुपये ज्यादा होने का संभावना है।

पूल के इस घाटे तथा भविष्य पदार्थों के उत्पादन में होने गेरावट की वैज्ञानिकों की को ध्यान में रखते हुये यह क हो गया है कि हम इसके वेकल्पों पर विचार करें।

के प्रमुख विकल्पों में है सौर समुद्री ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ली परियोजनायें, नाभिकीय बॉयो मास इत्यादि।

मारे देश में नाभिकीय ऊर्जा न की काफी संभावनाये हैं। पास विखण्डन द्वारा आण्विक उत्पादन के लिये आवश्यक माल के रूप में देश के विभिन्न में उच्चकोटि यूरेनियम तथा म का पर्याप्त भंडार है। नाभिकीय के पर्याप्त उत्पादन से न केवल पदार्थों पर हमारी निर्भरता न्यूनतम बल्कि पेट्रो पदार्थों के उपयोग होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति

हमारे देश में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की काफी संभावनाये हैं। देश के पास विखण्डन द्वारा आण्विक ऊर्जा उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे माल के रूप में देश के विभिन्न भागों में उच्चकोटि यूरेनियम तथा थोरियम का पर्याप्त भंडार है। नाभिकीय ऊर्जा के पर्याप्त उत्पादन से न केवल पेट्रो पदार्थों पर हमारी निर्भरता न्यूनतम होगी बल्कि पेट्रो पदार्थों के उपयोग से होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी।

नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करने वाली नाभिकीय क्रियायें दो तरह की होती है – (1) विखण्डन, (2) संलयन। अब तक प्रमुख रूप से पूरी दुनिया में विखण्डन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गयी है। किसी भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखण्डन कहलाती है। उदाहरण स्वरूप जब कोई मन्द न्यूट्रॉन यूरेनियम–235 के नाभिक से टकराता है तो बेरियम और क्रिप्टान के दो हल्के नाभिक उत्पन्न होते हैं साथ ही तीन तीव्र न्यूट्रान भी उत्पन्न होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम के एक अणु के विखण्डन से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (मेव) ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एक अणु प्राकृतिक गैस के जलने से उत्पन्न ऊर्जा के 200 मिलियन गुना ज्यादा है। 1 ग्राम यूरेनियम के विखण्डन से $5x10^{23}$ मेवा ऊर्जा मुक्त होती है जिससे लगभग $2x10^{4}$ किलोवाट घंटा विघुत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नाभिकीय विखण्डन में उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉन मन्दित होकर यूरेनियम के अन्य नाभिकों का विखण्डन करते हैं। पुनः न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रम चलता रहता है जिसे शृंखला अभिक्रिया कहते हैं। शृंखला अभिक्रिया दो तरह की होती है – अनियंत्रित तथा नियंत्रित। अनियंत्रित शृंखला अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता और विनाश होता है। यह परमाणु बम में होता है। नियंत्रित शृंखला अभिक्रिया में समुचित साधनों द्वारा जैसे बोरोन या कैडमियम जैसे न्यूट्रॉन अवशोषक तत्वों के छड़ों द्वारा न्यूट्रॉनों की संख्या नियंत्रित रखी जाती है और मुक्त नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों (यथा बिजली उत्पादन) में किया जा सकता है। यह नियंत्रित शृंखला अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टरों में होती है और उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं शांतिपूर्ण कार्यों में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में विखण्डनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम–235, यूरेनियम–238 या प्लूटोनियम–239 का प्रयोग होता है मॉडेरेटर या न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का तथा न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में बोरोन या कैडमियम का उपयोग करते हैं। शीतल जल का प्रयोग कर उपकरण को ठंडा रखा जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों से न केवल ऊर्जा मिलती है बल्कि इसने चिकित्सकीय प्रयोग हेतु रेडियो समस्थानिक तथा अन्य रेडियोधर्मी तत्व

Scanned with OKEN Scanner

> **यूरेनियम के एक अणु के विखण्डन से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट (मेव) ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एक अणु प्राकृतिक गैस के जलने से उत्पन्न ऊर्जा के 200 मिलियन गुना ज्यादा है। 1 ग्राम यूरेनियम के विखण्डन से 5×10^{23} मेवा ऊर्जा मुक्त होती है जिससे लगभग 2×10^{4} किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।**

भी उत्पन्न किए जाते है।

नाभिकीय रिएक्टर दो तरह के होते हैं तापीय रिएक्टर तथा ब्रीडर रिएक्टर। तापीय रिएक्टर में यूरेनिम–235 का उपयोग होता है जिसकी उपलब्धता कुल उपलब्ध यूरेनियम का केवल 0.7 प्रतिशत है। अतः तापीय रिएक्टरों का प्रयोग महंगा तथा अलाभकारी है। ब्रीडर रिएक्टरों में यूरेनियम–238 तथा थोरियम–232 का उपयोग होता है जिनसे क्रमशः अन्य रेडियो धर्मी तथा विखण्डनीय तत्व प्लूटोनियम–239 एवं यूरोनियम–233 उत्पन्न होते है जिनकी मात्रा अपने मातृ पदार्थों से ज्यादा होती है।

दुनिया का पहला नाभिकीय रियेक्टर 1942 में इटैलियन भौतिक विज्ञानी इनरिको फर्मी के नेतृत्व में अमेरिका तैयार हुआ। आज अमेरिका में 111 नाभिकीय रियेक्टर हैं जिनसे उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा अमेरिका के सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता के 22 प्रतिशत के बराबर है। यूरोपीय देश बेल्जियम की 52 प्रतिशत ऊर्जा नाभिकीय रियेक्टरों द्वारा उत्पादित होती है। जबकि भारत की कुल उत्पादित ऊर्जा का केवल 3 प्रतिशत ही नाभिकीय ऊर्जा होती है।

भारत में एटामिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1948 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिये की गयी थी। भारत के पास वर्त्तमान में 5 परमाणु रियेक्टर हैं – अप्सरा (सबसे पहला), सायरस, ज़र्लीना, पूर्णिमा तथा ध्रुव।

भारत में अभी निम्न परमाणु शक्ति गृह हैं – रावतभाटा, तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, काकरापाड़ा तथा कैगा।

इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 2500 मेगावाट हो गयी है। अन्य सात परमाणु बिजली घर विभिन्न स्थानों पर निर्माणधीन हैं। वर्ष 1999–2000 में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन 27.1 प्रतिशत बढ़ा है। 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 97,846 मेगावाट थी जिसमें तापीय विद्युत उत्पादन 72 प्रतिशत, पनबिजली उत्पादन 24 प्रतिशत, नाभिकीय विद्युत उत्पादन 3 प्रतिशत और पवनविद्युत उत्पादन 1 प्रतिशत था। स्थापित क्षमता 31 दिसम्बर 2000 में बढ़कर 1,00,136 मेगावाट हो गयी है। इसमें तापीय संयंत्रों का योगदान 80 प्रतिशत, पनबिजली का 18 प्रतिशत और शेष नाभिकीय तथा पवनऊर्जा संयंत्रों का योगदान है।

भारत सरकार द्वारा अपने आर्थिक समीक्षा (2000–2001) में दिये गये उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि देश ऊर्जा उत्पादन के लिये मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर निर्भर है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर हमारी यह निर्भरता हमें दूसरे देशों पर निर्भर बनाती है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम करने तथा बजट घाटे में तेल पूल घाटे को कम करने के लिये आवश्यक है कि हम अपने निजी स्रोतों पर ध्यान दें और उनके विकास के लिये कदम उठावें।

हमारे देश की बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता है। हमारे यहाँ उपभोग का स्तर निम्न है, अर्थात प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल 200 यूनिट बिजली की खपत है जिसे बढ़ाकर 2000 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष करना होगा। इसके लिये वर्त्तमान स्थापित क्षमता में 400 से 500 गीगावाट (एक गीगावाट 1,000 मेगावाट के बराबर होता है) बढ़ाना पड़ेगा। हमारे रिन्यूयेबल ऊर्जा स्रोत इतने बड़े नहीं हैं और अभी विकसित भी नहीं है। अतः हमें नाभिकीय ऊर्जा की तरफ ध्यान देना है।

हमारे यहाँ 50,000 टन यूरेनियम का भंडार है जिसका अभी दोहन किया जा सकता है। भविष्य में और भी भंडार मिलने की उम्मीद है। जिसके उपयोग से भारी पानी रियेक्टरों (तापीय) द्वारा 12,000 मेगावाट बिजली ही उत्पादित हो सकती है वह भी केवल 30 वर्षों के लिये जबकि हमारी आवश्यकता 400,000 से 500,000 मेगावाट बिजली की है। इस प्रकार हमारा तापीय रियेक्टर कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता।

लेकिन तापीय रियेक्टरों द्वारा उपभुक्त ईंधन से पुर्नउत्पादित यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रियेक्टरों में किया जा सकता है। तापीय रियेक्टरों में यूरेनियम के केवल 0.5 प्रतिशत से ही विद्युत का उत्पादन होता है जबकि फास्ट ब्रीडर रियेक्टरों में 75 से 80 प्रतिशत यूरेनियम का उपयोग होता है क्योंकि

Scanned with OKEN Scanner

यूरेनियम 238, प्लूटोनियम में
जाता है। इसका अर्थ यह हुआ
स्ट ब्रीडर रियेक्टरों से तापीय
ों की अपेक्षा 150 गुना ज्यादा
का उत्पादन होता है। जिससे
र्त्तमान यूरेनियम भंडार से
का उत्पादन कई शताब्दियों
सकता है। यहाँ तक कि
म्न स्तरीय यूरेनियम का भी
किया जाता है। इसके द्वारा
नी वार्षिक आवश्यकता का
70 प्रतिशत अर्थात लगभग
0 मेगावाट बिजली उत्पादित
ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा
ोडर रियेक्टर फ्रांस का 1,200
क्षमता का सुपरफेनिक्स है।
ारे देश की प्रमुख समस्याओं
ऊर्जा की समस्या है। ऊर्जा
स्या हमारे कोयला एवं अन्य पेट्रो उत्पादों पर निर्भर रहने की स्थिति में और गंभीर होती जाएगी। कोयला के अतिरिक्त किसी अन्य ऊर्जा उत्पादन स्रोत के ठीक से विकास न करने के कारण आज हमारे देश में जहाँ दुनिया के 15 प्रतिशत आबादी रहती है को दुनिया के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत मिल पाता है वहीं अमेरिका और रूस जिनकी सम्मिलित आबादी दुनिया की कुल आबादी का 7 प्रतिशत है का विद्युत उत्पादन एवं उपभोग पूरी दुनिया के 50 प्रतिशत के बराबर है। इसके साथ ही पेट्रो पदार्थों के समाप्त होने का खतरा भी सामने आ रहा है। जिससे निबटने के लिये यह आवश्यक है कि हम इसका कुछ विकल्प ढूँढें। उपलब्ध विकल्पों में एक प्रमुख विकल्प है फास्ट ब्रीडर रियेक्टरों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त आधारभूत संगरचना तथा अयस्क भी मौजूद है।

इसके अतिरिक्त नाभिकीय संलयन द्वारा विद्युत उत्पादन का भी प्रयास होना चाहिए। ब्रह्माण्ड में सर्वाधिक उपलब्ध तत्व हाइड्रोजन है जिसके अणुओं के संलयन की प्रक्रिया के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी संलयन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न तारो में ऊर्जा उपलब्ध रहती है। सूर्य पर एक ग्राम हाइड्रोजन से 62 खरब जूल ऊर्जा विमुक्त होती है जबकि 1 ग्राम कोयले को जलाने से 33 किलो जूल ऊर्जा मिलती है।

इस प्रकार वर्त्तमान ऊर्जा समस्या से निबटने में नाभिकीय ऊर्जा बेहद लाभदायक एवं सस्ती साबित हो सकती है। ■

मेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंध उठाये

अमेरिकी ने भारत और
स्तान पर 1998 के मई के
णु परीक्षणों के बाद लगे
क एवं सैन्य प्रतिबंधों को पूरी
से हटाने की घोषणा की है।
ी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति
ड्ब्ल्यू बुश ने 23 सितम्बर
रात को की। यह घोषणा
े हुये राष्ट्रपति बुश ने कहा
ये प्रतिबंध अमेरिका के राष्ट्रीय
ा हितों के अनुकूल नहीं है।
त ने प्रतिबंध हटाने की इस
णा को 'प्रत्याशित कार्यवाही'
ाया। पाकिस्तान ने भी इन
तिबंधों को हटाने की घोषणा का
ागत किया है। लेकिन अमेरिकी
देश मंत्री कोलिन पॉवेल ने कहा
क केवल परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंध हटे हैं।

इन प्रतिबंधों के हटने का सबसे बड़ा लाभ अमेरिकी उद्यमियों को मिलेगा क्योंकि वे अब बिना किसी रोक–टोक के भारत को अपने उत्पाद निर्यात कर सकेंगे।

भारत पर से ये प्रतिबंध हटने के बाद भारत के सैन्य कार्यक्रमों विशेषकर हल्के लड़ाकू विमान परियोजना और भारत के आयात तेजी आने की संभावना है। भारत पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में से अधिकतर तो क्लिंटन प्रशासन ने ही अपने व्यावसायियों एवं अनुसंधान संस्थाओं के दबाव में उठा लिये थे। बाकी बचे–खुचे प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण दोहरे प्रयोग वाले उपकरणों की भारत को बिक्री। इस पर से भी प्रतिबंध उठा लिया गया है।

इन प्रतिबंधों के हटने का सबसे बड़ा लाभ अमेरिकी उद्यमियों को मिलेगा क्योंकि वे अब बिना किसी रोक–टोक के भारत को अपने उत्पाद निर्यात कर सकेंगे। भारतीय उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर इसका कोई घनात्मक प्रभाव नहीं होगा।

इसको स्वीकारते हुये वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा "इन प्रतिबंधों को हटाने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं होगा।" ■

Scanned with OKEN Scanner

भूख का भूगोल

■ नरेश सिरोही

आज विश्व के हर कोने से भूख–गरीबी और दरिद्रता से जूझ रहे लोगों के प्रति चिंता व्यक्त की जा रही है। भूख और गरीबी से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। खाली सुझाव ही नहीं दिए जा रहे अपितु कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ गरीब देशों को गरीबी से निपटने के लिए कर्ज भी दे रही हैं। हमारे देश में भी भूखे, गरीबों और दरिद्रों की भरमार है – जिधर देखो दरिद्र ही दरिद्र। अपने देश के भाग्यविधाता यानी नौकरशाह जिनके कुत्ते दूध, केले और काजू खाकर बड़े होते हैं, वे भूखों की चिंता करते हैं और विभिन्न योजनाएँ बनाकर गरीबी और भूख को देश से मिटाना चाहते हैं। वे गरीब गर्भवती महिलाओं को आयरन की मुफ्त गोलियाँ बाँटकर, गरीब बच्चों को गाँव–गाँव में दलिया बाँटकर, बूढ़ों को अक्षर ज्ञान कराके, गाँव में कच्चे घरों में रहने वालों को आवासीय योजना के तहत एक पक्का कमरा बनवाकर, गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ऐसी सभी योजनाओं की सच्चाई गाँव–देहात जहाँ ये योजनाएँ लागू होती हैं वहाँ का बच्चा–बच्चा जानता है। आंगनवाड़ी में बँटने वाले दलिए को बाँटने वालों के ढोर खाते हैं। महिलाओं को बाँटने वाली आयरन की गोलियाँ कागज के

.....फिर भले ही जंगलों से बटोरे कंदमूल हो या आम की गुठली का चूरा, जिसे खाकर उड़ीसा में काशीपुर के लोग मरते रहे और इधर सरकारी गोदामों में जगह न होने के कारण अनाज सड़ता रहा। इनके विकास के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए थे, वे कहाँ गए।

पेट में चली जाती हैं, प्रौढ़ शिक्षा के स्लेट बत्ती तथा पढ़ाने वालों के पगार कागजों में पूरी हो जाती है गरीब के पक्के मकान का सपा डी.ओ. साहब की सेवा के बिना पू होना असंभव है। सब जानते हैं कि कितने रुपए किलो दलिया और सर्म अफसरों का कमीशन व सप्लायर के लाभ जोड़कर कितने रुपए किलो सप्लाई होती है। स्लेट–बत्ती, ब्लैक बोर्ड चाक आदि सामग्री का फर्ज बिल 25 प्रतिशत पर बाजार में ह स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध है ये तो मात्र अपने देश में चल रह विभिन्न क्षेत्रों की चंद योजनाओं की बानगी है। जबकि ऐसी अनगिनत योजनाएँ हैं जो जिनके लिए बनती है, उन तक पहुँचती ही नहीं और बीच में ही गायब हो जाती हैं। क्या ऐसी योजनाओं के बल पर भूख, गरीबी और दरिद्रता से निजात पायी जा सकती है? क्या भीख का दलिया खाने वाले बच्चे स्वावलम्बी भारत का निर्माण कर सकते हैं? क्या बेरोजगार नवयुवक की गर्भवती पत्नी मुफ्त की दवाई गोली और भीख का अन्न

Scanned with OKEN Scanner

र भारत के भविष्य को जन्म दे
ती है?
सरकारें आती और जाती हैं,
न विकास योजनाओं का अंजाम
ा त्यों ही बना रहता है। योजना
े वालों की इन योजनाओं के
की योजना को शायद देश की
-भाली जनता नहीं जानती। भूख,
के लिए अभिशाप है लेकिन इन
ाकारों तथा इनकी बिरादरी के
े स्तर के प्यादों के लिए वरदान।
तो इनके कुत्ते दूध, केले और
पर पलकर बड़े होते हैं।
भूख शरीर का स्वाभाविक धर्म
उसकी पूर्ति तो कहीं न कहीं से,
ी न किसी तरह होती ही रहती
फिर भले ही जंगलों से बटोरे
ूल हो या आम की गुठली का
जिसे खाकर उड़ीसा में काशीपुर
ोग मरते रहे और इधर सरकारी
ामों में जगह न होने के कारण
ज सड़ता रहा। इनके विकास के
60 करोड़ रुपए दिए गए थे, वे
गए। भुखमरी की खबरों के बाद
वहाँ जाकर देखा तो चालीस घरों
न्न का एक दाना भी नहीं था।
के लोग मरे, बस उन्हें कुछ चावल
पैसा सरकारी प्यादे दे गए थे
ी को नहीं दिया। शायद उनके
ने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें
ा किसने? लालच की भूख ने।
केन धन–संपदा की भूख ऐसी है,
ी कभी शांत नहीं होती। इसका
ई अन्त नहीं। एक बार लालच का
न मुँह से लग जाए तो आदमी
खार हो जाता है और मानवीय मूल्यों
ो भुलाकर हिंसक पशु की तरह
मदा बटोरने में लग जाता है –
र भले ही हत्याएँ हों, भुखमरी हो,
ूखा हो या बाढ़! उसे तो बस अपना
े भरना है। कितना ही मिल जाए,
फिर भी और की रट लगी रहती है। इसके बाद भी क्या वह व्यक्ति जीवनपर्यन्त चैन से रह सकता है।

अकूत धन–सम्पत्ति–वैभव प्राप्त करके भी वह दरिद्र ही बना रहता है। आज अपने समाज में चहुँ ओर ऐसे दरिद्रों की भरमार है। लेकिन विडम्बना यह है कि आज हम केवल धनाभाव को ही गरीबी या दरिद्रता का पैमाना मान बैठे हैं। वास्तव में दरिद्रता कई प्रकार की होती है जैसे मानसिक दरिद्रता, नैतिक दरिद्रता, राजनीतिक दरिद्रता, अज्ञानजन्य दरिद्रता, भौतिक दरिद्रता और आध्यात्मिक दरिद्रता।

भौतिकवाद का भंवर जाल

भौतिकवाद एवं बाजारवाद के भंवर जाल में फँसे तथाकथित सभ्य समाज को सच्चाई को पहचानने के लिए अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए – आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या वे मानसिकता से, नैतिकता से, राजनैतिकता से, सामाजिकता से आध्यात्मकिता से पूर्ण हैं। अपने अतीत को भुला कर कोई समाज व राष्ट्र प्रगतिपथ पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ दूर चलकर भ्रमित हो जाता है, भटक जाता हैं। आज वही स्थिति हमारी भी है। गाँव के पढ़े न सही लेकिन गुने हुए बुर्जर्गों को अक्षत ज्ञान कराकर क्या सिखाना चाहते हैं। मैं किसी के पढ़ाने का विरोधी नहीं हूँ। यह अच्छी बात है कि पिछले दो तीन वर्ष में ही तीन करोड़ लोग साक्षर हो गए और आजादी के समय की 18 प्रतिशत साक्षरता आज 60 प्रतिशत का आंकड़ा हो गया। लेकिन साक्षरता भी भीख में क्यों दी जाए। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन भीख से नहीं। हमारे समाज में स्कूल का मुँह न देखने वाले कबीर और रैदास जैसे आदर्श मौजूद हैं। लोग अपना पक्का मकान बनाएँ लेकिन अपनी कमाई से, भीख से नहीं। देश का बच्चा–बच्चा अच्छे से अच्छा भोजन करें, लेकिन अपने माँ–बाप की कमाई से, न कि भीख से। भीख से पलने वाला समाज व राष्ट्र कभी स्वावलम्बी नहीं बन सकता। बिना स्वावलम्बन के स्वाभिमान का बोध नहीं हो सकता। बिना स्वाभिमान के आत्मसम्मान व आत्मगौरव तथा आत्मज्ञान के बोध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी, आत्मज्ञानी तथा आत्मगौरव से परिपूर्ण व्यक्ति ही आत्मकल्याण और समाज में उच्च आदर्श स्थापित करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकता है। आजादी के बाद के पचास वर्षों में गरीबी हटाने के नाम पर हमने सबको भिखारी बना दिया। हर कोई सरकारी सहायता की बाट जोहता है। सरकार आए और हमें पढ़ाए, सरकार आए और हमारे घर बनाए, सरकार आए और हमें पानी पिलाए सरकार आए हमें गुण्डों और लुटेरो से बचाए, सरकार आए और हमारे मुँह में दाने डाले और हमारी झोली में बूढ़ों और विधवाओं की पेंशन टपकाए। इतनी पराधीनता तो शायद गुलामी के दिनों में भी नहीं थी।

पवित्र परंपरा

अब तनिक अतीत में चलें। हमारे पुरखों ने एक मुठ्ठी अनाज तथा जंगली फलों से अपनी भूख को शांत किया था। भौतिकता के नाम पर घासफूस की कुटिया में रहकर मानवीय चेतना के विकास अर्थात् सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवीय आदर्शों को उच्चता

Scanned with OKEN Scanner

प्रदान की थी। हमारे ऋषि मुनि सभी अपार ज्ञान और आंतरिक शक्ति की सम्पदा के स्वामी थे। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान व्यक्ति महलों में जन्म लेने और राजसी ठाठ–बाट के बीच रहकर पलने–बढ़ने के बावजूद इन्हीं के चरणों में बैठकर घासफूस की कुटिया में रहकर रूखा–सूखा खाकर बनवास और साधना का जीवन बिताते हुए ज्ञानार्जन कर उनकी सेवा अपना धर्म मानते थे। राम ने भीलनी के बेर खाए, कृष्ण विदुर के घर केले के छिलके और द्रौपदी की बटलोई में बचे चावल खाकर तृप्त हुए। महाराणा प्रताप घास की रोटियाँ खाकर बड़े हुए। क्या उनके जीवन को गरीबी या दरिद्रता का जीवन कह सकते हैं। ऐसे महापुरुषों की शिक्षा के ही कारण राजा हरिशचन्द्र जैसा व्यक्ति नितान्त दरिद्रता की स्थिति में भी अपने आचरण की उच्चता बनाए रखता है और अपने ही पुत्र के मृत शरीर को बिना कर दिए संस्कार करने की अनुमति नहीं देता। गुरुनानक देव राजा के भोजन का त्यागकर एक गरीब बढ़ई के घर की सूखी रोटी खाकर अन्न की पवित्रता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाने वाला चाणक्य जंगल में कुटिया में रहता था और सरकारी काम सरकार के पैसे से खरीद गए तेल के दिए में जलाकर करता था और अपना निजी कार्य अपनी पगार के पैसो से खरीदे गए तेल का दिया जल कर। अपने देश में उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का लम्बा इतिहास रहा है। इस इतिहास की रक्षा और इस परंपरा को जीवित रखने का काम मुगलों और अंग्रेजों से युद्ध करते, जुल्म सहते हुए गाँव, देहात, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने भूखे

काज के बदले अनाज योजना जहाँ नहीं चल पाती उसमें भूख और गरीबी से जुड़ी एक और समस्या का हाथ है। यह है बीमारी। भूखा आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि वह मामूली संक्रमण के सामने भी घुटने टेक देता है।

पेट रहकर भी किया था और आज भी कर रहे हैं। 'सर और 'रायबहादुर' की उपाधि के लिए अंग्रेजों की जीहजूरी करने वालों ने अपनी संस्कृति तथा मूल्यों की चिंता न तब की थी न ही उनकी संतानें आज कर रही है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गरीब की भूख मिटाने की योजना बनाने का काम इन्हीं के जिम्मे है।

एक बार अवध में अकाल पड़ा चारों तरफ भूख और गरीबी फैल गई और लोगों में हाहाकार मच गया तथा लोग बेरोजगार हो गए। तब अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने लोगों को रोजगार देने के लिए इमामबड़े का निर्माण कराया। दिन में लोग इमामबाड़े की चिनाई करते थे और रात में नवाब के लोग चुपके से उसको थोड़ा ढहा देते थे, ताकि लोगों को लम्बे समय तक रोजगार मिलता रहे। चाहते तो नवाब सरकारी खजाने से पैसा व अनाज मुफ्त में बँटवा सकते थे। मुफ्त में मिले पैसे व अनाज से लोगों की भूख तो मिट जाती, लेकिन उनका आत्मसम्मान व स्वाभिमान कुचला जाता। नवाब की योजना से गरीब का पेट भी भरा और आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी बचा। वरना अवध भी भिखारियों का देश बन कर रह जाता। इस तरह के अनेक उदाहरण अपने इतिहास में मिल जाएंगे। उनसे सीख लेकर आज भी ऐसी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। काज के लिए अनाज और अन्नपूर्णा जैसी योजनाएँ बनती हैं लेकिन बस बनकर रह जाती हैं। क्योंकि जिन योजनकारों के कुत्ते दूध, केले और काजू खाकर पलते हैं, वे पहले अपने कुत्तों की चिंता करें या भूख से मरने वाले गरीबों की।

काज के बदले अनाज योजना जहाँ नहीं चल पाती उसमें भूख और गरीबी से जुड़ी एक और समस्या का हाथ है। यह है बीमारी। भूखा आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि वह मामूली संक्रमण के सामने भी घुटने टेक देता है। फिर उसमें इतनी ताकत कहाँ से बचती है कि वह काम करने लगे। तालाब खोदे, पंचायत घर की चिनाई कराये, सड़क बनाए। वह तो कुछ ऐसे काम कर सकता है जो घर में बैठे ढाले हो जाएँ। रस्सी बुनना, कारगरी, दस्तकारी, बढ़ईगिरी वगैरह। वहीं कच्चा माल दे जाओ और तैयार माल के पैसे देकर उसे स्वावलम्बी बनाओ। तभी वह भूख, गरीबी और रोग इन तीनों के दुष्चक्र से उबारा जा सकेगा। यह काम भी सरकार पर न छोड़कर स्वयंसेवी संस्थाएँ करें। बेरोजगार नौजवानों को इसमें लगाएँ और उन्हें पगार देने की व्यवस्था मंदिरों और आश्रमों तथा समाजसेवी ट्रस्टों वगैरह को करनी चाहिए। तभी हम सन् 2007 में स्वतंत्रता की साठवीं वर्षगांठ तक भारत को भूख से मुक्त करने का स्वप्न साकार कर सकते हैं।

आज देश और समाज सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर पेट की भूख तो मिटा सकता है लेकिन बड़ा प्रश्न तो यह है कि नैतिक मानसिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से दरिद्रों की भूख मिटाने की योजना कौन बनाए?

Scanned with OKEN Scanner

ब विदेशी रोग पाना आसान, मात्रात्मक तबन्ध बाधक नहीं

आर.सी. गुप्ता

र्तमान में जीवन–यापन की गति में जितनी तीव्रता आई है, उतनी ही तीव्रता से लोगों षधि–प्रयोग को अपने दैनिक में बढ़ाया है, यही कारण है कि ल और वायु की भांति औषधि भी उनके जीवन–यापन की र्यता बनती जा रही है। कुछ ो आज ऐसी अवस्था में पहुँच कि वे औषधि के बिना जी ही कते हैं। यह विवशता या बुराई सी पाश्चात्य संस्कृति और की देन है जिससे अन्य ों को भारतीय जन–जीवन में दिया है। पाश्चात्य देशों में थित सुसंस्कृत और सभ्य समाज थति यह है कि बिना औषधि के उन लोगों का खाना हजम होता र न ही नींद की गोली लिए बिना रात को नींद आती है। सुख की तो बड़ी बात है अपना पेट साफ या निर्बाध शौच के लिए भी मित रूप से 'टेबलेट्स' लेना की विवशता है। रक्तचाप, मधुमेह शरीर की अन्य वैकारिक स्थिति बचने के लिए वे नियमित रूप से त्र प्रकार की गोलियों या अन्य औषधियों का आश्रय लेते रहते हैं। इन औषधियों के कुप्रभाव से बचने के लिए और औषधियाँ लेनी पड़ती है। आज यह सब पाश्चात्य संस्कृति की नियति बन गई है और उसी नियति ने भारतीय जन–जीवन में प्रवेश कर लोगों को तथाकथित 'सुसंस्कृत' और 'सभ्य' बनाना प्रारंभ कर दिया है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जन–जीवन उस ओर उन्मुख हो गया है, जिसे ओर कृत्रिमता जीवन संवारती है और प्रकृति से उसका नाता टूटता जाता है।

विगत लगभग चार–पाँच दशाब्दि पूर्व के भारतीय जन–जीवन, उनके रहन–सहन, आहार–विहार आदि की ओर यदि दृष्टिपात किया जाए तो लगता है कि हम प्रकृति के अधिक निकट थे, प्रकृति की सुरम्य गोद में हमारा जीवन–यापन होता था, प्राकृतिक परिवेश में अनुस्यूत हमारा आहार–विहार था और वही हमारी स्वास्थ्य–रक्षा का सुदृढ़ आधार था। बिना औषधि–सेवन के हम स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। औषधि का प्रयोग केवल बीमार होने की स्थिति में ही आवश्यक होता था, किंतु धीरे–धीरे

कुछ लोग तो आज ऐसी अवस्था में पहुँच गए हैं कि वे औषधि के बिना जी ही नहीं सकते हैं। यह विवशता या बुराई भी उसी पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की देन है जिससे अन्य बुराइयों को भारतीय जन–जीवन में घोल दिया है।

स्थिति में बदलाव आया और अब तो स्थिति बिलकुल ही बदल गई है।

आजादी के पहले मधुमेह या डायबिटीज कुछ ही लोगों को ही होती थी और शायद 0.5 प्रतिशत से कम ही थी और प्रायः उन लोगों को ही होती थी जो शारीरिक काम नहीं करते थे और भोजन करते थे गरिष्ठ से गरिष्ठ। पर अब यह रोग सभी वर्गों में तेजी से बढ़ रहा है और भारत में ही लगभग 2 करोड़ व्यक्ति मधुमेह से

Scanned with OKEN Scanner

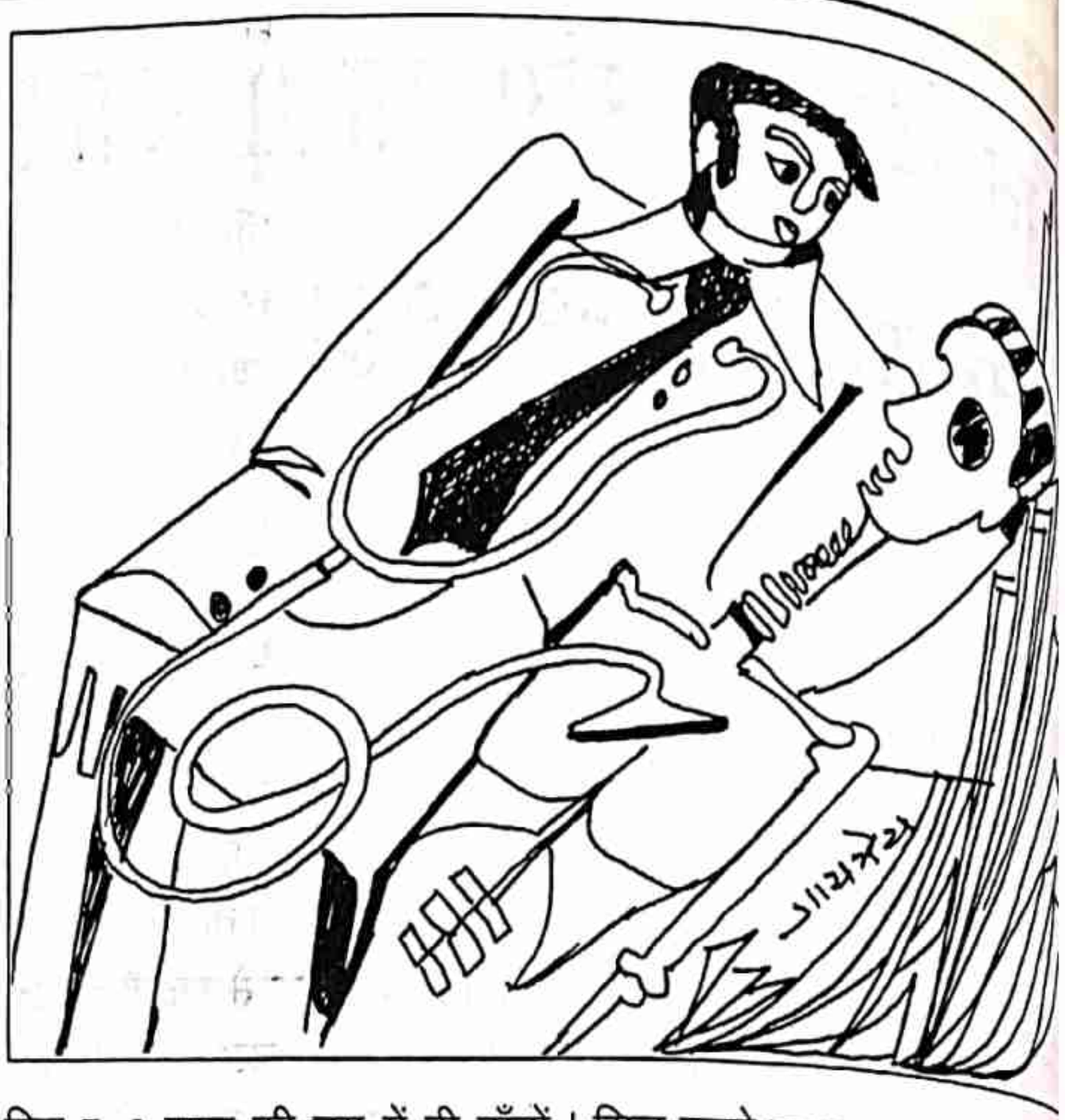

पीड़ित है। कुछ समय पूर्व तक गाँवों में कब्ज की शिकायत करने वालों को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा जाता था पर अब क्या है? इसी तरह हम बहुत सी बीमारियाँ स्वयं मोल ले रहे हैं, मधुमेह ही नहीं, उच्च रक्तचाप, नींद की कमी या कैंसर अब गांवों में भी पहुँच गया है और अगर 'सभ्य' और 'सुसंस्कृत' होने का यही मापदंड है तो गाँव वाले भी पीछे क्यों रहना चाहेंगे, रोगी आप हो नहीं रहे हैं – आप रोग खरीद रहे हैं।

कुछ दिनों पूर्व मेरी छह वर्षीय पौत्र मुझे समझा रही थी – बाबा आप भी चाकलेट खाया करिए, दो गिलास दूध के बराबर एक चाकलेट होती है, फिर उसमें विटामिन, कैल्शियम भी होता है। वह वही बात कह रही थी जो वह दिन में पच्चीसों बार टी0बी0 पर सुनती है। मैं उसे कैसे समझाऊँ कि एक चाकलेट, कैल्शियम के हिसाब से 2 गिलास के बराबर और कीमत के हिसाब से 7 गिलास के बराबर है और यदि चाकलेट विटामिन और कैल्शियम दे भी दे, पर प्रोटीन, मिनरल, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व इत्यादि कहाँ से देगी? मैं उसे कैसे समझाऊँ कि एक चाकलेट में सीसा की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे खाने वाले बच्चों की बुद्धि का विकास ही रुक जाता है या फिर 7–8 साल की उम्र में ही दाँतों में खोखलापन आ जाता है और फिर दंत चिकित्सक के पास दौड़ता पड़ता है अमेरिका के 32 प्रतिशत बच्चे (15 साल से कम आयु के) चाकलेट च्यूंइगम इत्यादि मीठी चीजें खाने के साथ अपने दाँत हमेशा के लिए खराब कर बैठे हैं। इसी तरह हमें बताया जा रहा है कि मदिरा या शराब बड़े लाभ की चीज है।

शायद गलत कार्य करने वाले अपने कार्यों को सही साबित करने के लिए एक मुखौटा – मास्क बना लेते हैं जिससे वह गलत बात को सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व मेरे एक अध्यापक थे – काय चिकित्सा के (खाने–पीने के शौकीन पर शायद दूसरों की जेब पर ही, उन्हें मधुमेह था उच्च रक्तचाप भी था, नींद भी कम आती थी, पढ़ाने–लिखने में भी कम रुचि थी (आज तो बिल्कुल ही नहीं है) और रिसर्च के नाम पर तो जो भी कहा जाए – थोड़ा है (भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे) उनके शोध परीक्षण के आकड़े उसी हिसाब से बनते थे, जो वह चाहते थे और उनका एक प्रिय वाक्य था मदिरापान के लिए – हवेन अल्कोहल कैन प्रिजर्व द डेड, वाई नॉट लिविंग अर्थात् जब अल्कोहल से मृत कोशिकाएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं तो जीवित क्यों नहीं। अब उनसे कौन कहें कि अगर जीवित कोशिकाओं को अल्कोहल में डाल दीजिए तो वे मर जायेंगी – पर उन्हें शराब पीने के लिए कोई शगूफा, कारण या मुखौटा चाहिए और उन्होंने बना लिया था। वही बताते रहते थे, अपने मित्रों को

आजादी के पहले मधुमेह या डायबिटीज कुछ ही लोगों को ही होती थी और शायद 0.5 प्रतिशत से कम ही थी और प्रायः उन लोगों को ही होती थी जो शारीरिक काम नहीं करते थे और भोजन करते थे गरिष्ठ से गरिष्ठ। पर अब यह रोग सभी वर्गों में तेजी से बढ़ रहा है और भारत में ही लगभग 2 करोड़ व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। कुछ समय पूर्व तक गाँवों में कब्ज की शिकायत करने वालों को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा जाता था पर अब क्या है?

Scanned with OKEN Scanner

अपने शिष्यों को भी।
अभी कुछ समय पूर्व एक सम्मानीय
रोग चिकित्सक का एक दैनिक
या गया साक्षात्कार छपा था –
कहना था कि "1–2 गिलास
पीने से हृदय रोग कम हो जाते
नका कहना था कि यद्यपि फलों
से भी लाभ पहुँचता है पर शराब
धिक पहुँचता है क्योंकि उसमें
रक्षक तत्व माईक्रोन्यूट्रिएन्ट
न्टीऑक्सीडेन्टस अधिक होते हैं
फिर उन्होंने यह भी समझाया कि
से मानसिक तनाव कम होता
फिर इसी तरह की बात एक
सा पत्रिका में भी कही गई। क्या
नहीं समझ सकते कि यह हमसे
हमारी जनता से कितना बड़ा
गाड़ किया जा रहा है। शराब, वह
भी रूप में क्यों न हो, भारत जैसे
देश जहाँ तापमान 48–50 डिग्री
ो जाता है, के लिए लाभकारी
ो सकती है, हाँ, इतना अवश्य
यह ठंडे देशों जहाँ तापक्रम –5
तक हो जाता है के लिए
गरी है क्योंकि वह शरीर को
तापमान सही रखने में सहायक
है। जो वस्तु अमेरिका, कनाडा
लास्का के लिए लाभप्रद है, वह
के लिए भी होगी? पर बहुराष्ट्रीय
यों को तो अपना सामान बेचना
या मजे की बात है कि जो देश
नागरिकों को साफ, शुद्ध पानी
दे सकता – वहाँ वह अपने
रिकों को 'स्कॉच व्हिस्की'
वाएगा और फिर शायद इन सबके
य ही आयेगी मैड काऊ डिजिज।
खिर यह रोग गायों को कैसे हुए
र फिर मनुष्यों में कैसे पहुँचा?
ंदश्सन नामक बीमारी मुर्गियों में
से आई? और फिर मनुष्यों को कैसे
ुई? आप ही सोचिए! जब हम गाय
जैसे शुद्ध शाकाहारी ही नहीं, घास–फूस, पत्तियाँ चर के खाने वाले जीवों को एक खूँटे से ही बाँध देंगे, उसकी प्राकृतिक और नैसर्गिक क्रियाओं को बिल्कुल सीमित कर देंगे और उसे केवल मिल्क काऊ या बीफ काऊ में बदल देंगे और उसके भोजन में प्राकृतिक पदार्थ न होकर, हारमोन, विटामिन, एण्टीबायटिक और गाय के खून और हड्डी का भोजन होगा तो स्वाभाविक है कि ऐसी गाय की जीवनदायिनी शक्ति तो कम हो ही जाएगी और फिर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उसे रोगी तो बना ही देगा। गाय रोगी हुई तो उसे गाढ़ दिया गया – हजारों गायें केवल इंग्लैण्ड में ही गाढ़ दी गयीं। अभी हाल में 12 लाख मुर्गियाँ भी मार दी गयी। क्योंकि उन्हें भी एवियन फ्लू हो गया था जो मनुष्यों को भी मार सकता था। इंग्लैण्ड और हाँगकाँग में तो यह कर दिया गया या करना पड़ा क्योंकि वहाँ का समाज बहुत जागरूक है, वरना वे आसानी से अपना समस्त रोगा सहित सामान भारत जैसे देशों को भेज देते या फिर भेज रहे हैं और हम भी 'बीफ' से सनी मैक्डोनाल्ड की आलू की फ्रेंच फ्राईज़ खाकर अपने को धन्य समझेंगे इसीके साथ मुफ्त में मिलेगा मैड काऊ डिजिज, इस रोग को समझने वाले चिकित्सक भी हमारे यहाँ नहीं है।

खुशी मनाइये कि अब भारत विदेशों से अनेकों प्रकार के रोगयुक्त भोज्य पदार्थ या 'कचरा' सस्ते दामों पर मँगा सकता है। संभव है कुछ अधिक समझदार लोग भारत की बढ़ती जनसंख्या घटने के लिए इन आयातित पदार्थों को कारगर उपाय के रूप में व्याख्या भी करें।

आइये 'कचरे' खाने की खुशियाँ मनायें। ■

पृष्ठ 22 का शेष...

उदारीकरण में श्रम.....

मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है तथा सामाजिक सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके साथ–साथ श्रमिकों की छंटनी एवं बढ़ती बेरोजगारी भी एक समस्या बनती जा रही है। पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शी नीतियों एवं गलतियों से श्रमिकों की छंटनी हो रही है। महिला श्रम की स्थिति विचित्र बनी हुई है। भूमंडलीकरण के दौर में महिला श्रम हाशिए पर है। अधिकांश घरेलू श्रम महिलाएँ करती है, जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं बनता और इसका कोई लेखा–जोखा नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आय के कुल विभाजन में मजदूरी का हिस्सा भी कम हो जाता है। श्रम के मूल्याँकन में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू श्रम की उपेक्षा से राष्ट्रीय आय में पूंजी की हिस्सेदारी बढ़ती है और श्रम की हिस्सेदारी कम होती है, यानी महिलाओं के श्रम की उपेक्षा पूंजीवाद के हित में होती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण विकसित देशों की सस्ती पूँजी का प्रवाह तो विकासशील देशों की ओर हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों के सस्ते श्रम का विकसित देशों की ओर प्रवाह उत्प्रवास संबंधी अनेक बाधाओं के कारण नहीं हो पा रहा है। अंत में श्रमिकों के बारे में यह कहा जा सकता है कि जब तक समाज व्यवस्था श्रम व पूंजी के बीच का द्वंद्व खत्म नहीं करती और जब तक मनुष्य का जीवन और उसकी सृजनात्मकता समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होती, तब तक वह व्यवस्था किन्हीं भी सार्थक अर्थों में श्रमिकों की स्थिति स्वतंत्र एवं सुदृढ़ नहीं बना सकती। इसलिए सरकार को चाहिए कि श्रमिकों के हितों के लिए कोई कदम उठाने से पहले श्रमिक संगठनों एवं उस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से विचार–विमर्श करे। ■

Scanned with OKEN Scanner

संस्कृति के नाम पेटेंट हुई है हमारी जैव सम्पदा

■ डॉ0 प्रमोद कुमार दूबे

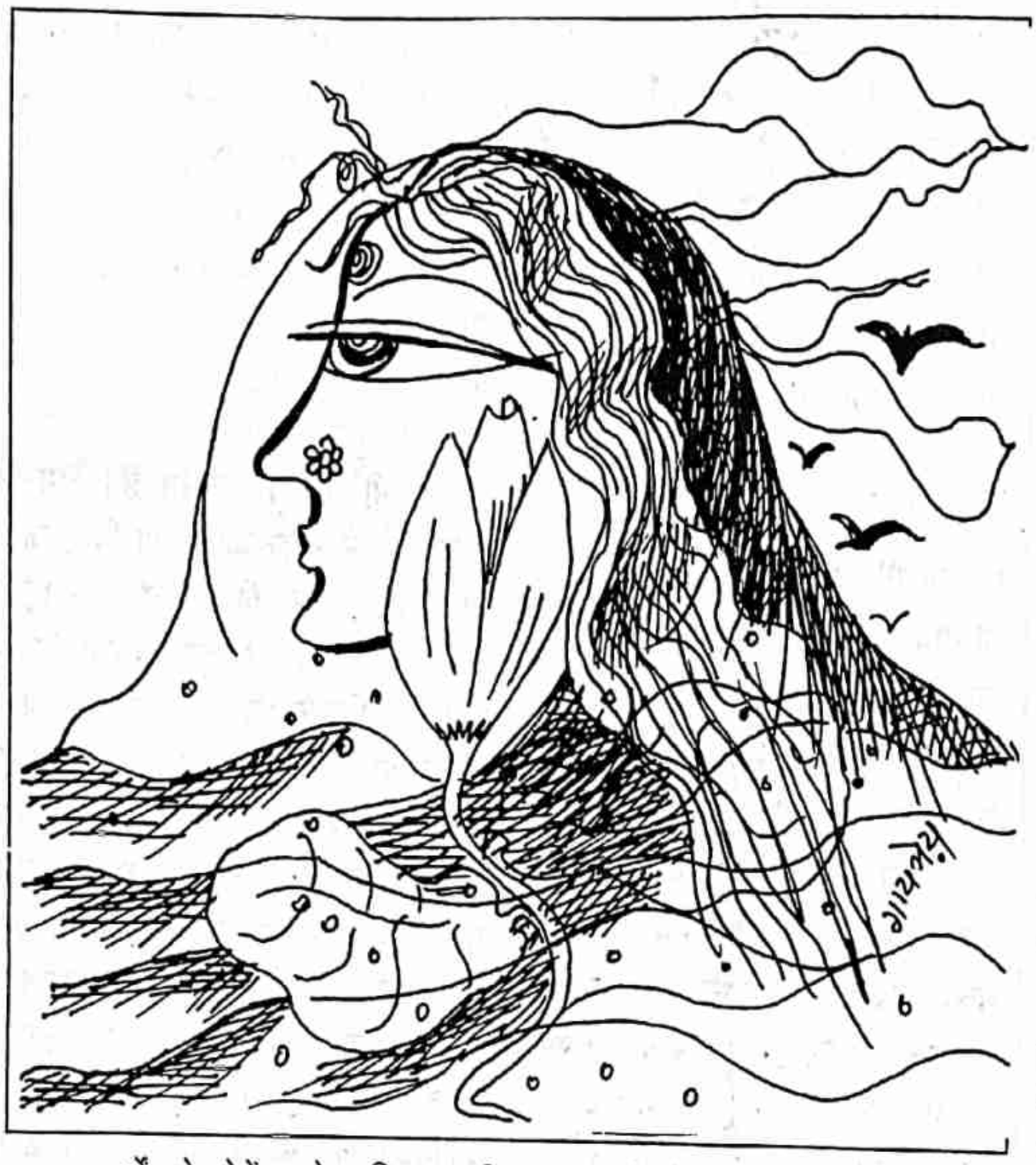

हमारे तत्व द्रष्टा ऋषियों ने अपनी जैव सम्पदा को लोक जीवन के साथ समरस करके सांस्कृतिक अंग के रूप में पेटेंट कर दिया है। राजकीय कानून की छोटी क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली रूप में हमारी धरोहरें सुरक्षित हैं। लेकिन शहरीकरण का दैत्य जिस प्रकार हमारे ग्रामीण जीवन को अपने घड़ियाली जबड़े में दबोचता जा रहा है, कहना कठिन है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित है।

वर्षों से पेटेंट के हथियार की चोट सहते रहने पर अब भारतीय लोगों के मन में अपनी जैव सम्पदा के प्रति जागरुकता आ रही है, कई जुझारू नाम इस बात के लिए यशान्वित हो रहे हैं कि उन्होंने अंततः नीम के विदेशी पेटेंट को खारिज करवा ही लिया, इसी प्रकार हल्दी, आँवला, जामुन, उत्तम किस्म के चावलों इत्यादि के विदेशी पेटेंट को भी लड़कर तोड़वा लेंगे। यह सुखद प्रसंग है। इस युद्ध में सम्मिलित होकर विजयी होना बड़ा रोमांचक और सार्थक लगता है। इससे हमें अपनी सम्पदा की प्रतीति भी होती है। भारत भूमि के ऐश्वर्य की जानकारी से हम गौरव का अनुभव भी करते हैं। इसी तर्ज पर भारत के ऋषियों; तपस्वियों, तत्वोंज्ञों द्वारा हजारों वर्ष के श्रम से अर्जित बौद्धिक सम्पदा के प्रति जब विदेशियों की जिज्ञासा बढ़ी, हमारे देश के लोग भी अपनी सम्पत्ति की प्रतीति में लगे, उन्हें भी लगने लगा कि हमारे पूर्वजों ने आनेवाली पीढ़ी के लिए इतना कुछ रचा–बनाया है। लेकिन एक असंतोष भी जोर शोर से सुनने को मिल रहा है, यह कि हमारे लोगों ने इन अर्जित बौद्धिक सम्पदाओं और प्रकृति–प्रदत्त जैव सम्पदाओं को पेटेंट क्यों नहीं करवाया? मुझे भी अपने अग्रजों की इस भूल से चिंता हुई। पर, संस्कृति की दृष्टि से जब मैं इस समस्या पर विचार करने के लिए विवश हुआ, मेरा भ्रम दूर हो गया कि हमारे अग्रजों से कोई भूल हुई।

हमारे आप्तजनों ने अपनी सम्पदाओं को न केवल अर्जित किया, अपितु उनके महत्व को गहराई से समझते हुए उन्हें श्रेष्ठतम सुरक्षा भी प्रदान की है। यह सुरक्षा व्यवस्था राज्य शक्ति से संरक्षित और पालित होने वाली कानूनी व्यवस्था नहीं है। यह सुरक्षा सभी सम्पदाओं को संस्कृति की प्राणधारा में सुगंधि बनाकर प्रदान की गयी है। राज्य शक्तियों का समायोजन परिवर्त्तनशील है, पर संस्कृति की सत्ता चिरस्थायी है, शाश्वत और सनातन भी। जब भी सृष्टि की शाश्वत, अजर अमर ब्रह्म की सत्ता अपने को प्रकट करती है उसकी अभिव्यक्ति के उपादान होते ही हैं। वे उपादान क्या हैं? ध्वनि, वनस्पति प्राणी, प्रकृति के विविध रूप इन्हीं उपादानों में तो ईश्वर की व्याप्ति होती है। ईश का आवास चराचर जगत ही तो है। यही उस अमूर्त अदृश्य ब्रह्म का प्रकट रूप है जिसमें हमारे

Scanned with OKEN Scanner

ने चैतन्य की व्यप्ति का अनुभव ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचित जगत।

...कवि कलिदास ने माँ पार्वती के ...का वर्णन करते हुए कहा – सृष्टि ...सर्वोत्तम द्रव्यों को संचयन कर ...स्थान विनवेशित करके ब्रह्मा ने ...न से पार्वती का सौंदर्य बनाया –

...मा द्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेश
विनवेशितेन।
...र्मेता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थ
सौंदर्य दिदृक्षयेव।।

...ष्टि के सर्वोत्तम द्रव्यों को एक–एक ...न न लेकर एक ही साथ सबको ... ने पार्वती के महासौंदर्य का ...बना दिया, कितने द्रव्यों के नाम ...ाते, इसके लिए अवकाश कहाँ था। ...ती तो सम्पूर्ण सृष्टि ही हैं – ब्रह्म ...ोचर स्थिति से लेकर व्यक्त स्थूल और व्यवहारिक सृष्टि तक। वही ... त्रिभुवन मोहिनी सर्वत्र हैं – प्राणी, ...े, ध्वनि अथवा प्रकृति रूप में। ब्रह्म ...त रूप पार्वती स्वयं है। यही हमारी ...का स्वरूप भी हैं। जिनके एक–एक अंश से सभी द्रव्य संबंधित हैं। इन्हीं हैं, हममें वह हैं। हल्दी में, नीम में, में, चावल (अक्षत) में, रोली में, दूब ...ा में, दही–दूध–घी, गंगा–जल में, में, सोना में, पर्वत–वन, प्राणी–प्राणी पिंडो में वायु, आकाश, अग्नि में संस्कृति स्वरूपा पार्वती व्याप्त हैं। ...द्रव्य को काटे–छाँटे दूर करेंगे हम। ...मग्र में, समस्तमें अपनी संस्कृति के ...ो देखते हैं। इनके मूलरूप को एक ...दिया जाता है – पंचमहाभूत – क्षिति ...ल – पावक – गगन – समीर। यही ...हाभूत सृष्टि निर्माण के मूल तत्व कहे हैं इनका एकमात्र आश्रय हैं – ...ावन – महाकाल – भूतनाथ – ...देव – शिव। इन्हीं महादेव की अर्द्धांगिनी संस्कृतिरूपा पार्वती। हमारी सारी जैव ...पदा इन्हीं के सौंदर्य के उपादान है।

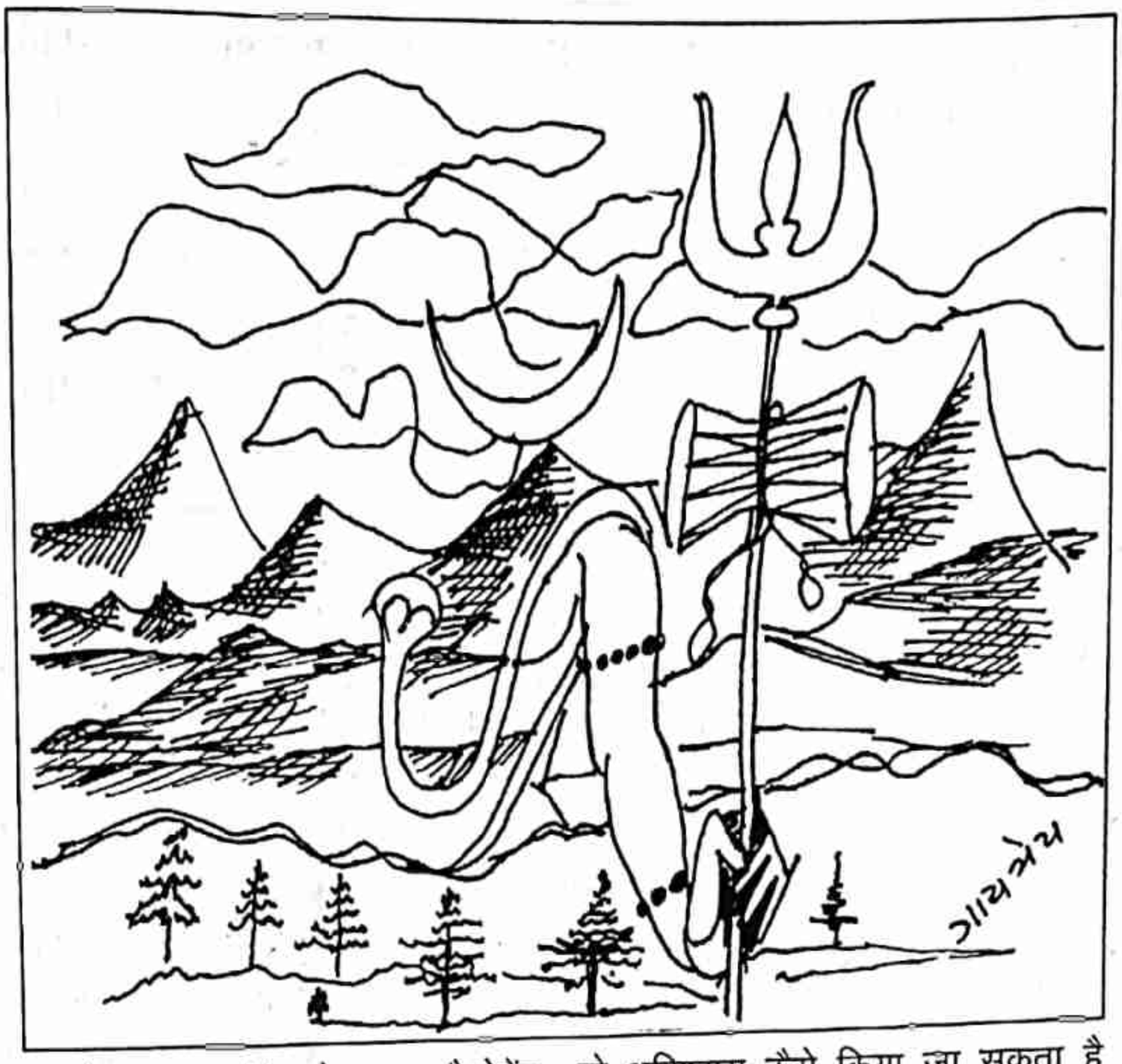

पेटेंट की दुनिया के लोग इस व्याख्या ...सुनकर विचित्र–सा अनुभव करेंगे। ...मारे देश के वैज्ञानिक सोंच–समझ के ...ोग भी खींझ सकते हैं – कहाँ से 'मिथ' ...ढ़ा किया इस लेखक ने? बताइए, इन विषयों का क्या संबंध हो सकता है पेटेंट जैसे वस्तुवादी विषयों से? मैं भी उन्हें यह बताने में कोई रुचि नहीं रखता कि टाइम और स्पेस की तुम्हारी अवधारणा अभी लोकजीवन से दूर कुछ अध्येताओं के लिए है और हमारे महाकाल (टाइम) घर–घर में पूजित हो रहे हैं हमारी सृष्टिरूपा पार्वती (स्पेस) घर–घर की आराधना है। ज्ञान–विज्ञान हमारे लोक जीवन में परायी चीज नहीं, अपितु यह सर्वत्र समरस और सजीव प्रवाह बना हुआ है। इसलिए कि हमने अलग–अलग करके सृष्टि के उपादानों को देखा नहीं, हमने सबको एक ही माता जगदम्बा के सौंदर्य का साधन मानकर पूजा।

इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने सृष्टि के विविध द्रव्यों को ठीक से परखा नहीं, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया, उसकी उपयोगिता को जाना नहीं; इस विषय में महाकवि कालिदास ने क्या कहा है, यहीं न कि विश्व स्रष्टा ने पार्वती माता के सौंदर्य का मंडन करने वाले सभी द्रव्यों की जाँच–परख करके चुनाव किया, उन द्रव्यों के गुण–धर्म के अनुसार उन्हें योग्य स्थान पर रखा। इस बात को बतानेवाले कलिदास विश्वस्रष्टा के इन कार्यों के साक्षी हैं। उन्होंने हम तक यह सूचना पहुँचाई है। कालिदास का वचन है तो अविश्वास कैसे किया जा सकता है भला। हमें इसका कुछ और प्रमाण चाहिए तो आयुर्वेद के ग्रंथों का सहयोग लिया जा सकता है। संभव है, तर्क से पराजित करने में कुशल लोग मुझ कमजोर लेखक को पटकने के लिए प्रश्न उठावें कि क्यों नहीं सीधे आयुर्वेद से लेख का प्रारंभ करके पेटेंट के मामले में अपना पक्ष रखने का प्रयास किया गया? कालिदास के काव्य में वर्णित पार्वती के सौंदर्य के उपादानों की चर्चा की कोई संगति पेटेंट से है क्या, हाथ सिर के पीछे करके नाक छूने की क्या जरूरत? मैं इस प्रश्न का उत्तर यही दूँगा कि आयुर्वेद में द्रव्यों के गुण–धर्म के परीक्षण और प्रयोग की चर्चा आई है, पर पेटेंट के लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है तो क्यों? इस बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा के प्रति उदासीनता क्यों दिखाई गई है? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में महाकवि कालिदास के शरण में जाना पड़ा। क्योंकि वहीं से संस्कृति के ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनसे हमारे लोक–जीवन के संस्कारों, विश्वासों, आचार–विचारों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे संस्कृतिविद् भारत के समग्र सांस्कृतिक चेतना की व्याख्या के लिए महाकवि कालिदास के काव्य को ही केन्द्र बनाते रहे

Scanned with OKEN Scanner

यदि कोई विदेशी हल्दी को पूरी तरह पा लेना चाहता है, उसकी सभी उपयोगिताओं को लूट लेना चाहता है तो हमें प्रसन्नता होगी। यदि वह हमारी तरह ही हल्दी को औषधि, आहार और मांगल्य तीनों रूपों में लूटे। अर्थात् चोट लगने पर हल्दी को चूना मिलाकर गर्म करें, चोट के स्थान पर छापे, बच्चा पैदा होने पर उसे दूध में मिला कर स्त्री को पिलावे, दाल–सब्जी में मिलाकर खाए, विवाह आदि शुभ कार्य में लग्न देखकर वर–वधू को हल्दी लगाए.....

हैं, उन्होंने यहाँ तक माना है कि भारतीय संस्कृति के विस्तृत आयामों का सर्वोत्तम संचयन और संचयनित सांस्कृतिक तत्वों का यथाप्रदेश विनिवेश कालिदास के काव्य में ही हुआ है। इस गुरु वाक्य को नकारना मेरे लिए कठिन है। इसी विश्वास से मैंने सोंचा कि महाकवि ने राष्ट्र की समग्र सांस्कृतिक चेतना को निर्मित करते हुए नीम, हल्दी, आँवला इत्यादि को सहेजने का काम अवश्य किया होगा। प्राप्त यह हुआ कि उन्होंने सभी श्रेष्ठ द्रव्यों को पार्वती के सौंदर्य को समर्पित कर लोक–आस्था से जोड़ दिया है, उन्हें जीवन–यज्ञ का साधन मान लिया है। यह संरक्षण प्रक्रिया इतना बलशाली है कि इससे राज्य और कानून व्यवस्था कभी जीत नहीं सकती।

वस्तुतः प्रकृति–प्रदत्त जैव संपदाएँ केवल उच्चकोटि के साहित्यों से ही नहीं संरक्षित हुई हैं इनसे केवल विद्वत–बोध में इनकी रसमय स्मृति परावर्तित होती रही है और वहाँ से वह स्मृति जनमानस तक जाती है। अन्य महत्वपूर्ण सबल स्रोत भी हैं, जिनसे भारत का जन–जीवन अपनी बौद्धिक एवं जैव सम्पदाओं को सिर्फ पहचानता ही नहीं है, उसके साथ जीता भी है। ये सम्पदाएँ उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की दृष्टि से जैव पदार्थों – हल्दी, नीम इत्यादि को जनजीवन से जोड़ रखा है। पर भारतीय चिकित्सा पद्धति पर अँग्रेजी (एलोपैथी) चिकित्सा पद्धति की कब्जावारी के बाद हमारी लोक–स्मृति से बहुत–से जैव पदार्थों का परिचय धीरे–धीरे गायब हो गया है साथ ही हमें पराधीन बनाने वाले विदेशियों ने जिन शिक्षा पद्धतियों को लागू किया उसके प्रभाव में हमारी अधिकांश शिक्षित हुई पीढ़ियाँ इन जैव–सम्पदा के ज्ञान से वंचित हुई। ये पीढ़ियाँ न घर की हुई, न घाट की, बस अपने समय में टिकी रही, कहीं न कहीं व्याकुलता भी अनुभव करती रही, जिसके कारण आज जागृति आने लगी है। आयुर्वेद से कटने के बाद भी हम अपनी जैव सम्पदा से पूरी तरह दूर नहीं हो पाए, तो इसलिए कि यह सम्पदा हमारे दैनिक आहार–व्यवहार और संस्कार के भी अंग रही हैं। यह हमारी भाषा–साहित्य के उपदान भी रही हैं। उदाहरण के लिए नीम के वृक्ष पर करेले की लता चढ़ जाने की लोकोक्ति से हम सभी परिचित हैं। अर्थात् करेला की कडुआहट जब नीम की कडुआहट से मिलेगी तो कैसा स्वाद होगा – यह प्रसंग हमारी भाषा के उपादानों में प्रयोग होता है इससे यह प्रतीति बनी रही कि नीम और करेले का स्वाद कडुआ होता है।

जैव सम्पदा की स्मृति में हमारे संस्कार–पद्धति बहुत सहयोगी हुई हैं। पूरे भारतवर्ष में हल्दी मांगलिक द्रव्य के रूप में प्रचलित है। विवाह आदि शुभ–कर्म में हल्दी की एक अपरिहार्य भूमिका है, इसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता। दूल्हा–दुल्हन होने के लिए हल्दी से रंगना–पुतना जरूरी होता है। जब तक हल्दी न चढ़े वैवाहिक लग्न का प्रारंभ नहीं होता। इसी प्रकार अक्षत–रोली का मामला है। अक्षत सभी चावल नहीं होते। केवल उसी चावल को अक्षत कहते हैं जो कहीं से भी टूट हुआ न हो – क्षत नहीं हुआ हो। यही अक्षत शुभ की कामना में प्रयोग होता है। यह हल्दी के साथ रंगा जाता है, दही में तृत्प होता है और तब मंगल भाव और मंत्र से माथे पर लगा दिया जाता है विजय की यह लिपि हमने अपने ललाट से अब तक मिटाई नहीं है। हमारे संस्कारों की परंपरा ने हमें सनातन होने की शक्ति दी है। हम इन्हीं आँखों से अपनी जैव सम्पदा

पहचानते रहे हैं।

संस्कृत साहित्य में कालद्रष्टा ऋ
या तत्वज्ञानी के लिए एक वाक्य का
प्रयोग होता है कि वह तीनों काल
हथेली पर रख आँवले की भाँति देखे
'हस्तामलक' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त
है। इसका अर्थ है हाथ पर रखा आँव
आँवला को हमारे पूर्वजों ने सामान्य
नहीं रहने दिया। अक्षय नवमी के
आँवले के नीचे भोजन बनाने और
सामूहिक रूप में जीमने का सुख क्या
है यह तो वही जानेगा जो इस पारंप
सांस्कृतिक अनुष्ठान में सम्मिलित
हो। इन दिनों जब पारंपरिक धरोहरों
प्रति तेज गति से जागरुकता बढ़ रही
कुछ लोग जैव–संपदाओं के अभिप्राय
व्याख्या प्रतीक की भांति करने लगे
लेकिन यह कार्य कई संदर्भों में ह
पहचान को एकांगी भी करता है। ये
प्रतीक नहीं हैं, इनमें हमारे जीवन
समग्रता है। आँवला, पीपल, वटवृक्ष इत्य
हमारी तरह सजीव अस्तित्व हैं, हम उन
अवलम्बित है वे हम पर अवलम्बित हैं,
आपस में परस्परावलम्बी है। हम एक–दू
से अविभाज्य हैं।

आकाशीय ग्रह पिण्डों की गति
रश्मियों का आकलन करने वा
ज्योतिष–निर्णित तिथियाँ – वार – न
– लग्न – मुहुर्त के साथ पर्व–व्रत
आयोजनों द्वारा हमारे जनजीवन
विस्तृत खगोल से जोड़ देती हैं। इ
आयोजनों में भौगोलिक संसाधन भी अव
के अनुसार सम्मिलित होते रहते हैं। क
कुशा महत्व पाती है कभी दूब, कभी हल्
कभी चंदन, कभी अक्षत–रोली, कभी नी
कभी पीपल इत्यादि। गाय, बैल, कुत्
हाथी, घोड़ा, गधा, सियार, सर्प स
पशु–पक्षी हमारे जीवन–यज्ञ के सहभा
होते हैं। हम किसी से अलग कोई शासक
या शोषक अस्तित्व नहीं है। इन सभ
प्राणियों, वनस्पतियों के साथ एकात्मभा
के जीव–जगत की कल्पना पश्चिम
आधुनिक जीवन के पास नहीं है और
महानगरों के वर्त्तमान विकासित ढाँचे म
इस समग्र जीवन के लिए कोई स्थान है।
महानगरों में उपजी हुई विकलांग मानसिकता
बहुमंजिली इमारतों के बंद कमरों में तैयार

Scanned with OKEN Scanner

निसठ, सूखी, निचुड़ी हुई। इसे
आएगा कि बरसात की घनी
त में जब बादल छाए होते हैं,
आवाज चारों दिशाओं में गूँजती
तब किसी कुत्ते का भौंकना
ोत्पादक लगता है, इस अनुभव
ह समझ में नहीं आएगा कि कुत्ता
ों कहा जाता है। विदेशी
यों को गोद में उठाकर उनकी
ते शहरी लोगों को मैंने देखा है।
लोग अपने को बड़ा विकसित
हों अपने पिल्ले को समुद्र मंथन
हुआ रत्न मानते हों, पर मुझे ये
कार्य में लगे हुए, झूठ में फँसे
हैं। इनकी मानसिकता की
ुनावट में स्वदेशी संस्कृति के
नहीं खुल सकते। ये लोग पेटेंट
ही आत्मरक्षा का एकमात्र साधन
दि पेटेंट विरोधी संघर्ष में हम
कृतिक शक्ति का उपयोग करें
और जन जागृति का दोहरा लाभ
भी बासमती चावल के गुणों के
थवा वंशाणु संवर्द्धन से निर्मित
और कालामती अमेरिकी कंपनी
चर्चा में आए थे। अमेरिका के
र कैलिफोर्निया की धरती पर
ये चावल भारत की धरती और
उपजने वाले बासमती चावल
नहीं कर सकते। यह दुनियाभर
ाजार को बताने की आवश्यकता
हीं तो धीरे–धीरे ही सही नकली
के अंतर की समझ उपभोक्ताओं
में आ ही जाती है। सुना जा रहा
से इन नकली चावलों की बिक्री
है, बासमती चावल की बिक्री में
की वृद्धि हो गई है। यदि यही
संगत ढंग से बताई जाए कि
पदार्थ की वास्तविक गुणवत्ता
ल जलवायु और धरती की निजी
होती है, उसकी दैशिकता को
रेत नहीं किया जा सकता। जो
हिमालय में होती हैं वह कहीं
जाई तो जा सकती पर वह
त्ता से अलग हो जाएगी, केवल
पर अधिकार कर लेने से पूरी
नहीं हो सकती। इस विषय में
के मत का भी उपयोग हो सकता है। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जड़ी–बूटियों के लिए कई संदर्भों में यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि अमुक क्षेत्र की जैव सम्पदा ही उपयोगी होगी, उदाहरणार्थ एक औषधि के निर्माण में कामरूप, असम के गन्ने के रस को ही प्रयोग करने का उल्लेख है। इससे यह ज्ञात होता है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ जैव सम्पदा की गुणवता के लिए उत्तरदायी हैं। दैशिक अस्तित्व से दूर करके किसी द्रव्य को उसके वास्तविक रूप में नहीं पाया जा सकता। यह मान्यता वनस्पति शास्त्र से भी पोषित होती है। यदि जलवायु और धरती से किसी जैव सम्पदा का अभिन्न संबंध है तो उसका वास्तविक पेटेंट उस क्षेत्र की जलवायु और धरती के नाम पहले ही प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है कोई इस जिद्द पर आता है कि वह उसे लूट लेगा तो वह अपराधी है। इसके लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात् एक स्थान की जैव सम्पदा का पेटेंट दूसरे स्थान पर होना ही नहीं चाहिए।

जैव संपदा की संरक्षण का संघर्ष बहुत सहजता से जीता जा सकता है, यदि हम अपनी सांस्कृतिक शक्ति को जागृत करें, पूरे विश्व में इसके स्वरूप को विख्यात करें। हमारे धर्म की धारणा को जितनी शास्त्र व्याख्या करते हैं और आचार पद्धतियों में प्रचलित करने की भूमिका निभाते हैं उससे बहुत अधिक जनजीवन अपने लोकाचारों द्वारा धर्म को प्रकृति प्रदत्त साधनों से स्वयं पोषित करता है। हमारा धर्म शास्त्रा–चरण से कहीं अधिक लोकाचरणों से सम्वाहित होता है, शास्त्र तो संकेतक है। लोकाचार ही व्यापक रूप से उसे प्रयोग में लाता है। लोकाचारण के साधन रूप में हमारी जैव सम्पदाएँ उपयोग होती हैं। उनके साथ जनभावना अनेक माध्यमों से संलग्न है। यदि कोई विदेशी हल्दी को पूरी तरह पा लेना चाहता है, उसकी सभी उपयोगिताओं को लूट लेना चाहता है तो हमें प्रसन्नता होगी। यदि वह हमारी तरह ही हल्दी को औषधि, आहार और मांगल्य तीनों रूपों में लूटे। अर्थात् चोट लगने पर हल्दी को चूना मिलाकर गर्म करें, चोट के स्थान पर छापे, बच्चा पैदा होने पर उसे दूध में मिला कर स्त्री को पिलावे, दाल–सब्जी में मिलाकर खाए, विवाह आदि शुभ कार्य में लग्न देखकर वर–वधू को हल्दी लगाए, निमंत्रण–पत्र और लग्न–पत्रिका में हल्दी लगाए, केवल औषधि के रूप में ही क्यों आहार और आचार में भी, साहित्य और संस्कृति में भी, भाषा और व्यवहार में भी भारतीय जीवन पद्धति को स्वीकार करे, तभी वास्तविक रूप में हल्दी का उपभोक्ता हो सकेगा।

पश्चिमी देशों में बढ़ते शाकाहार योग और गीता के ज्ञान से वहाँ के मांस–व्यापारियों में भारी चिंता व्याप्त होने लगती है कि उनके कारोबार में गिरावट आ रही है। चर्च चिंतित होने लगते हैं कि हिन्दुत्व बढ़ रहा है। जीवनदायी जीवन–शैली चाहिए तो हिन्दुत्व की ओर आना होगा। यदि इसे कोई खतरा कहे, तो यह भी सच है कि हमारी जैव सम्पदा और अन्य बौद्धिक सम्पदाएँ कोई फैशन की चीज नहीं है कि कपड़ों की तरह बदली जा सकेगी। ये आचरण से ही सजीव होती है; इन्हें पूरी सजीवता में प्राप्त करने के लिए पूरी जीवनशैली ही बदलनी पड़ सकती है।

हमारे तत्व द्रष्टा ऋषियों ने अपनी जैव सम्पदा को लोक जीवन के साथ समरस करके सांस्कृतिक अंग के रूप में पेटेंट कर दिया है। राजकीय कानून की छोटी क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली रूप में हमारी धरोहरें सुरक्षित हैं। लेकिन शहरीकरण का दैत्य जिस प्रकार हमारे ग्रामीण जीवन को अपने घड़ियाली जबड़े में दबोचता जा रहा है, कहना कठिन है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित है। इस भय को रचने वाले विकास नीति के निर्माताओं से हमें आग्रह करना पड़ेगा कि यदि वे इसी प्रकार सिरफिरापन निभाते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी संस्कृति का व्यवहार पक्ष लुप्त हो चुका होगा। हमारे सारे आत्मगौरव की प्रशस्तियाँ केवल कहने–सुनने की बात रह जाएगी। जैसे अमेरिकी लोग कहते है कि चार सौ संस्कृतियाँ विनष्ट करके आज का अमेरिका खड़ा हुआ है इसका हमें शर्म है – दुःख है, हम भी कहेंगे कि हम स्वयं वह अभागी मछली हैं जो अपने जलाशय का सारा पानी पी चुकी है और छटपटा कर दमतोड़ रही है। ■

Scanned with OKEN Scanner

लेख

दोहरे दुर्दिन की मार खाए

देशी उद्यमियों से स्पर्धा की आशा

■ राधेश्याम सिंह

अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या हमारे देश के सामान्य उद्यमियों को पारंपरिक बाजार मिल पाया? देश के धनी उपभोक्ताओं के लिए जिन क्षेत्रों में उत्पादन होते रहे और उनमें विदेशियों को सफलता नहीं मिल सकती थी, जैसे मुरादाबाद के कशीदेदार बर्तन , बनारसी साड़ियाँ अथवा अन्य कशीदें, रेशमी कपड़े के उद्यम आज भी फल–फूल रहें हैं। इनका लाभकारी निर्यात भी होता है।

देश के छोटे–बड़े उद्योग–धंधों को यह कहकर हतोत्साहित करना अनुचित लगता है कि प्रतिस्पर्धी उत्पादों की भारी मात्रा बाजार में उपलब्ध हो रही है – उनकी विपणन नीतियाँ आक्रमक हैं। इसलिए सरकार उपक्रमों के उत्पादों की भागीदारी घट रही है। दुनिया के प्रतिस्पर्धा में हम टिक नहीं पा रहे हैं, हमारा प्रबंधन ठीक नहीं है, आर्थिक हालत कमजोर है। यदि सचमुच अपनी उत्पादन क्षमता, प्रबंधन और गुणवत्ता उत्तम बनाकर बाजार की भागीदारी बढ़ानी है तो पहला काम यह करना होगा कि विदेशों की तुलना और उनके बाजार में स्थान पाने के प्रयासों से पहले अपने देश और अपने बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की बात करनी होगी।

कुछ छोटे उत्पादन ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारे समाज में हजारों वर्ष से प्रचलित है जैसे बर्तन, लोहे के हथियार, कैंची, छुरी और अन्य उपयोग के पारंपरिक सामानों में हमारी बराबरी करना दूसरों के लिए कठिन होगा। लेकिन हुआ यह कि नए भारत के रहनुमाओं ने काँसे के वासन के स्थान पर अल्यूमिनियम के बर्तन का उत्पादन शुरू किया बिना सोंचे समझे कि धातु की दृष्टि से अल्यूमिनियम का उपयोग भोजन पकाने के लिए करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अल्यूमिनियम जब गर्म होता है उससे अल्यूमिनियम ऑक्साइड नामक जहरीला यौगिक बनता है। धातु के विषय में जानकारी का अभाव होने के बाद भी स्वतंत्र भारत के निर्माता अपनी नादानी को पुराने ज्ञान से श्रेष्ठ समझते रहे। यह भी विचार नहीं किया गया कि बर्तन बनाने के उद्योग में लगे लोग बेरोजगार होंगे। इनका कारोबार गाँवों के बाजारों से लेकर पुराने शहरों तक छाया हुआ है। इसी प्रकार प्लास्टिक के जूते–चप्पल खिलौनों का प्रचलन बढ़ा। इन उद्यमों में लगे हुए लोग बेरोजगार तो हुए ही साथ ही इनके प्रचलन से जन–स्वास्थ्य की हानि भी होने लगी। वस्तुतः स्वतंत्रता के पहले से ही बहुत सी विदेशी कंपनियाँ भारत में जड़ जमाए हुए थी। वह यहाँ के धनी वर्ग के लिए खुशगवार उत्पादन कर रही थी, इनमें हिन्दुस्तान लीवर का उत्पाद और बिक्री की मार से अविकास की दशा में रहे भारतीय उद्यमों एवं उत्पादों की दर्द भरी कहानी जरूर याद रखनी चाहिए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या हमारे देश के सामान्य उद्यमियों को पारंपरिक बाजार मिल पाया? देश के धनी उपभोक्ताओं के लिए जिन क्षेत्रों में उत्पादन होते रहे और उनमें विदेशियों को सफलता नहीं मिल सकती थी, जैसे मुरादाबाद के कशीदेदार बर्तन , बनारसी साड़ियाँ अथवा अन्य कशीदें, रेशमी कपड़े के उद्यम आज भी फल–फूल रहें हैं। इनका लाभकारी निर्यात भी होता है।

नये समय के अनुसार विकसित हुई जीवनशैली के उपयुक्त जितने उत्पादन हो सकते थे, उनको बड़ी–बड़ी कंपनियाँ कब्जा करती चली गई जैसे जैम–जैली, शॉस, बिस्कुट, ब्रेड हमारे उद्यमी बना सकते थे, मॉर्डन फूड की सफलता इसका उदाहरण सबके सामने है। जिस उद्यम को जानबूझ कर बर्बाद कर दिया गया। परंतु इन उत्पादों पर भी स्वतंत्र भारत में विदेशी कंपनियाँ भारी पड़ती रही। इससे नए उपभोक्ताओं तक हमारे मूल्यवान उत्पादन नहीं पहुँचे। साफ शब्दों में कहा जाए तो उत्तम से उत्तम पारंपरिक उत्पादनों को जहाँ हमारी सफलता विश्व को चुनौती देने योग्य होती, उन्हें विकसित होने का अवसर ही नहीं मि जो भी नये अवसर आए उसे बड़ी कंपनियों ऊपर उठा लिया। आज गाँवों के बाजार भी इन घटिया उत्पादन पहुँच जाता है जि पारंपरिक विश्वसनीय उत्पादन मरता गया है। अभी जो काम विश्व व्यापार संग के नियमों के अनुसार हो रहा है, इसी को पहले भारत की बड़ी कंपनियाँ ग्रामीण पारंपरिक उद्यमों के साथ कर चुकी है इनका चरित्र भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ही रहा है। टाटा देशी कंपनी कही जाती लेकिन वह नमक तक बनाती है और फ और कुदाल भी गढ़ती है। कुला मिला स्वतंत्र भारत का तथाकथित औद्योगिक वि की मानसिकता भी विदेशी आर्थि आक्रमणकारियों की तरह रही है। इससे ह पारंपरिक उद्यम दोहरी मार से नीचे धस चली गई है। निर्यात में आई गिरावट मिटाने के लिए देश के वाणिज्य मंत्रालय कुशल सचिवों और विशेषज्ञों का दल रा की निर्यात क्षमता की खोज करना चाहता राज्य अपने नगरों ग्रामीणों बाजारों के उत्पाद की खोज करेंगे। कुछ न कुछ इन्हें अवश्य मि जाएगा जिसकी बराबर विदेशी कंपिनयाँ न कर सकती है फिर भी उपेक्षा के शिकार क्षेत्रीय विशेषता वाले सामानों को जब त उचित प्रश्रय नहीं दिया जाता इनके प्रतिस्प र्ी होने की आशा नहीं की जा सकती। आ लगने पर कुँआ खोदने के क्या मतलब हु कुछ तो निराशा हाथ आएगी ही। अंतरराष्ट्री बाजार की चुनौतियों को स्वीकारने की बा उठाई जा रही है पर क्या इस पर कभी ध्या दिया गया। अब राज्य तक जाकर विशेषज्ञदल करेगा क्या निराशा होकर लौटेगा और यह भ कह सकता है कि राज्यों के पास संतोषजनक उत्पादन है ही नहीं। यदि आटा, दाल, चावल और खाद्य तेल तक हिन्दुस्तान लीवर जैसी कोई कंपनी बेंचना आरंभ कर दे तो छोटे उद्यमियों की कुछ दिनों बाद यादें मिलेगी उद्यमी नहीं।

Scanned with OKEN Scanner

शब्द प्रयोग की मर्यादा

■ रघु शास्त्री

मुख रूप में प्रींट मीडिया की खबरें शब्दों के कंधे पर चढ़कर जनमानस के पास है। शब्दों में अपनी अर्थ सत्ता है जो किसी भाषा की अपनी होती है। मोटे तौर पर कहें तो जातीय स्मृतियों और बौद्धिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों के र योग्यता से बनती है। जब भाषा द्ध-सम्पदा किसी अर्थवान व्यक्ति ों पड़ती है, वह और समृद्ध होती केन जब यह किसी व्यर्थवान के हाथों में पड़ती है इसका नाश है। मतलब यह कि शब्दों की ता को बढ़ा देने वाले लेखक श्रेष्ठ और शब्दों के अर्थ को गिराने ा तोड़-मोड़ देने वाले लोग महत्व ाते। नमूने के लिए घर शब्द के ग पर ध्यान दें। डाकघर चश्मा घर नेक शब्द इसके बावजूद प्रचलित क अंग्रेजी के होम हाऊस बिल्डिंग के साफ-साफ अर्थ प्रयोग करने ग सतर्कता बरतते हुए पाए जातें गलती अंग्रेजी में नहीं दिखती। कवि सच्चिदानंद वात्स्यायन ने को लेकर कविताएँ लिखी घर शब्द ान हुआ। काव्यमय उत्तम परिभाषा ने के बाद घर शब्द की अर्थवत्ता । घर घरनी से होता है घरनी अर्थात् णी ही घर को रचती है अन्यथा बिन ी घर भूत का डेरा होता है। भूत ाँ डेरा डाल देता है वह घर नहीं हो ता। किसी अदृश भूत प्रेत के डेरा लने की बात हो या न हो पर इतना सही कि घर में वर्षों के पुरानी सड़ीगली चीजे कूड़े-कबाड़े पड़े हो तो वह रहने योग्य नहीं हो सकता और तब उस स्थान को घर कहना उचित नहीं होता।

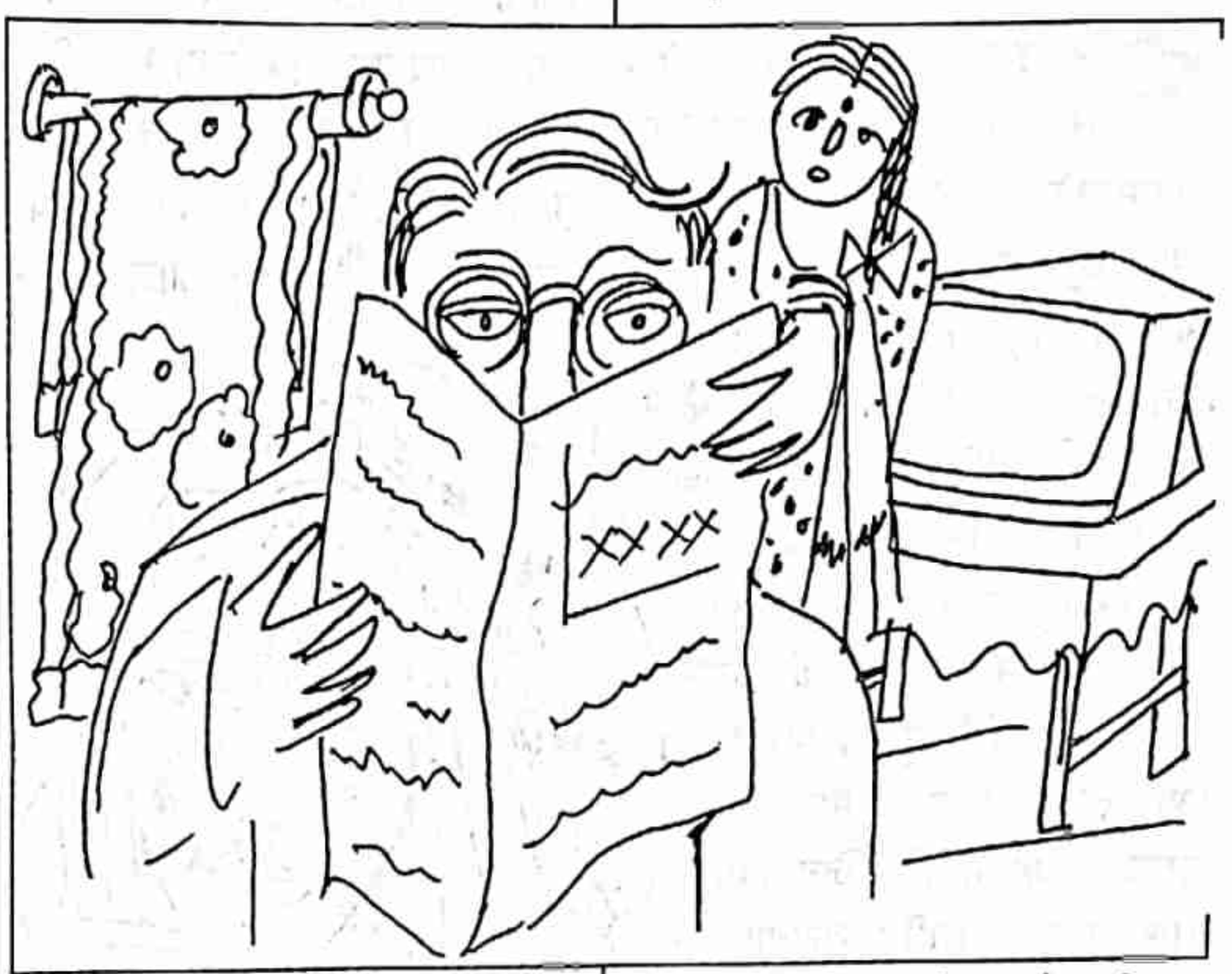

शब्दों को कूड़े-कबाड़ों को दशा तक पहुँचाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की तब संभावना बढ़ जाती है जब चौंकने वाली चटकदार खबरों का बाजार भाव अधिक हो और उत्पादक भी इसके लिए जागरूक। एक जमाना था जब कम्युनिस्टों का असर अधिक था वह बात-बात में कम्युनिस्ट शब्दावली से उस व्यक्ति को पीटते देर नहीं लगाते थे बुर्जुआ - प्रतिक्रियावादी इत्यादि उनके शाब्दिक हथगोले होते थे हालाँकि ये शाब्दिक हथगोले सब जगह प्रचलित नहीं थे कामरेडों के इर्द-गिर्द ही इनका प्रचलन था। इसलिए ये शब्द अजीब लगते थे जैसे एकाएक भारतीय गाँव का कोई व्यक्ति चीनी रेस्तरां में पहुंच गया हों और उसे खाना पकाने वाले कमरे में खड़ा कर दिया गया हो। फासीवादी भी इसी तरह का एक शब्द प्रचलित हुआ। भारतीय जनजीवन और इतिहास के भीतर फासीवाद का जन्म नहीं हुआ न तो इससे लोगों का परिचय हुआ फिर भी इसके प्रहार से आतंक पैदा करने की कोशिशें हुई, श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में फासिस्टों का दमन हो रहा था, अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह स्वतंत्रता की माँग करने वालों को कुत्ते काँग्रेसी ब्राह्मण आदि प्रयोग हुआ करता था। मतलब यह कि किसी को निरस्त करने के लिए शब्दों की गोलाबारी एक स्वाभाविक कार्यक्रम रहा है।

हमलावर शब्द प्रयोग भी हैं और साधारण भी धोखेबाज-मजमेबाज

(पृष्ठ 44 पर शेष)

Scanned with OKEN Scanner

स्त्री का साकारात्मक पक्ष

■ लवलीन

स्त्री की अनेक पक्षघरताओं की लड़ाई विभिन्न विचारों के मोर्चाबंद लोग लड़ रहे हैं। पूरी ईमानदारी से हमारी परंपरा में स्त्री की अस्मिता की खोज और इसके अभ्युदय की लड़ाई अभी भी अपूर्ण है। जिन संस्थाओं की वैचारिक तैयारी परंपरा की धारा के पक्ष में है वे राजनीति से दूर हैं और जिनके लिए स्त्री आंदोलन का हथियार है वे संस्थाएँ जुझारू रूप में सामने आती रही है। इनमें तीन तरह की धाराएँ है एक वामपंथी दूसरी पारंपरिक और तीसरी धारा मध्यममार्गी है। सच्चाई यह है कि जिन विचार धाराओं का भारतीय राजनीति में अस्तित्व रहा है उनके मार्चे भी रहे हैं। अभी आतंकवादी संगठनों का जोर बढ़ रहा है तो युवकों के साथ युवतियों की भी भारी संख्या इनके लिए उपयोग हो रही हैं। सुना जाता है कि नेपाल में माओवादी संगठन के भीतर युवक-युवतियों की तेजगति से भर्ती चल रही है इसका आकर्षण इसलिए भी बढ़ रहा है कि वहाँ सामाजिक वर्जनाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है यह सामाजिक विघटन की विषैली हवा है इससे पीढ़ियों का सर्वनाश होगा किसी प्रकार की सफलता हाथ लगती है तो उसका सुख उन्हें होगा जो लोग संगठन चला रहे हैं। वही सत्ता में रहेंगे, हजारों की संख्या में स्त्रियों (लड़कियों) का उपयोग विघटनकारी और आतंकी संगठन कर रहे हैं। वे लोग भी स्त्री के पक्ष में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पर, यथार्थ क्या हैं; इसका परिचय सामने-सामने होगा। न आज और न

बीते दिनों में कभी स्त्री रीढ़हीन अस्तित्व में रही है, पुरुष के साथ उसका समानान्तर का अस्तित्व हर काल में रहा है। जब पुरुष पराधीन और दास रहा स्त्री भी इस दुर्दिन का शिकार रही। जब पुरुष को सफलता के अवसर मिले स्त्री ने भी सफलता के अवसर पाए हैं। विकृत सामाजिक परिस्थितियों में कन्याओं की जन्म के बाद हत्या, स्त्रियों की लूट, यौन शोषण, क्रय-विक्रय, विकृत सती प्रथा, अनमेल विवाह, बाल-विवाह अनेक स्त्रियों से विवाह के दुखदायी प्रचलन रहे हैं इनके विरुद्ध निरंतर संघर्ष हुए हैं। समाज को विचारवान बनाने वाले लोगों ने इन विकृतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।

एक बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक पुरुष किसी न किसी स्त्री की संतान है जैसे प्रत्येक स्त्री किसी पुरुष पिता की संतान। स्त्री-पुरुष में विभेद की रेखा खींच कर उसे द्वंद्व का विषय बनाया जाना भी एक सामाजिक विकृति को फैलाने के समान है। होना यह चाहिए कि बराबर अवसर और योग्यता को प्राप्त करने की धारणा समाज में हो। और कभी भी जीवन की गाड़ी की इन दोनों पहियों को अलग-अलग तोड़कर रखने वाले प्रयास नहीं किए जाए। चाहे वामपंथी लाख चीखें पर वे स्वभावतः विघटन पर अधिक जोर देते हैं समाज को रचने-सँवारने के प्रयास नहीं करते, उसे चिथड़ा करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं। आज सभी स्त्रियाँ एकजुट होकर दहेज का विरोध कर दें, माँ-बहनें-बहुएँ दहेज के दानव को समाज से निष्कासित कर दें तो पुरुष इस माँग के लिए अडिग नहीं रह सकता देखा यह जाता है बहुओं के विरुद्ध सास और ननदें खड़ी होती हैं। और प्रताड़ना में भी अगली भूमिका निभाती हैं, यह तो सरासर अस्वाभाविक दशा है स्त्रियों को एक-दूसरे का पक्ष लेना चाहिए। वास्तव में हमारे समाज के विवेक को संचालित करने वाला अर्द्धनारीश्वर गुरु सत्ता भूमिका विहीन हो गई है अथवा उसकी शक्ति क्षीण हो गई और दुकान चलाने वाले प्रवचनकारी व्यापारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है इसीलिए हमारी अन्नपूर्णाएँ अपना स्वरूप भूल रही हैं और हमारे शिव स्वयं को पहचानना छोड़ चुकें है अन्यथा विघटन की हहाकार इस तरह नहीं बढ़ती।■

Scanned with OKEN Scanner

करोबार-परिवार

■ त्रिशूल पाणि

छले दिनों मेरी मुलाकात स्वामी इंडिया परिवार के प्रबंध कार्यकर्त्ता स्वामी से हुई उनसे मिलकर मैं आ – ठीक वैसे ही जैसे दुबारा आए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल से मिलकर स्वामी आभूषण हित बहुतेरी जनता को खुशी से टन के अनुपात में बढ़ी थी। आभुषण से मैंने लम्बी बातचीत । मैं उनके विचार जानने के में उनकी एयर सर्विस कंपनी एयर परिवार से पंद्रह दिनों गनचारी रहने का सौभाग्य प्राप्त था। मैंने उनके नौलक्खा विचार अहोभाग्य कि मैं उन्हीं को अपने टे शब्दों में परोसने का साहस हा हूँ।

ामी इण्डिया परिवार के कई के कारोबार चलते हैं इन किस्मों किस्म जन कल्याण का भी है नी दुनिया का भला चाहती है लिए वह हर तरह के काम करना है किसानों के लिए, बेरोजगार वातियों के लिए, रिटायर द्धाओं के लिए, बीमार–मजबूर के लिए देश के नेताओं और यों के लिए, तीर्थ यात्रियों की के लिए, पर्यटकों और फैशन लोगों के लिए, सबसे आगे आतंकवाद से विश्व को मुक्ति कर शांति प्रदान करने के लिए। उद्देश्यों के लिए स्वामी इण्डिया र ने फिल्म, फैशन, अखबार, अन्न–पानी, खरीद–बिक्री, मसाला, नमक, लोहा, कोयला, ा, हास्पिटल, ऊर्जा, शिक्षा आदि में उद्यम लगाने में जुटी है चूँकि कंपनी ये काम विश्व हित में कर रही है, 'वसुधैव कुटुम्बम्' और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार कर रही है इसके लिए उसने अपनी पत्नी, बेटे, बेटी, दामाद–बहु, सगे–संबंधी तक को लगा रखा है कंपनी कंपनी नहीं एक परिवार है, पदाधिकारी पदाधिकारी नहीं कार्यकर्त्ता है। हो सकता है लोगों को अटपटा लगे प्रबंध कार्यकर्त्ता, उपप्रबंध कार्यकर्त्ता जैसे पद नाम सुनकर, कुछ लोग आपति करने का साहस भी कर सकते हैं कि कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकर्त्ता नहीं कहा जा सकता। जैसे राजनेता को व्यवसायी या उद्यमी नहीं कहा जा सकता, इसके बावजूद कि वह फैक्ट्री मालिक होता है, उसका वंश उसकी परिसम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। जनता में छवि और चुनाव लड़ने की हैसियत भी तो परिसंपत्ति होती है जिसका उत्तराधिकारी उसके बेटे–बेटी, बहु–दामाद, विधवा पत्नी या भाई को सरेआम मिलता है, फिल्मी अभिनेता–अभिनेत्री भी अपना उत्तराधिकार छोड़ते हैं राजवंश की तरह। यह वैधानिक क्यों नहीं हो सकता कोई लेखा अधिकारी इस परिसंपत्ति को आकलन करके काला धन बता सकता है? पैसा पकड़ने वाला कोई औजार नए वंशों की छवि और अन्य सामर्थों का मूल्यांकन करके दिखा सकता?

इसी तरह कोई परिवार और कार्यकर्त्ता शब्दों को कंपनी के साथ जोड़ने पर गैर–कानूनी नहीं कह सकता। हुए होंगे कभी देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने वाले

Scanned with OKEN Scanner

कार्यकर्त्ता.....होंगे कोई गृहत्यागी परिव्राजक भारतमाता की भक्ति में जीवन लगाने वाले, परिवार धर्मी भावना के लोग। स्वामी आभूषण का स्वामी इण्डिया परिवार भी अपना सारा कारोबार विश्व कल्याण के लिए नेकटाई लटकाकर कर रहा है।

गुड स्वामी इण्डिया की नमस्कार शैली स्वामी आभूषण ने चलाई थी। उनके परिवार–कारोबार में गुड स्वामी इण्डिया कहकर हाथ मिलाना प्रचलित हुआ। उन्होंने इन कार्यक्रमों को सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया था। उनका कहना था जब तक पेंडुलम की तरह गले में लटकी हिलती नहीं है दिमाग की घड़ी ठीक–ठीक चलती नहीं है जब तक गुड गुड़ागुड की आवाज घड़ी की टिक् टिक् की तरह होता नहीं हैं आदमी की सक्रियता का अंदाजा नहीं मिलता। यह कार्य–संस्कृति के विस्तार के लिए जरूरी है।

परिवार और कार्यकर्त्ता जैसे आत्मिक मूल्यों के शब्द समाज और देश के लिए अपने को बलिदान कर देने के भाव पैदा करते हैं इसका उपयोग कारोबार के विस्तार के लिए होना चाहिए। इसी तरह भक्ति, ध्यान, समाधि, ईश्वर प्रभु प्रार्थना स्तुति, साधना, षोड़सोपचार नैवेध जैसे भावपरक शब्द है इनका प्रयोग भी कारोबार के विस्तार के लिए वैधानिक माना जाना चाहिए। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, विश्वास को छले बिना पैसा नहीं होता। अब रही–विश्वास बनाने के लिए कुछ बलिदानियों, त्यागियों, तपस्वियों की जरूरत तो वह भी विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता के तर्ज पर पूरी कर ली जाएगी। लोग शूली चढेंगे, सिर कटाएँगे, इनके यशोगान लिखे जाएंगे, क्या यह फिल्म और अखबार में केवल दिमागी स्तर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वामी जी अहिंसा का परमधर्म छोड़ना नहीं चाहते।

(पृष्ठ 41 का शेष.....)

शब्द प्रयोग.....

शब्द प्रयोग भी। इनके प्रयोग को देखकर सम्प्रेषण करने वाले व्यक्ति का मिजाज जाना जा सकता है। उसके विचार जाने जा सकते हैं। इन दिनों बड़े पैमाने पर 'भगवा' 'भगवाकरण', 'भगवा छीटें' इत्यादि का प्रयोग हो रहा है। भगवा का विरोध कभी भगवाध्वज के विरोध का ध्यान दिलाता है कभी यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध का स्वाद पैदा करता है। इतिहास के आपतिजनक पाठों को लेकर पिछले दिनों संसद में बड़ी चर्चा हुई। 'भगवाकरण नहीं हो' इसके लिए सहमत नाम के एक संगठन ने बड़े–बड़े सुरमे एकत्र किये, विपक्षी नेताओं ने भी भगवाकरण के विरोध में दम भर शोर किया। अखबारों में भगवाकरण के विरुद्ध कई लेखकों ने कलम घीसे। अब 'भगवा' शब्द लगभग सर्वत्र फैल चुका है जहाँ तक राजनीति और खबर का बाजार का फैलाव है कम से कम वहाँ तक तो यह शब्द पहुँच ही चुका होगा। भगवा के वास्तविक अर्थ और इन रेलों–रेलियों से फैले भगवा के अर्थ की दूरी को माप कर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि अर्थ का अनर्थ हो चुका है। भगवा के मूलार्थ खारिज हो गया है। गाँव का किसान जो इन खबरों के बाजार से दूर खेत की मेड़ पर बैठकर जीवन और कर्म के बारे में विचार करता है आकाश के बादलों को निहारता है हवा और मिट्टी की नमी को अनुभूतता है बैल की भूख–प्यास गाय के रंभास को पढ़ता है उसके मन के 'भगवा' के अर्थ से खबरों के बाजार के 'भगवा' की तुलना कीजिए। राजनीति हुई अखबार बिके किस विपिनचन्द्रा ,और रोमिला थापर की लेखकीय दुकानदारी चली या ठप्प रही इतिहास से कमाने खाने वाले किस व्याख्यानकर्त्ता का व्यापार चौपट हो गया किस का मुगलकाल, किसका ब्रिटिशकाल खारिज हुआ, किसके किले बने, किसके उजड़ गए, इससे क्या शब्दों की अर्थवत्ता बढ़ती है और सच्चे जन–जीवन कल्याण होता है?

शब्दों के प्रयोग की मर्यादा है शोर की ध्वनियाँ भी है चीख–चिल्लाहट उन्हें बम–गोले की तरह उपयोग करने वाले का हाथ को नहीं रोकेगा। पर भगवा को रौंदने वालों के प्रति जनमानस में आपत्ति होगी ही।

संसद बहस के लिए ही होती है सूचना माध्यम विचार के लिए ही होते है तर्कसंगत तथ्यपरक, सम्प्रेषण के नियमों के अनुसार वाद–विवाद हो एक 'भगवा' शब्द उठाकर कलाबाजी दिखाने से क्या जनमानस अपनी जातीय स्मृति से क्षुब्ध होकर उसे फेंक आएगी और किसी विदेशी प्रतीक की अधीनता स्वीकार लेगा? यह कभी संभव नहीं होगा क्योंकि हर दिन की सुबह जनमानस को भगवा अर्थ पढ़ती है हर दिन का उदित होता सूरज उसे भगवा का प्रत्यक्ष बोध देता है।

Scanned with OKEN Scanner

...पीय अदालत में भारत की जीत

...रोपीय संघ के इस्पात उत्पादकों ...रतीय इस्पात निर्यातकों के विरुद्ध ... आयोग परिषद में किए गए ...त के बाद भारतीय इस्तपात ...ों पर लगे एण्टी–सब्सिडी ड्यूटी ...पीय अदालत ने समाप्त कर दिया ... एण्टी–सब्सिडी ड्यूटी स्टेनलेश ...के छड़ों पर लगायी गयी थी।

...रोपीय अदालत (यूरोपीयन कोर्ट ...फर्स्ट इंस्टैंस) ने अपना फैसला ... निर्यातकों के पक्ष में देते हुए, ...को निर्यात की गयी स्टील छड़ों पर ... गई एण्टी–सब्सिडी ड्यूटी को ...जिब ठहराया है।

...स केस में भारतीय पक्ष को हैमंड सूडाड्र्स एज नामक फर्म में कार्यरत दो अधिक्ताओं जे. ब्रांटॉन तथा के अडामांटोपाउलस ने रखा था।

फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि किसी भी वस्तु पर एण्टी सब्सिडी शुल्क लगाने के पहले यह साबित करना आवश्यक है कि उसके लिए निर्माता देश में अवैध ढंग से सब्सिडी दी गयी है। इस फैसले से भारतीय इस्पात निर्यातकों को ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है।

यूरोप में भारतीय इस्पात की माँग बढ़ने का मुख्य कारण इसका कम मूल्य एवं क्वालिटी में यूरोपीय उत्पादों से बेहतर होना है साथ ही यूरोप में स्टील उत्पादकों द्वारा कृत्रिम रूप से मूल्य वृद्धि भी है। ■

अमेरिका में प्रतिबंधित दवा भारत में बिक रही है

अमेरिका और यूरोप में कम से कम 52 लोगों की मौत के लिये जिम्मेवार दवा, अब भारतीय बाजार में बिक्री के लिये उपलब्ध है। इन दवाओं को इनकी निर्माता कंपनियों ने यूरोपीय एवं अमेरिकी सरकारों के दबाव में वहाँ के बाजार से हटा लिया था। यह दवा है सेरीमास्टैटिन जिसका उपयोग कोलेस्टेराल कम करने में होता है। यह दवा भारत में लिपोबे और सेरिभा नामों से उपलब्ध है।

भारत के दवा नियंत्रक अश्विनी कुमार ने कहा है कि लिपोबे बनाने वाली कंपनी ने इसे भारतीय बाजारों से हटा लेने का वादा किया है इसके बावजूद दिल्ली में कई दवा दुकानों में यह दवा उपलब्ध है यहाँ तक कि कंपनी अब इस दवा पर क्रेताओं को छूट भी दे रही है।

सबसे बुरी बात तो यह है कि हृदय रोग विशेषज्ञों को इसके हानियों के विषय में पता नहीं है, एस्कार्ट हार्ट सेंटर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि कसलीवाल का कहना है कि यह संभव है कि बहुत से विशेषज्ञ अभी भी इसके हानियों के प्रति अनजान है।

इसके हानियों के विषय में औषधिय पत्रिका लैनसेन्ट के ताजे अंक में आया है "इससे सबसे ज्यादा हानि बड़े उम्र वाले रोगीयों को होती है जो इसके साथ–साथ मोटापा की दवा भी लेते हैं।"

भारत में यह दवा 1997 से बिक रही है। अपने कोलेस्टेरॉल हटाने की प्रक्रिया के दौरान ही यह दवा शरीर के मांसपेशियों को भी नुकसान पहुँचाती है जिससे राब्डोमियोलाइसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। ■

...क्षा अब मौलिक अधिकार होगी

...केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् ने एक महत्वपूर्ण ...में शिक्षा को मौलिक अधिकारों में ...त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे ...कार इसके लिये संविधान संशोधन ... संसद के शीतकालीन सत्र में ...। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् ...ने 18 सितम्बर की बैठक में शिक्षा ...न्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले ...जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी ...के लिये शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य ...का प्रस्ताव; 0–6 वर्ष तक के बच्चों ...भाल तथा शिक्षा के लिए राज्यों को ...र बनाना तथा बच्चों को शिक्षा देने ...ए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ...पिता या अभिभावक के कर्त्तव्य को ...के कर्त्तव्य बनाना है।

इसके लिए प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद् की इस बैठक में एक नया संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करना तय हुआ।

यह 93वाँ संविधान संशोधन विधेयक होगा जिसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21–ए जोड़ा जाएगा तथा अनुच्छेद 45 का पुर्नलेखन होगा। साथ ही राज्यसभा में लम्बित विधेयक 83 को वापस लिया जाएगा।

अनुच्छेद 21–ए में लिखा होगा – "सरकार 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी।" वहीं अनुच्छेद–45 के पुर्नलेखन में लिखा जाएगा – "राज्य 0–6 वर्ष तक के सभी बच्चों की देखभाल करेगा तथा सबको शिक्षा उपलब्ध कराएगा।" ■

Scanned with OKEN Scanner

एनरॉन लगवाएगा आर्थिक प्रतिबंध

एनरॉन प्रमुख केनेथ ले ने एनरॉन विवाद का फैसला उनके पक्ष में न होने पर भारत पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी है। ध्यातव्य है कि एनरॉन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति बुश का प्रमुख फाइनांसर रहा है।

केनेथ ले की एनरॉन कारपोरेशन भारत के दाभोल ऊर्जा कंपनी में 65 प्रतिशत की भागीदार है और एनरॉन ने इसमें भारत में होने वाले सभी विदेशी निवेशों में सबसे बड़ा निवेश किया है।

केनेथ ले ने फाइनेंशियल टाईम्स को दिये अपने एक साक्षात्कार में दाभोल विवाद से सम्बन्धित प्रश्न का जबाव देते हुए कहा कि 'अमेरिका में ऐसा कानून है कि अगर किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा विदेश में निवेश की गयी राशि उसे वापस नहीं मिलती तो अमेरिकी सरकार उस देश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता या अन्य किसी भी तरह का सहयोग रोक सकती है। लंदन के इस प्रमुख आर्थिक दैनिक में यह साक्षात्कार ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका भारत पर 1998 के परमाणु बम परीक्षणों के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंधों को उठाने की बात कर रहा था और भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश में था (ये प्रतिबंध 23 सितम्बर को उठा लिये गये हैं – संपादक)। इस विषय पर एनरॉन के अन्य अधिकारियों ने बाद में सफाई पेश करते हुए यह कहा कि केनेथ केवल पत्रकारों के प्रश्न "दाभोल विवाद में गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत सरकार को कैसे मजबूर किया जा सकता है? का उत्तर दे रहे थे।

एनरॉन द्वारा उत्पादित बिजली का मूल्य बहुत ज्यादा होने के कारण भारत में इसके खरीददार नहीं मिल रहे है जिसके कारण इसे अपना संयंत्र बन्द करना पड़ा है साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना बकाया देने से इन्कार कर दिया है। (भारतीय उच्चतम न्यायलय ने भी एनरॉन को 136 करोड़ रुपए बकाये के भुगतान पर 21 सितम्बर को रोक लगा दी है – संपादक)

एनरॉन का कहना है कि उसके परियोजना में करीब पौने नौ करोड़ डॉलर लगाया है और वह लागत पर अपना हिस्सा बेचने को तैयार है। फाइनेंसियल टाईम्स के साक्षात्कार में छपा है कि यदि भारत दाभोल परियोजना को अपने स्वामित्व में लेती है तो भी अपने कानूनों के तहत अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनरॉन के प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी अधिग्रहण के बाद संपत्ति का मूल्य कम होने की स्थिति में यदि एनरॉन अपना लागत मूल्य नहीं प्राप्त करता है तो अमेरिकी कानूनों के तहत यह भी स्वामित्व हरण ही होगा। जिसके तहत भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। ■

अमेरिका में 42 भारती उत्पाद शुल्क मुक्त

अमेरिका ने भारत के साथ अ सम्बन्धों में सुधार की दिशा में ए महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत आयात होने वाली 42 वस्तुओं को आय शुल्क से मुक्त करने का फैसला किया ये 42 उत्पाद आभूषण, चमड़ा एवं काली क्षेत्र से हैं। इस सभी वस्तुओं का वर्तमा अनुमानित व्यापार मूल्य 54 करोड़ अमेरि डॉलर है। अमेरिकी व्यापार मंत्री राबर्ट जोलिक ने वाणिज्य एवं उद्योगमं मुरासोली मारन से मुलाकात के ब बताया कि हमने जी.एस.पी. प्रावधानों तहत लगभग 54 करोड़ अमेरिकी डॉल कार तरजीही व्यापार प्रवेश देने निश्चय किया है। इन प्रावधानों के तह तटकर मूल्य महीने के अंत तक घटा दि जाएँगे। इन रियायतों सहित उत्पादों क निर्यात 60 करोड़ डॉलर पार कर जाने उम्मीद है। ■

आतंकवादी हमले का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों पर भी

अमेरिका पर हुये आतंकवादी हमले से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले भी प्रभावित होंगे। पूरे दुनिया मे लगभग 24 स्थानों पर प्रतिवर्ष लगने वाली इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शकों तथा दर्शकों की उपस्थिति कम रहने की आशंका है। भारतीय उद्योग परिसंघ का कहना है कि यद्यपि मेले समय पर ही आयोजित होंगे लेकिन इसमें भाग लेने वाले उद्यमियों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ जनवरी 2002 में 'आटो एक्सपो' आयोजित करेगा। एक विशेषज्ञ के अनुसार अमेरिका में चल रही गतिविधियों के कारण बहुत से ग्राहक इससे अलग हो जाएँगे। ■

Scanned with OKEN Scanner

स्वदेशी जागरण मंच, दिल्ली प्रदेश ने की दोषपूर्ण रोजगार विषयक टास्क फोर्स के विरुद्ध सफल संगोष्ठी

स्वदेशी जागरण मंच की दिल्ली प्रदेश इकाई ने ५ सितम्बर, २००१ को मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में तैयार रोजगार की संभावनाओं के लिए टॉस्क फोर्स की आई रपट के संदर्भ में एक संगोष्ठी आयोजित की। जो कंस्टिच्यूशन क्लब, रफी मार्ग पर सम्पन्न हुई। इस संगोष्ठी में पूर्वरक्षा मंत्री और समता पार्टी के वरिष्ठ नेता जार्ज फर्नांडीज, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिवाधिकारी मुकुंद गोरे, जाने माने अर्थशास्त्री रुद्रदत्त और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मुरलीधर राव उपस्थित थे।

बड़ी जन-उपस्थिति में अर्थशास्त्री रुद्रदत्त ने ५ जुलाई, २००१ को सरकार को सौंपी गई अहलूवालिया के रोजगार संबंधी रपट की विस्तार से समीक्षा की। अपनी समीक्षा के निष्कर्ष रूप में रुद्रदत्त ने कहा कि ठोस कारणों से यह रपट रोजगार बढ़ाने वाली नहीं है। इससे रोजगार की हानि होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभ उठाएगी, जनता का भला नहीं होगा। भामसं की ओर से शामिल हुए मुकुंद गोरे जो लम्बे समय से मजदूर हितों के सिलसिले में रोजगार विषयक अध्ययन से जुड़े रहे हैं, ने अहलूवालिया रपट की मानसिकता की व्याख्या की और उनका निष्कर्ष भी अहलूवालिया रपट के विरोध में ही था।

स्व. जा. मं. के राष्ट्रीय संगठक पो. मुरलीधर राव के साथ पूर्व रक्षामंत्री जार्ज फर्नांडीज

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक ने स्वदेशी जागरण मंच के संकल्प को दुहराया उन्होंने राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की चर्चा करते हुए जनता के हित में रोजगार के स्वरूप और आर्थिक उन्नति के समुचित मार्ग को रेखांकित किया साथ ही भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा पर इस प्रकार की रपटों के दुष्प्रभावों से संभावित आशंकाओं को व्यक्त किया।

प्रधानवक्ता के रूप में आमंत्रित जार्ज फर्नांडीज इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने अहलूवालिया कमिटी की रपट का पहले ही अध्ययन कर उसके रोजगार विरोधी दुष्परिणामों के विषय में सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया था। उनका पत्र इस बात का द्योतक था कि वे जिस रोजगार के अवसर के न केवल आर्थिक उन्नति में आवश्यक समझते रहे है बल्कि राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक मानते रहे हैं। उन्होंने काश्मीर और भारत के पूर्वी प्रदेशों में छाये आतंक का संदर्भ लेते हुए अपने दौरे और आतंकी हो रहे युवकों से भेंट करके उनकी मानसिकता के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के आतंक का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। स्थानीय संसाधनों की सुव्यवस्था से वहाँ की बेरोजगारी दूर की जा सकती है। चीन में यह काम हुआ है। चीन ने बाँस के उत्पादनों से करोड़ो डॉलर की कमाई की है। वही बाँस सीमा के इस पार भी है इस स्थानीय संसाधन का उपयोग करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। हमारी पारंपरिक क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग हो तो रोजगार समस्या नहीं बन सकता। इसी तरह काश्मीर की चर्चा करते हुए श्री जार्ज ने कहा कि वहाँ मस्जिद में स्वयं जाकर उन्होंने आतंकवाद की ओर झुकते युवकों से बात की और पाया कि रोजगार की समस्या से आतंक को प्रश्रय मिल रहा है। सवाल सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुविधाएं और कमाई का नहीं है बड़ा सवाल लाखों बेरोजगार होते युवकों के सामने छाए अंधकारमय भविष्य का है जिसका लाभ आतंकी उठाते चले जा रहे है और देश को भारी हानि हो रही है। श्री जार्ज का मानना था कि अहलूवालिया की रपट समस्या को घटाने वाली नहीं है बल्कि और बढ़ाने वाली है। विश्व बैंक के हितों से अलग रहकर अपने देश की समस्याओं पर विचार करने की जरूरत है। इस समस्या को लेकर गंभीर स्थिति की नीति निर्धारकों को बजट और योजना के फासले का पता होता। बजट और योजना में दूर बढ़ाने वाली नीतियाँ कमी कारगर नहीं हो सकती।

श्री जार्ज स्वदेशी आन्दोलन में अपनी भूमिका और स्वदेशी जागरण मंच से अपने सम्बन्ध को अनजान नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने पुराने सम्बन्ध को व्यक्त किया और बताया कि स्वदेशी और स्वभाषा के लिए आरंभ से ही उन्होंने आन्दोलन किया है। उन्होंने आगे भी स्वदेशी जागरण मंच से अपना सम्बन्ध बनाए रखने का वचनबद्धता दुहराई। और कहा कि १९९१ में जब हम विपक्ष में थे तब उदारीकरण की नीतियों का विरोध करते रहे, आज सरकार में है तो उन्हीं नीतियों को लागू कर रहे है। इससे बेरोजगारी फैलेगी। उन्होंने युवा पीढ़ी से अस्तित्व रक्षा के लिए सक्रिय रहने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक श्री जार्ज फर्नांडीज का कोई निजी क्षोभ सरकार के प्रति बिल्कुल नहीं था। परंतु वह दोषपूर्ण नीति के विरोध में जनतांत्रिक दृष्टि से उचित बात कहने के पक्ष में थे। उन्होंने सरकार को रोजगार के विषय में गंभीर रहने के लिए सजग किया। हालाँकि पेशेवर पत्रकारों ने जार्ज के इस जनतांत्रिक चेष्टा को सरकार पर प्रहार की तरह उछाल कर अपनी अखबारी व्यवसायिकता को बल दिया जिसके राजनीति दृष्टि से अनावश्यक अर्थ भी निकाले जा सकते हैं जबकि उनका उद्देश्य सीधा था जनपक्षधरता, सार्वजनिक हित। जिसके लिए कोई भी राजनीतिक दल वचनबद्ध होती है। सरकार से सम्बद्ध होने के बाद भी उनके आलोचनात्मक तेवर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यह मौन स्वीकृति के रूप में भी जा सकती है कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी का उद्देश्य और जार्ज फर्नांडिज का कथन सर्वथा उपयुक्त है। इस सफल कार्यक्रम का सुदृढ़ संचालन स्वदेशी जागरण मंच, दिल्ली प्रदेश के सह-संयोजक डॉ. अश्विनी महाजन ने किया।

Scanned with OKEN Scanner

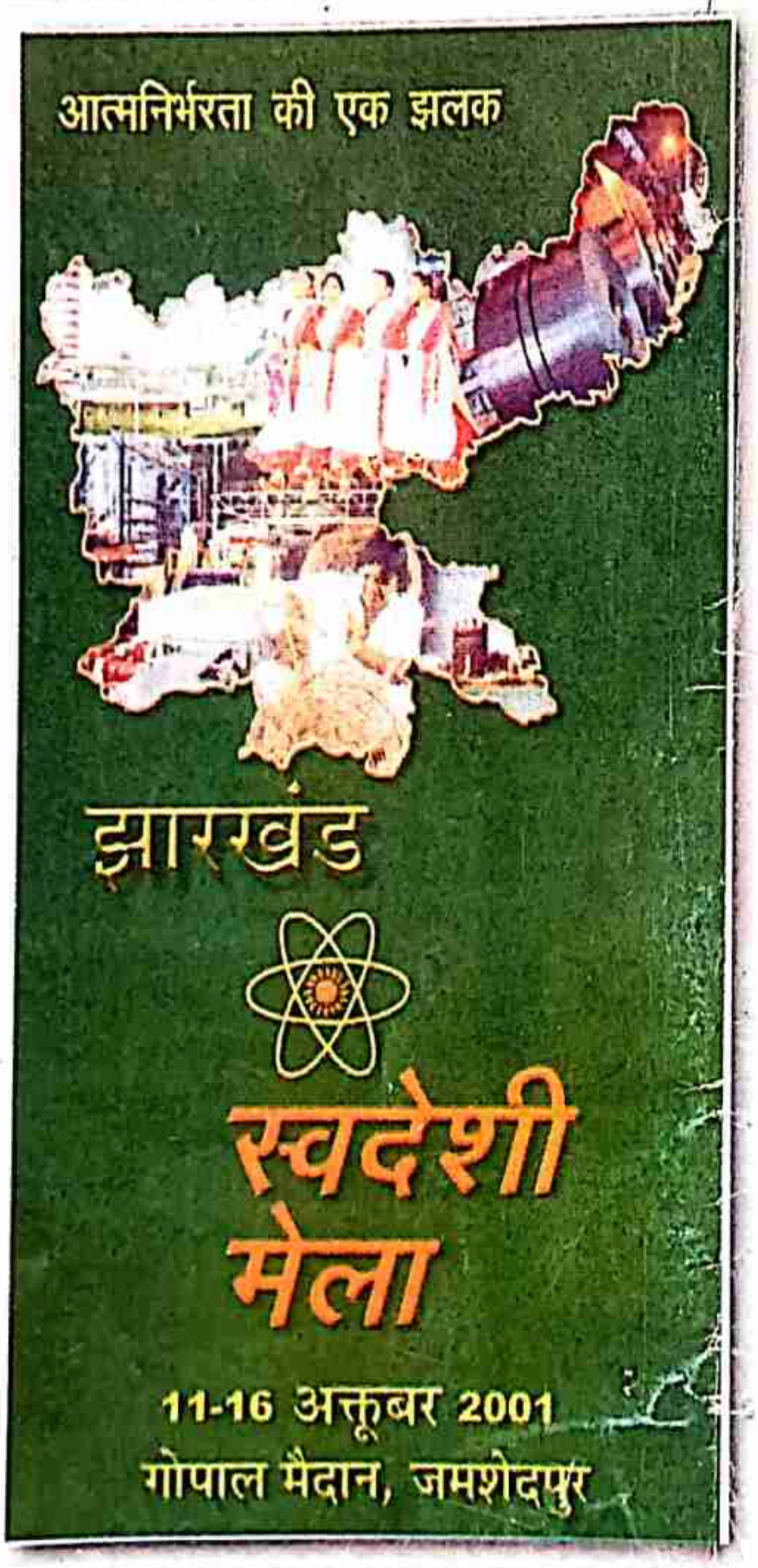

स्वदेशी खाद "धनन्जय" का प्रयोग करें।
INDO JAPAN
AGROTECH. LTD.
Manufacturer of :
"Dhnanjay " Bio Organic Fertilizer
"धनन्जय" कार्बनिक जैविक खाद के निर्माता
Head Office : 100-A, Cycle Market,
Jhandewalan Extn. New Delhi-1100055
Tel.: 91-011-3617013 Fax : 91-011-3556436
Res.: 2260773, 2264642 Mobile 98100-17327
Factory : GIDC-Tharsa, Gujrat
आपकी अपनी स्वदेशी कम्पनी

ईश्वर दास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन के लिए कुमार ब्रदर्स प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ से मुद्रित एवं ६०, नॉर्थ एवेन्यू से प्रकाशित

Scanned with OKEN Scanner